चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 09 अक्टूबर- 15 अक्टूबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

चीनी मिल घोटाले की जांच में केंद्र सरकार डाल रही बाधा

योगी जी! दोषी कौन जेटली या मोदी

- डीजी की जांच रिपोर्ट किनारे रख कर सीसीआई ने दे दी मायावती को क्लीन-चिट
- डीजी ने जांच में पकड़ा था यूपी की 21 चीनी मिलों की बिक्री में भारी गड़बड़झाला
- राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कैग की रिपोर्ट को संज्ञान में ही नहीं लिया

प्रभात रंजन दीन

मायावती के मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग-अलग स्टैंड पर खड़ी हो गई है. मायावती को कानून के शिकंजे में कसने की योगी कोशिश कर रहे हैं तो जेटली उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं. इसे राजकीय भाषा में ऐसे कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार बसपाई शासनकाल के घोटालों की जांच कराने का निर्णय लेती है तो केंद्र सरकार उसे कानूनी तौर पर बेअसर कर देती है. मायावती और अरुण जेटली के बीच कोई रहस्यमय समझदारी है या केंद्र की मोदीनीत भाजपा सरकार भविष्य के लिए मायावती को 'रिजर्व' में रखना चाहती है? कहीं जेटली को आगे रख कर मोदी ही मायावती को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? भाजपाइयों को ही यह बात समझ में नहीं आ रही है. इस गुत्थी के निहितार्थ योगी के भी पल्ले नहीं पड़ रहे.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के छह महीने पूरे होने पर जारी श्वेत-पत्र में भी प्रदेश की करीब दो दर्जन चीनी मिलों को बेचे जाने में हुए अरबों रुपए के घोटाले का उल्लेख किया है. इसके पहले अप्रैल महीने में योगी ने चीनी मिलों के बिक्री-घोटाले की जांच कराए जाने की घोषणा की थी. लेकिन अरुण जेटली के कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय ने इस मामले में कानूनी रायता बिखेर दिया. आप यह जानते ही हैं कि जेटली वित्त के साथ-साथ कॉरपोरेट अफेयर विभाग के भी मंत्री हैं. नॉर्थ-ब्लॉक गलियारे के एक आला अधिकारी कहते हैं कि यूपी की चीनी-मिलों को कौड़ियों के मोल बेच डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आखिरी फैसला आना बाकी है, लेकिन कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया) ने जो कानूनी रोड़े खड़े किए हैं, उससे घोटाला साबित होने में मुश्किल होगी. चीनी मिल बिक्री घोटाले से मायावती को बेदाग बाहर निकालने की समानान्तर किलेबंदी कर दी गई है. योगी जी को ध्यान रखना होगा कि यह किलेबंदी उन्हीं की पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने की है.

पिटारा खुलेगा, तो सभी होंगे बेनक़ाब

चीनी मिलों के विक्रय-प्रकरण का पिटारा खुलेगा तो भाजपा की भी संलिप्तता उजागर होगी. सपा की भूमिका से भी पर्दा हटेगा. भाजपा इस वजह से भी इस मामले को ढंके रहना चाहती है और योगी इस वजह से भी इसे उजागर करने में रुचि ले रहे हैं. चीनी मिलों को बेचने की शुरुआत भाजपा के ही शासनकाल में हुई थी. भाजपा सरकार ने ही चीनी-मिलों पर गन्ना किसानों और किसान समितियों की पकड़ कमजोर करने और बिखेरने का काम किया था. चीनी मिलें बेचने की शुरुआत तत्कालीन भाजपा सरकार ने की थी, सपा ने अपने कार्यकाल में इसे आगे बढ़ाया और बसपा ने इसे पूरी तरह अंजाम पर ला दिया. इसकी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे. अभी यह बताते चलें कि मायावती के कार्यकाल में चीनी मिलों को औने-पौने भाव में कुछ खास पूंजी घरानों को बेचे जाने के मामले की जांच की घोषणा योगी सरकार ने सत्तारूढ़ होने के महीनेभर बाद ही अप्रैल महीने में कर दी थी. इस घोषणा से केंद्र सरकार फौरन सक्रिय हो गई और कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने अगले ही महीने यानि, मई महीने में ही अपना फैसला सुनाकर योगी सरकार को झटके में ला दिया. कमीशन ने साफ-साफ कहा कि मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की बिक्री में कोई गड़बड़ी नहीं की. कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की संवैधानिक अधिकार प्राप्त विनियामक संस्था है. आयोग ने चार मई 2017 को दिए अपने फैसले में कहा है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई हो. चीनी मिलों की बिक्री में अपनाई गई प्रक्रिया आयोग की नजर में पूरी तरह पारदर्शी है. आयोग ने यह भी कहा है कि नीलामी से किसी भी पार्टी को रोका नहीं गया और न किसी को धमकी ही दी गई. इस फैसले पर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कुमार सीकरी और सदस्य न्यायमूर्ति जीपी मित्तल, यूसी नाहटा और ऑगस्टीन पीटर के हस्ताक्षर हैं.

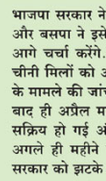

देवेंद्र कुमार सीकरी चेयरमैन, सीसीआई

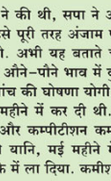

ऑगस्टीन पीटर सदस्य, सीसीआई

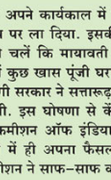

न्यायमूर्ति जीपी मित्तल सदस्य, सीसीआई

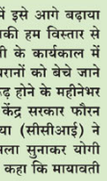

यूसी नाहटा सदस्य, सीसीआई

चीनी मिल घोटाले पर भिड़ीं दो केंद्रीय संस्थाएं

आप मजा देखिए, सियासत जिस जगह नाक घुसेड़ दे, वहां क्या हाल कर देती है. संवैधानिक अधिकार प्राप्त केंद्र सरकार की दो संस्थाएं चीनी मिल बिक्री घोटाले में मायावती की संलिप्तता को लेकर दो अलग-अलग परस्पर-विरोधी दिशा में खड़ी हैं. महालेखाकार (सीएजी) की जांच रिपोर्ट कहती है कि चीनी मिलों की बिक्री में घनघोर अनियमितता हुई, लेकिन प्रतिस्पर्धा आयोग कहता है कि बिक्री में कोई अनियमितता नहीं हुई. कैग की जांच रिपोर्ट पहले आ गई थी, (शेष पृष्ठ 2 पर)

> "चीनी मिलों के विक्रय-प्रकरण का पिटारा खुलेगा तो भाजपा की भी संलिप्तता उजागर होगी. सपा की भूमिका से भी पर्दा हटेगा. भाजपा इस वजह से भी इस मामले को ढंके रहना चाहती है और योगी इस वजह से भी इसे उजागर करने में रुचि ले रहे हैं. चीनी मिलों को बेचने की शुरुआत भाजपा के ही शासनकाल में हुई थी."

- महालेखाकार (कैग) पहले ही कर चुका है चीनी मिलों की बिक्री में घोटाले की पुष्टि
- भाजपा के शासनकाल में हुई थी चीनी मिलों को बेचने की शुरुआत, सपा भी दोषी
- चीनी मिल घोटाले पर कार्रवाई चाह रहे योगी को भी अब सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद

योगी जी! दोषी कौन, जेटली या मोदी

पृष्ठ 1 का शेष

आयोग का फैसला अभी हाल में आया है. दो परस्पर-विरोधी रिपोर्टें देख कर आम नागरिक क्या धारणा बनाए और किस जगह खड़ा हो! यह विषम स्थिति है. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 103 पेज का फैसला 'चौथी दुनिया' के पास है. इस फैसले को पढ़ें तो यह अपने आप में ही तमाम विरोधाभासों से भरा पड़ा है.

पौंटी चड्ढा की कंपनी से जुड़े हैं चीनी मिल घोटाले के तार

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के डायरेक्टर जनरल (डीजी) नितिन गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की 10 चालू और 11 बंद चीनी मिलों को बेचे जाने के मामले की गहराई से छानबीन की थी. इस छानबीन में भी चीनी मिलें खरीदने वाले पूंजीपति पौंटी चड्ढा की कंपनी के साथ नीलामी में शामिल अन्य कंपनियों की साठगांठ आधिकारिक तौर पर पुष्ट हुई. यह पाया गया कि नीलामी में शामिल कई कंपनियां पौंटी चड्ढा की ही मूल कंपनी से जुड़ी हैं,

नितिन गुप्ता, डायरेक्टर जनरल, सीसीआई

जबकि नीलामी की पहली शर्त ही यह थी कि एक मिल के लिए एक ही कंपनी नीलामी की निविदा-प्रक्रिया में शामिल हो सकती है. प्रतिस्पर्धा आयोग के डीजी ने अपनी छानबीन में पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 10 चालू हालत की चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में पहले तो 10 कंपनियां शरीक हुईं, लेकिन आखिर में केवल तीन कंपनियां वेव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, पीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड ही रह गईं. चालू हालत की 10 चीनी मिलों को खरीदने के लिए आखिर में बचीं तीन कंपनियों में 'गजब' की समझदारी पाई गई. जिन मिलों को खरीदने में वेव की रुचि थी, वहां अन्य दो कंपनियों ने कम दर की निविदा (बिड-प्राइस) भरी और जिन मिलों में दूसरी कंपनियों को रुचि थी, वहां वेव ने काफी कम दर की निविदा दाखिल की. इस तरह बहराइच की जरवल रोड चीनी मिल, कुशीनगर की खड्डा चीनी मिल, मुजफ्फरनगर की रोहनकलां चीनी मिल, मेरठ की सकोती टांडा चीनी मिल और महराजगंज की सिसवां बाजार चीनी मिल समेत पांच चीनी मिलें इंडियन पोटाश लिमिटेड ने खरीदीं और अमरोहा चीनी मिल, बिजनौर चीनी मिल, बुलंदशहर चीनी मिल व सहारनपुर चीनी मिल समेत चार चीनी मिलें वेव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को मिलीं. दसवीं चीनी मिल की खरीद में रोचक खेल हुआ. बिजनौर की चांदपुर चीनी मिल की नीलामी के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 91.80 करोड़ की निविदा दर (बिड प्राइस) कोट की. पीबीएस फूड्स ने 90 करोड़ की प्राइस कोट की, जबकि इसमें वेव कंपनी ने महज 8.40 करोड़ की बिड-प्राइस कोट की थी. बिड-प्राइस के मुताबिक चांदपुर चीनी मिल खरीदने का अधिकार इंडियन पोटाश लिमिटेड को मिलता, लेकिन ऐन मौके पर पोटाश लिमिटेड नीलामी की प्रक्रिया से खुद ही बाहर हो गई. लिहाजा, चांदपुर चीनी मिल पीबीएस फूड्स को मिल गई. नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो जाने के कारण इंडियन पोटाश की बिड राशि जब्त हो गई, लेकिन पीबीएस फूड्स के लिए उसने पूर्व-प्रायोजित-शहादत दे दी. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में यह भी तथ्य खुला कि पौंटी चड्ढा की कंपनी वेव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और पीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों के निदेशक त्रिलोचन सिंह हैं. त्रिलोचन सिंह के वेव कंपनी समूह का निदेशक होने के साथ-साथ पीबीएस कंपनी का निदेशक और शेयरहोल्डर होने की भी आधिकारिक पुष्टि हुई. इसी तरह वेव कंपनी की विभिन्न सम्बद्ध कंपनियों के निदेशक भूपेंद्र सिंह, जुनैद अहमद और शिशिर रावत पीबीएस फूड्स के भी निदेशक मंडल में शामिल पाए गए. मनमीत सिंह वेव कंपनी में अतिरिक्त निदेशक थे तो पीबीएस फूड्स में भी शेयर होल्डर थे. इस तरह वेव कंपनी और पीबीएस फूड्स की साठगांठ और एक ही कंपनी का हिस्सा होने का दस्तावेजी तथ्य सामने आया. यहां तक कि वेव कंपनी और पीबीएस फूड्स द्वारा निविदा प्रपत्र खरीदने से लेकर बैंक गारंटी दाखिल करने और स्टाम्प पेपर तक के नम्बर एक ही क्रम में पाए गए. आयोग के डीजी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों कंपनियां मिलीभगत से काम कर रही थीं, जो कम्पीटीशन एक्ट की धारा 3(3)(ए) और 3(3)(डी) का सीधा-सीधा उल्लंघन है. चालू हालत की 10 चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में शामिल होकर आखिरी समय में डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मीपति बालाजी शुगर एंड डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एसबीईसी बायोइनर्जी लिमिटेड और तिकौला शुगर मिल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के भाग खड़े होने का मामला भी रहस्य के घेरे में ही है. हालांकि आयोग ने अपनी जांच में इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.

नीलामी में शामिल तीन कंपनियों का एक ही पता

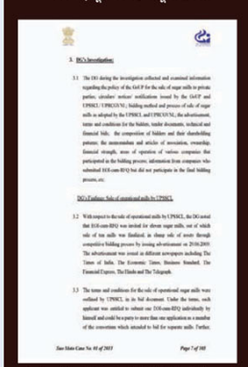

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की प्रदेश में बंद पड़ी 11 चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में भी ऐसा ही कुछ 'खेल' हुआ. नीलामी की औपचारिकताओं में कुल 10 कंपनियां शरीक हुईं, लेकिन आखिरी समय में तीन कंपनियां मेरठ की आनंद ट्रिपलेक्स बोर्ड लिमिटेड, वाराणसी की गौतम रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा की श्रीसिद्धार्थ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड मैदान छोड़ गईं. जो कंपनियां रह गईं उनमें पौंटी चड्ढा की कंपनी वेव इंडस्ट्रीज़ के साथ नीलगिरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, नम्रता, त्रिकाल, गिरियाशो, एसआर बिल्डकॉन व आईबी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल थीं और इनमें भी आपस में खूब समझदारी थी. नीलगिरी फूड्स ने बैतालपुर, देवरिया, बाराबंकी और हरदोई चीनी मिलों के लिए निविदा दाखिल की थी, लेकिन आखिर में बैतालपुर चीनी मिल छोड़ कर उसने अन्य से अपना दावा वापस कर लिया. इसके लिए उसे जमानत राशि भी गंवानी पड़ी. बैतालपुर चीनी मिल खरीदने के बाद नीलगिरी ने उसे भी कैनयन फाइनैंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड के हाथों बेच डाला. इसी तरह त्रिकाल ने भटनी, छितौनी और घुघली चीनी मिलों के लिए निविदा दाखिल की थी, लेकिन आखिरी समय में जमानत राशि गंवाते हुए उसने छितौनी और घुघली चीनी मिलों से अपना दावा हटा लिया. वेव कंपनी ने भी बरेली, रामकोला और शाहगंज की बंद पड़ी चीनी मिलों को खरीदने के लिए निविदा दाखिल की थी. लेकिन उसने बाद में बरेली और रामकोला से अपना दावा छोड़ दिया और शाहगंज चीनी मिल खरीद ली. बाराबंकी, छितौनी और रामकोला की बंद पड़ी चीनी मिलें खरीदने वाली कंपनी गिरियाशो और बरेली, हरदोई, लक्ष्मीगंज और देवरिया की चीनी मिलें खरीदने वाली कंपनी नम्रता में वही सारी संदेहास्पद-समानताएं पाई गईं जो वेव इंडस्ट्रीज़ और पीबीएस फूड्स लिमिटेड में पाई गई थीं. यह भी पाया गया कि गिरियाशो, नम्रता और कैनयन, इन तीनों कंपनियों का दिल्ली के सरिता विहार में एक ही पता है. बंद पड़ी 11 चीनी मिलें खरीदने वाली सभी कंपनियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई पाई गईं, खास तौर पर वे पौंटी चड्ढा की वेव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड से सम्बद्ध पाई गईं. लेकिन विडंबना यह है कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने ही डीजी की छानबीन को किनारे लगा दिया और फैसला सुना दिया कि यूपी की 21 चीनी मिलों की नीलामी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी और साठगांठ साबित नहीं पाई गई. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के इस फैसले को अभी नहीं माना है. कानून के विशेषज्ञ कहते हैं कि आयोग के जरिए केंद्र सरकार ने कानूनी पचड़ा फंसाने की कोशिश तो की है, लेकिन आयोग के डीजी की छानबीन रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की निगाह में है.

नेता, नौकरशाह और पूंजीपतियों की मिलीभगत से बिक गई यूपी की 10 चालू चीनी मिलें

उसी तरह कौड़ियों के मोल बेच डाली गई यूपी की 11 बंद पड़ी चीनी मिलें

सीसीआई के डीजी ने चीनी मिलों की बिक्री में गड़बड़ी की पुष्टि की, लेकिन आयोग ने इसे टाल दिया

सीसीआई ने डीजी की जांच को ताक पर रखकर मायावती को दे दी क्लीनचिट

नौकरशाहों ने दलालों की तरह काम किया

एक तरफ प्रतिस्पर्धा आयोग कहता है कि चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई, दूसरी तरफ अगर दस्तावेज देखें तो धांधली साफ-साफ दिखाई देती है. चीनी मिलों की अरबों की चल-अचल सम्पत्ति को कौड़ियों के भाव बेच दिया जाना घोर भ्रष्टाचार की सनद देता है. महालेखाकार की छानबीन में भी यह स्पष्ट हो चुका है कि चीनी मिलों की विक्रय-प्रक्रिया में शामिल नौकरशाहों ने पूंजी-प्रतिष्ठानों के दलालों की तरह काम किया. सीएजी का मानना है कि निविदा की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही यह तय कर लिया गया था कि चीनी मिलें किसे बेचनी हैं. निविदा में भाग लेने वाली कुछ खास कंपनियों को सरकार की बिड-दर पहले ही बता दी गई थी और प्रक्रिया के बीच में भी अपनी मर्जी से नियम बदले गए. मिलों की जमीनें, मशीनें और उपकरणों की कीमत निर्धारित करने में मनमानी की गई. बिक्री के बाद रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी भी कम कर दी गई. कैग का कहना है कि चीनी मिलें बेचने में सरकार को 1179.84 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ. यानि, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चालू हालत की 10 चीनी मिलों को बेचने पर सरकार को 841.54 करोड़ का नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की बंद 11 चीनी मिलों को बेचने की प्रक्रिया में 338.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

मायावती की करतूतों को अखिलेश ने लीपा पोता

चीनी मिल विक्रय घोटाला क्या, अखिलेश सरकार ने मायावती के कार्यकाल के सारे घपले-घोटालों को अपने कार्यकाल में खूब लीपा पोता. महालेखाकार की रिपोर्ट अखिलेश के कार्यकाल में ही विधानसभा के पटल पर रखी गई थी. लेकिन मुख्यमंत्री होने की अखिलेश ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई. मामला लोकायुक्त के पास चला गया, लेकिन सरकार की लापरवाही या दबाव के कारण लोकायुक्त की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई. अखिलेश सरकार ने लोकायुक्त के मत्थे ठीकरा फोड़ दिया. जबकि तत्कालीन लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने कहा कि छानबीन में सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है. सम्बद्ध नौकरशाहों से जवाब मांगा तो सिरचढ़े नौरशाहों ने लोकायुक्त को जवाब तक नहीं भेजा.

भाजपा शासन से शुरू हुई थी चीनी मिलों की बर्बादी और गन्ना किसानों की तबाही

किसानों को राजनीतिक दलों ने बड़े शातिराना तरीके से मारा है. इसके लिए समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अकेले दोषी नहीं है. चीनी मिलों को बर्बाद करने और गन्ना किसानों को तबाह करने का सिलसिला सबसे पहले भाजपा के शासनकाल में ही शुरू हुआ था. थोड़ा पृष्ठभूमि में झांकते चलें. कभी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान खुशहाल थे. गन्ने की खेती और चीनी मिलों से प्रदेश के गन्ना बेल्ट में कई अन्य उद्योग धंधे भी फल-फूल रहे थे. चीनी मिलों और किसानों के बीच गन्ना विकास समितियां (केन यूनियन) किसानों के भुगतान से लेकर खाद, ऋण, सिंचाई के साधनों, कीटनाशकों के साथ-साथ सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल और औषधालय तक की व्यवस्था करती थीं. गन्ने की राजनीति करके नेता तो कई बन गए लेकिन उन्हीं नेताओं ने गन्ना किसानों को बर्बाद भी कर दिया. नतीजतन गन्ना क्षेत्र से लोगों का भयंकर पलायन शुरू हुआ और उन्हें महाराष्ट्र और पंजाब में अपमानित होते हुए भी पेट भरने के लिए मजदूरी के लिए रुकना पड़ा. उत्तर प्रदेश में 125 चीनी मिलें थीं, जिनमें 63 मिलें केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में थीं. इनमें से अधिकतर चीनी मिलें बेच डाली गईं और कुछ को छोड़ कर सभी मिलें बंद हो गईं. सरकार ने चीनी मिलें बेच कर पूंजीपतियों को और खुद को फायदा पहुंचाया. चीनी मिलों के परिसर की जमीनें पूंजी-घरानों को कौड़ियों के भाव बेच डाली गईं, जिस पर अब महंगी कॉलोनियां बन रही हैं. जबकि चीनी मिलों को किसानों ने गन्ना समितियों के जरिए अपनी ही जमीनें लीज़ पर दी थीं. लेकिन उन किसानों के मालिकाना हक की चिंता किए बगैर अवैध तरीके से उन जमीनों को भी मिलों के साथ ही बेच डाला गया. 1989 के बाद से प्रदेश में नकदी फसल का कोई विकल्प नहीं खड़ा किया गया. गन्ना ही किसानों का अस्तित्व बचाने की एकमात्र नकदी फसल थी. चीनी मिलों के खेल में केवल समाजवादी पार्टी ही शामिल नहीं, अन्य दल भी जब सत्ता में आए तो खूब हाथ धोया. भाजपा की सरकार ने हरिशंकर तिवारी की कम्पनी 'गंगोत्री इंटरप्राइजेज' को चार मिलें बेची थीं. उस समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार में हरिशंकर तिवारी मंत्री थे. 'गंगोत्री इंटरप्राइजेज' ने चीनी मिलों की मशीनें और सारे उपकरण बेच डाले. फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने प्रदेश की 23 चीनी मिलें अनिल अम्बानी को बेचने का प्रस्ताव रख दिया. लेकिन तब अम्बानी पर चीनी मिलें चलाने के लिए दबाव था. सपा सरकार ने उन चीनी मिलों को 25-25 करोड़ रुपए देकर चलवाया भी, लेकिन मात्र 15 दिन चल कर वे फिर से बंद हो गईं. तब तक चुनाव आ गया और फिर बसपा की सरकार आ गई. मुख्यमंत्री बनी मायावती ने सपा कार्यकाल के उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और चीनी मिलों को औने-पौने दाम में बेचना शुरू कर दिया. मायावती ने पौंटी चड्ढा की कम्पनी और उसके गुट की कंपनियों को 21 चीनी मिलें बेच डालीं. देवरिया की भटनी चीनी मिल महज पौने पांच करोड़ में बेच दी गई. जबकि वह 172 करोड़ की थी. इसके अलावा देवरिया चीनी मिल 13 करोड़ में और बैतालपुर चीनी मिल 13.16 करोड़ में बेच डाली गई. अब उन्हीं मिलों की बेशकीमती जमीनों को प्लॉटिंग कर महंगी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है. बरेली चीनी मिल 14 करोड़ में बेची गई, बाराबंकी चीनी मिल 12.51 करोड़ में, शाहगंज चीनी मिल 9.75 करोड़ में, हरदोई चीनी मिल 8.20 करोड़ में, रामकोला चीनी मिल 4.55 करोड़ में, घुघली चीनी मिल 3.71 करोड़ में, छितौनी चीनी मिल 3.60 करोड़ में और लक्ष्मीगंज चीनी मिल महज 3.40 करोड़ रुपए में बेच डाली गई. ये तो बंद मिलों का ब्यौरा है. जो मिलें चालू हालत में थीं उन्हें भी ऐसे ही कौड़ियों के मोल बेचा गया. अमरोहा चीनी मिल महज 17 करोड़ में बेच डाली गई. सहारनपुर चीनी मिल 35.85 करोड़ में और सिसवां बाजार चीनी मिल 34.38 करोड़ में बिक गई. बुलंदशहर चीनी मिल 29 करोड़ में, जरवल रोड चीनी मिल 26.95 करोड़ में और खड्डा चीनी मिल महज 22.65 करोड़ में बेच डाली गई.

पूर्वांचल के जुझारू किसान नेता शिवाजी राय कहते हैं कि पहले यह व्यवस्था थी कि यूपी के किसान गन्ना की फसलें गन्ना समितियों को बेचते थे और गन्ना समितियां उसे चीनी मिलों को बेचती थीं. किसानों को पैसे भी समितियों के जरिए ही मिलते थे. सारा कुछ बहुत ही सीधी रेखा पर चल रहा था. लेकिन भाजपा सरकार ने इस प्रक्रिया को ऐसा घुमाया कि उसे नष्ट ही कर दिया. गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने की व्यवस्था लागू कर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केन यूनियनों को पंगु करने की शुरुआत की थी. उसके बाद न तो किसानों के खाते में पैसे पहुंचे और न केन यूनियनें ही फिर से ताकतवर हो पाईं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 32
09 अक्टूबर- 15 अक्टूबर 2017
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-65500786
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कांग्रेस के बाद अब भाजपा के दौर में भी

'विफलता का स्मारक' बनती मनरेगा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तौर पर शुरू हुई मनरेगा को ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन में सार्थक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना गया था. यही कारण भी था कि इस योजना को गांधी जी का नाम दिया गया, जो खुद समाज के निचले तबके के विकास में भारत का विकास देखते थे. लेकिन अफ़सोस कि मनरेगा के माध्यम से गांधी जी की ग्रामोदय की अवधारणा को सार्थक करने का सपना आज भी अधूरा है. क्यों? जानिए इस रिपोर्ट के ज़रिए...

निरंजन मिश्रा

फरवरी 2015 में बजट सत्र को सम्बोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोकसभा में कहा था, 'मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है और मैं गाजे- बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा.' इसके एक साल बाद ही 2016 में मनरेगा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राष्ट्रीय गर्व का विषय बताया था. हालांकि वर्तमान समय में मनरेगा की स्थिति का अवलोकन करें, तो पता चलता है कि ये योजना राष्ट्रीय गर्व का विषय नहीं बन सकी और इसे लेकर 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई बात ही सच साबित हो रही है. अंतर सिर्फ इतना है कि अब ये कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की विफलताओं का स्मारक बनती जा रही है. इस योजना के जरिए एक जॉब कार्ड होल्डर के लिए 100 दिनों के रोजगार की बात कही गई है, लेकिन सूखा ग्रस्त राज्यों में इसे 150 दिनों तक बढ़ाने के बाद भी इसके जरिए रोजगार सृजन का राष्ट्रीय औसत 38 दिन ही है. 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का एलान करते हुए सरकार ने अपनी पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि ये राशि इससे पिछले साल 38,500 करोड़ थी. लेकिन हकीकत ये है कि पिछले साल के 11,000 करोड़ के बकाए के कारण 2016-17 में ही ये राशि 38,500 करोड़ से बढ़कर 47,499 करोड़ रुपए हो गई थी.

रोज़गार में 7 लाख कमी, मांग में 12 लाख बढ़ोतरी

16 राज्यों में मनरेगा के जरिए रोजगार पाने वाले परिवारों की तादाद में बीते तीन सालों में 7 लाख की कमी आ गई है. हाल में आई केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 2013-14 में पूरे 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 46,59,347 थी, जो 2016-17 में घटकर 39,91,169 रह गई. गौर करने वाली बात ये भी है कि नवंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़ीशा में मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने वालों की संख्या में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. ये संख्या लगभग 12 लाख है. जिन 39 लाख परिवारों को रोजगार मिला उनकी मजदूरी में भी बढ़ोतरी नहीं हुई या हुई भी तो ऐसी जिसे आंशिक भी नहीं कहा जा सकता.

जैसे, उत्तर प्रदेश में पिछले साल मनरेगा कर्मियों की मजदूरी 174 रुपए थी, जिसमें सिर्फ एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसे 175 रुपए किया गया है. गौर करने वाली बात है कि बढ़ोतरी के बाद भी ये न्यूनतम मजदूरी नहीं है. जबकि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि मनरेगा की मजदूरी को राज्यों के न्यूनतम वेतन के बराबर लाया जाय. लेकिन हद तो ये है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ही मनरेगा की मजदूरी न्यूनतम वेतन के बराबर करने को गैर-जरूरी मानती है. हालांकि वो समिति खुद ये स्वीकार करती है कि 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मनरेगा कर्मियों को दी जाने वाली मजदूरी खेत मजदूरों की दिहाड़ी से भी कम है. वर्तमान सरकार ने मनरेगा मजदूरों को भुगतान में देरी पर दिए जाने वाले मुआवजे की रकम कम करने के लिए भी नियमों में बदलाव कर दिया है. पहले के नियम के अनुसार, हाजिरी रजिस्टर तैयार होने के 15 दिन के अंदर कामगारों को भुगतान करना जरूरी था. इसमें देरी पर उन्हें मुआवजा दिया जाता था. लेकिन नए नियम के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि मुआवजे की गणना मजदूरी के भुगतान के लिए अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर मांग किए जाने की तारीख के अनुसार होगी. पहले से लंबित मुआवजे का भी पूरा वितरण नहीं हो सका है. अप्रैल 2017 तक लगभग 53 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान लंबित होने की वजह से एक मई तक 6.31 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना था, जबकि इसमें से मात्र 1734 रुपए का ही भुगतान हो सका है.

मनरेगा कर्मी त्रस्त, मुखिया/प्रधान मस्त

मनरेगा को लेकर किए जा रहे दावों और जमीनी असलियत की पड़ताल के लिए हमने विभिन्न राज्यों के मनरेगा कर्मियों से बीतचीत की. मनरेगा कर्मियों ने जिस सच्चाई से पर्दा हटाया, वो चौंकाने वाला है. लगभग सभी राज्यों में मुखिया/प्रधान जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मनरेगा कर्मियों को मिलने वाले पैसों का बंदरबांट करते हैं. चूंकि इनके माध्यम से ही भुगतान होना होता है, इसलिए मजदूर इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते. कई मजदूर, नाम न उजागर करने की शर्त पर 'चौथी दुनिया' से बातचीत को तैयार हुए. इन्हें डर है कि प्रधान को अगर ये पता चले तो वे इन्हें काम नहीं देंगे. मध्य प्रदेश के पन्ना के उगरी गांव निवासी एक मनरेगा कर्मी ने बताया कि 'मेरे घर में चार लोगों के पास जॉब कार्ड है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एकसाथ सभी को काम मिला हो. प्रधान कहता है कि एक बार में एक घर से किसी एक आदमी को ही काम मिल सकता है. अगर ऐसा होता कि किसी एक आदमी को भी पूरे 100 दिन काम मिल पाता, तो हम किसी तरह से गुजारा कर सकते थे, यहां तो चार लोगों को मिलाकर भी पूरे 100 दिन काम नहीं मिल पाता. मजबूरी में मेरे घर से किसी एक को दिल्ली-पंजाब जाना पड़ता है, कमाई के लिए.' बिहार में तो स्थिति और भी खराब है. यहां कई जिलों में ऐसी अनियमितता देखने को मिली, जहां वर्षों पहले पूरे हो चुके काम को नवनिर्माण बता कर पैसा उठा लिया गया. उसमें न तो मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिला और न ही कोई काम हो सका. कई जगह तो पहले से मौजूद निजी तलाबों को ताजा खुदाई बता कर कागजी कार्रवाही कर ली गई. हमें अपनी पड़ताल में ये भी पता चला कि कई बार मुखिया उपस्थिति पंचिंग मशीन रोजगार कार्ड धारकों के घर लाकर उनके अंगूठे का निशान ले लेते हैं, ताकि उनकी हाजिरी बन जाए और फिर उसी आधार पर उनके खाते में पैसा भी आ जाता है. यहां गौर करने वाली बात ये है कि बिना काम किए मनरेगा कर्मियों के खाते में आया ये पैसा प्रधान के हाथ में ही जाता है और खाताधारक को उसका मामूली सा हिस्सा मिलता है. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के करम्बर गांव निवासी एक मनरेगा कर्मी की कहानी ऐसे फर्जीवाड़े की तस्दीक करती है. 'चौथी दुनिया' से बातचीत में उन्होंने बताया कि 'एक बार मेरे खाते में 10,000 रुपए आए. पता चला कि ये मनरेगा का पैसा है. मैं चौंक गया कि मुझे तो उतने दिनों का काम मिला नहीं, फिर ये पैसे कहां से आ गए. जब मैं बैंक पहुंचा, तो वहां मुझे पैसा निकालने से रोक दिया गया और कहा गया कि प्रधान को लेकर आओ. फिर मैंने प्रधान को फोन किया. वे आए, तो 6,000 रुपए निकाले और उसमें से मुझे 3,000 देकर बाकी 3000 खुद रख लिए.' ये कहानी वर्तमान समय में पूरे भारत में हो रहे मनरेगा फर्जीवाड़े की कहानी है.

मज़ाक़ है मज़दूरी में एक रुपए की बढ़ोतरी

2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के बाद जब इसकी सफलता का ढोल पीटा गया, तो ये संभावना जगी थी कि मनरेगा कर्मियों के भी अच्छे दिन आएंगे. लेकिन काम मिलने में कमी और विभिन्न राज्यों में मनरेगा कर्मियों की मजदूरी में नाम मात्र की बढ़ोतरी ने उन संभावनाओं पर पानी फेर दिया. दरअसल, इस वित्तीय वर्ष यानि अप्रैल 2017 के बाद यूपी, बिहार, असम और उत्तराखंड में मनरेगा कामगारों की मजदूरी में सिर्फ एक रुपए की वृद्धि हुई है. वहीं ओड़ीशा में दो रुपये और पश्चिम बंगाल में चार रुपए मजदूरी बढ़ाई गई है. बेतहासा बढ़ रही महंगाई के इस दौर में मजदूरी बढ़ोतरी के ये आंकड़े मनरेगा कर्मियों के लिए किसी मजाक से कम नहीं हैं. ये भी गौर करने की बात है कि 2006 में नरेगा योजना शुरू होने के बाद से इसकी मजदूरी में ये सबसे कम बढ़ोतरी है. ठीक एक साल पहले ही 2016-17 में ये बढ़ोतरी 5.7 फीसदी थी, लेकिन 2017-18 में ये मात्र 2.7 फीसदी रही.

मनरेगा कर्मियों का जंतर-मंतर पर हल्ला बोल

पिछले महीने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए 16 राज्यों के मनरेगा कर्मियों ने भी ऐसे फर्जीवाड़ों से निजात दिलाने की बात कही थी. 11 से 15 सितम्बर तक जंतर-मंतर पर आंदोलनरत रहे इन मनरेगा कर्मियों का कहना था कि उन्हें मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा है और यदि कभी काम मिलता भी है, तो सरपंच और मनरेगा अधिकारी उनसे आधे पैसे की रिश्वत मांगते हैं. मनरेगा के लिए आधार की अनिवार्यता इन मजदूरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है. राजस्थान से आए एक मनरेगा कर्मी ने 'चौथी दुनिया' से बातचीत में कहा कि 'मेरे घर में चार लोग हैं, जो मनरेगा में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, इसलिए प्रधान हमारा जॉब कार्ड नहीं बनाता. चार लोगों का आधार कार्ड बनवाने में लगभग 15 सौ रुपए लगेंगे. हम किसी भी तरह से मेहनत-मजदूरी कर के खाने की व्यवस्था करते हैं. अब आधार कार्ड बनवाने के लिए 15 सौ रुपए कहां से लाएं.' आंदोलन कर रहे इन मनरेगा कर्मियों का नारा था- 'सही समय पर पूरा काम, सही समय पर पूरा दाम.' इनकी मांग है कि इन्हें साल में 240 दिन का काम मिले और मजदूरी बढ़ाकर 600 किया जाय. कई संगठन भी मनरेगा कर्मियों की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं. ऐसे ही एक संगठन अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह ने 'चौथी दुनिया' से बातचीत में कहा कि 'जब मनरेगा आया तब जमीनी स्तर पर इसका बहुत सकातरात्मक प्रभाव देखने को मिला था.इससे वृहद स्तर पर पलायन रुका था और लोगों को उनके गांव में ही राजेगार मिल रहा था, लेकिन बीते तीन-चार सालों में स्थिति खराब हुई है. अब तो शायद ही कोई हो जिसे सौ दिनों का रोजगार मिल रहा हो. साथ ही सरकार भी इससे सुदृढ करने की जगह कमजोर करती जा रही है.' ■

feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा के लिए आधार की अनिवार्यता इन मजदूरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है. राजस्थान से आए एक मनरेगा कर्मी ने 'चौथी दुनिया' से बातचीत में कहा कि मेरे घर में चार लोग हैं, जो मनरेगा में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, इसलिए प्रधान हमारा जॉब कार्ड नहीं बनाता. चार लोगों का आधार कार्ड बनवाने में लगभग 15 सौ रुपए लगेंगे.

2019 तक सबको शौचालय

क्या ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा!

केन्द्रीय मंत्रियों के संसदीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण की प्रगति (वित्त वर्ष 2015-16 तक)

केंद्रीय मंत्री	संसदीय क्षेत्र	अक्टूबर 2019 तक कितने शौचालय बनाए जाने बाकी है	वित्त वर्ष 2015-16 में बनाए गए शौचालय की संख्या	इसी दर से काम हुआ तो कब तक पूरा होगा लक्ष्य
नरेन्द्र मोदी	वाराणसी	234489	7327	2048
राजनाथ सिंह	लखनऊ	186177	5332	2051
सुषमा स्वराज	विदिशा	112479	13391	2024
नितिन गडकरी	नागपुर	57429	24931	2018
उमा भारती	झांसी	105513	7867	2029
राम विलास पासवान	हाजीपुर	554434	12292	2061
कलराज मिश्रा	देवरिया	244560	11729	2037
मेनका गांधी	पीलीभीत	161057	5676	2044
अशोक गजपति राजू	विजियानाग्राम	344432	17173	2036
अनंत गीते	रायगढ़	111726	16265	2023
हरसिमरत कौर बादल	भटिंडा	12843	3851	2019
नरेन्द्र सिंह तोमर	ग्वालियर	81584	12754	2022
जुआल ओराम	सुन्दरगढ़	179044	73756	2018
राधामोहन सिंह	पूर्वी चंपारण	829391	11162	2090
मनोहर परिकर (अब गोवा के सीएम)	पणजी	22545	17984	2017
सुरेश प्रभु	राजापुर	32476	42899	2017
वीरेन्द्र सिंह	उंचाकलां	20672	6444	2019

शशि शेखर

साल 2019 के 2 अक्टूबर तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य सरकार ने रखा है. 2 अक्टूबर 2019 तक करीब 8 करोड़ शौचालय बनाने की जरूरत है, ताकि भारत को खुले में शौच मुक्त देश घोषित किया जा सके. केंद्र सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर के महात्मा गान्धी को 2019 में श्रद्धांजलि देना चाहती है. जाहिर है, इस दिशा में पिछले 2 साल से काफी जागरूकता भी आई है. लेकिन, वित्त वर्ष 2015-16 तक के कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो बताते हैं कि सरकार शायद ही 2019 तक इस लक्ष्य को हासिल कर पाए. ये डेटा सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरमेंट की है, जो 2015-16 तक, 22 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं (सांसद/मंत्री) के संसदीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण का जायजा लेती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक इन क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का जो दर है (ध्यान रहे, ये आंकड़ा 2015-16 तक के हिसाब से है), उसी हिसाब से आगे भी काम होता रहा तो खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस लय को हासिल करते-करते 32 साल और लग जाएंगे, यानि 2048 तक जाकर सबको शौचालय का लक्ष्य पूरा हो सकेगा. इसी तरह, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र पूर्वी चंपारण में शौचालय निर्माण का जो दर है (2015-16 तक), उसके मुताबिक ये लक्ष्य 2090 तक पूरा हो सकेगा.

15 अगस्त 2016 तक के आंकड़े (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़े) बताते हैं कि 2019 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए करीब 8 करोड़ शौचालय बनाए जाने की जरूरत है. इस आंकड़े को थोड़ा और तोड़ कर देखें. अगर सरकारी मशीनरी 24 घंटे लगातार काम करे, तब

चिंता की एक बात ये भी है कि लक्ष्य हासिल करने की होड़ में सरकारी मशीनरी जैसे-तैसे शौचालय बना रहे हैं. उसकी तस्वीर ले कर मंत्रालय को भेज रहे हैं और किसी तरह आंकड़ा बढ़ाने की जुगत में लगे हैं. बिना दरवाजा, बिना पानी की व्यवस्था किए ऐसे शौचालय भी बनाए जा रहे हैं जो बारिश के दिनों में शायद इस्तेमाल के लायक भी न रहें.

जाकर ये काम पूरा हो सकेगा. यानि, अगस्त 2016 से अक्टूबर 2019 सरकार को प्रति घंटा 3179 शौचालय या प्रति सेकंड एक शौचालय का निर्माण करना होगा, तब कहीं जा कर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अब ये देखते हैं कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कितने शौचालय बने? इस वित्त वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भारत में 1.26 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, यानि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो निर्माण दर चाहिए था (प्रति सेकंड एक शौचालय), उससे काफी कम है ये संख्या. अगर इस हिसाब से काम हुआ तो ये लक्ष्य 2022 तक पूरा हो सकता है. लेकिन, इसी के साथ हम आपको 20 केंद्रीय मंत्रियों के संसदीय क्षेत्रों का भी ब्योरा बता रहे हैं (देखे बॉक्स, आंकड़ा स्रोत: सीएसई) जिसके हिसाब से कई इलाकों में यह काम साल 2019 तक भी पूरा हो जाए तो गनीमत है.

इसके अलावा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां खुले में शौच की समस्या अभी भी विकराल स्वरूप में है. देशभर में खुले में शौच करने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों में है. उत्तर प्रदेश में करीब 273 लाख ग्रामीण परिवारों में लगभग 54 प्रतिशत लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं. केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक (जून, 2017 के आंकड़े), भारत में 2 अक्टूबर 2019 तक 6.4 करोड़ घरों में शौचालय बनाने की जरूरत है. इन परिवारों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 23 प्रतिशत, बिहार का 22 प्रतिशत, ओडिशा का 8 प्रतिशत और झारखंड का 4 प्रतिशत है. इसके अलावा, एक और भी समस्या है. सरकार के मुताबिक, अभी जितने शौचालय हैं, उनमें से अधिकांश ऐसी स्थिति में हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. पूरे देश भर में 79 लाख शौचालय बेकार पड़े हैं, जबकि बिहार में 8.2 लाख, झारखंड में 6.8 लाख, 2.1 लाख ओडिशा में और 16 लाख उत्तर प्रदेश में ऐसे शौचालय हैं, जो बेकार हैं, यानि इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं. इन्हें फिर से बनाना होगा.

इसके अलावा, चिंता की एक बात ये भी है कि लक्ष्य हासिल करने की होड़ में सरकारी मशीनरी जैसे-तैसे शौचालय बना रहे हैं. उसकी तस्वीर ले कर मंत्रालय को भेज रहे हैं और किसी तरह आंकड़ा बढ़ाने की जुगत में लगे हैं. बिना दरवाजा, बिना पानी की व्यवस्था किए ऐसे शौचालय भी बनाए जा रहे हैं जो बारिश के दिनों में शायद इस्तेमाल के लायक भी न रहें. ऐसे में खुले में शौच से मुक्ति का तात्कालिक राजनीतिक जुमला तो उछाला जा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर लोग फिर से खुले में शौच के लिए मजबूर हो जाएंगे. एक बड़ी समस्या उनलोगों की भी है, जिनके पास रहने के लायक भी जमीन नहीं है. ऐसे लोग भला कहां से अपने लिए शौचालय बनवा सकते हैं. सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के घर और शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध कराना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

नर्मदा सरदार सरोवर बांध विस्थापितों की मांग

विस्थापन मंज़ूर पर पहले हो पुनर्वास

चौथी दुनिया ब्यूरो

नर्मदा आंदोलन ने पर्यावरण तथा विकास के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पहले नर्मदा विस्थापितों को दो हेक्टेयर जमीन के बदले 60 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, तभी सरकार को जमीन खाली कराने का अधिकार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है. शुरू में आंदोलनकारियों की मांग लोगों के विस्थापन और पर्यावरण विनाश को रोकना था. लेकिन सरकार की हठधर्मिता से लाचार होकर अब उनकी मांग उचित पुनर्वास पर आ टिकी है.

नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था. गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच जल वितरण को लेकर उस दौरान सहमति नहीं बन पाने के कारण परियोजना पर काम शुरू नहीं हो सका. इसके बाद 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था. इसके बाद ही नर्मदा घाटी परियोजना पर काम शुरू हुआ. इसमें नर्मदा नदी व उसकी 4134 सहायक नदियों पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया जाना है. इसके अलावा 28 मध्यम बांध तथा तीन हजार जल परियोजनाओं का निर्माण भी होना है.

विलंब से बढ़ा परियोजना का ख़र्च

सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की सवा दो करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा. बिजली का निर्माण होगा, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा और क्षेत्र में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी रोका जा सकेगा. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, इस परियोजना से तीन राज्यों की 37 हजार हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी. सरदार सरोवर से तीन राज्यों के लाखों लोग उजड़ने जा रहे हैं. महाराष्ट्र के करीब चार हजार, गुजरात के पांच हजार और मध्य प्रदेश के पैंतालीस हजार से अधिक परिवार डूब क्षेत्र में आ रहे हैं. इस परियोजना के विरोध ने धीरे-धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी है. इस परियोजना की कुल लागत का आकलन अंतिम बार 1999 में किया गया था. तब इसकी लागत 22 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी. कम-से-कम तीन बार कुल लागत का आकलन किया गया है. हर बार यह लागत बढ़ती जा रही है. सरकार इसके लिए आंदोलनकारियों को दोषी ठहराती है. उसका तर्क है कि आंदोलनकारियों के कारण परियोजना शुरू होने में विलंब हो रहा है, जिससे इसकी लागत बढ़ती जा रही है.

डूब आएगी, तब भी नहीं छोड़ेंगे ज़मीन

1980 में नर्मदा बांध से विस्थापित मध्य प्रदेश के 19 गांवों के आदिवासियों को गुजरात के जिला नर्मदा के केवाडिया कॉलोनी स्थित पुनर्वास स्थल पर भेजा गया था. 36 साल बाद गुजरात सरकार ने उन्हें पुनर्वास स्थल से दोबारा विस्थापित करने का निर्णय लिया. सरकार ने उनसे कहा कि उन्हें गलत पात्रता के आधार पर लाभ दिए गए. सरकार की इस बेरुखी से नाराज 1000 आदिवासी और किसान केवाडिया कॉलोनी स्थित पुनर्वास कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि पुनर्वास स्थल के पास न तो पानी की सुविधा है और न ही जल निकासी व अन्य बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध हैं. ट्रिब्यूनल अवार्ड के तहत जो सिंचाई का लाभ मिलना था, वह भी पुनर्वास स्थल पर अभी तक नहीं पहुंचा है. अब विस्थापितों ने भी तय कर लिया है कि अगर डूब आएगी, तब भी नर्मदा किनारे से नहीं हटेंगे. वहीं, गुजरात सरकार प्रभावितों की इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल रही है और न ही उनकी शिकायतों पर ध्यान दे रही है.

विस्थापितों को नर्मदा मां का सहारा

छोटा बड़दा गांव के बाहर ग्रामीणों ने एक तख्ती लगा दी है, यहां सिर्फ भूत-प्रेत रहते हैं. सरकार दावा कर रही है कि यह गांव खाली कराया जा चुका है, जबकि ग्रामीण वहां डटे हैं. उन्हें उम्मीद है कि नर्मदा मां उनकी रक्षा करेंगी. सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर कहती हैं कि पुनर्वास के नाम पर आज तक लोगों से सरकार ने झूठे वादे किए हैं. सरकार पहले पुनर्वास और मुआवजे का इंतजाम करे, फिर बांध का निर्माण शुरू करे. वे सैकड़ों महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में बड़वानी ज़िले के छोटा बाड़दा गांव में उचित पुनर्वास की मांग को लेकर नर्मदा में जल सत्याग्रह कर रही हैं. मध्यप्रदेश की नर्मदा घाटी में बड़वानी के पास हजारों महिलाएं जल सत्याग्रह में उनका साथ दे रही हैं. लोगों का कहना है कि सरकार विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे रही है. विस्थापितों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अगर पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, तो वे इसकी शिकायत जीआरए के समक्ष कर सकते हैं. लोगों ने शिकायतें दर्ज कराईं, पर न तो उनकी मांगें सुनी गईं और न ही सुविधाओं में कोई सुधार हुआ.

सरकार के वादों से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज़

1995 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार बांध के काम को तब तक रोक दे, जब तक कि लोगों का उचित पुनर्वास नहीं हो जाता. अप्रैल 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा परियोजना से जुड़ी राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि यदि उचित पुनर्वास नहीं हुआ, तो निर्माण रोक दिया जाएगा. अब तो आलम यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के वादों पर सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है. इसका प्रमाण यह है कि कोर्ट ने सरकार द्वारा विस्थापितों को दिए गए मुआवजे और पुनर्वास किए जाने का सरकार से सबूत मांगा है. पूरी दुनिया का ध्यान दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर बांध विस्थापितों के आंदोलन पर टिका है. विश्व बैंक ने भी 1994 में सही तरीके से विस्थापन नहीं होने पर परियोजना से अपने हाथ खींच लिए थे. इसके अलावा, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ दल ने 1993 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि परियोजना में पर्यावरण की भारी अनदेखी की गई.

प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव की हड़बड़ी में हैं. वे चाहते हैं कि नर्मदा विस्थापितों का मुद्दा उनके सियासी सफर में बाधा न बने, इसलिए आनन-फानन में सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन भी कर दिया गया है. साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि चुनाव से पूर्व मध्यप्रदेश का पानी गुजरात तक पहुंच जाए. लेकिन इस हड़बड़ी में वे यह भी भूल गए कि अभी तो गुजरात में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें ही नहीं बनी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिला आरक्षण विधेयक

आधी आबादी को चाहिए पूरा अधिकार

शफीक आलम

महिलाओं को लोक सभा और राज्यों के विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों का अब तक का रवैया 'साफ़ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं' का रहा है. दोनों पार्टियां महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं. आधिकारिक तौर पर दोनों ने महिला आरक्षण विधयक को समर्थन दे रखा है, लेकिन जब भी इस विधयक को पारित करने की कोशिश की जाती है, कोई न कोई अड़चन आ जाती है. नतीजा यह होता है कि यह मामला ठन्डे बस्ते में चला जाता है. अब तक इस बिल का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी राजनैतिक रोटियां ही सेंकती रही हैं.

सोनिया गांधी का पत्र

बहरहाल एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में है. अभी सरकारी हलकों में इस बिल को लेकर कुनमुनाहट हो रही थी कि सोनिया गांधी ने भी एक तीर छोड़ दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर इस विधयक को पारित करवाने की गुहार लगा दी. अपने पत्र में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि आपकी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, इसलिए इस बहुमत का लाभ उठाते हुए आप लोकसभा में महिला आरक्षण विधयक को पारित करवाएं. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस विधेयक का साथ दिया है और आगे भी देती रहेगी. सोनिया गांधी ने यह भी याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के विचार को आगे बढ़ाया था, जिसे विपक्षी दलों ने 1989 में राज्यसभा से पारित नहीं होने दिया था. वो विधेयक आखिरकार 1993 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था. ज़ाहिर है कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 10 साल तक सत्ता में रही. उस दौरान इस बिल को पारित करवाने की कोशिशें भी की गई और 2010 में इसे राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगियों के विरोध के कारण यह बिल लोकसभा से पारित नही हो सका. कारण यह बताया गया कि इस बिल को पारित करने से यूपीए सरकार संकट में आ जाती. गौरतलब है कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था. तो सवाल यह उठता है कि मनमोहन सिंह ने जो इच्छा शक्ति उस समय दिखाई थी, वो इच्छा शक्ति इस विधेयक पर उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में क्यों नही दिखाई? और जब राज्यसभा से यह बिल पारित हुआ तो क्या उस समय सरकार पर संकट के बादल नहीं मंडराए थे?

बहरहाल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के इस विधेयक के विरोध में होने का मुख्य कारण पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं. उनका कहना है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और उनके लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए. शरद यादव का विवादास्पद बयान भी इसी वजह से आया था. ज़ाहिर है यह मामला जितना लैंगिक असमानता का है, उतना ही राजनैतिक भी है. इसमें हरेक पार्टी के अपने-अपने हित हैं, लेकिन यह तो तय है कि भारत में आधी आबादी को देश के अहम फैसलों में हिस्सेदारी से दूर रखा जाता है. इसलिए यह जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले दूसरे देशों की स्थिति क्या है और भारत उनके मुकाबले में कहां खड़ा है?

संसद में महिला आरक्षण बिल कुछ तथ्य

- एचडी देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार सितंबर 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की कोशिश की थी
- जून 1997 में एक बार फिर इस विधेयक को पास कराने का प्रयास हुआ.
- शरद यादव ने 'परकटी महिलाएं' वाला अपना विवादास्पद बयान दिया था.
- साल 1998 में 12 वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार ने इस विधेयक को पेश करने की कोशिश की.
- फिर बाद में एनडीए की सरकार ने दोबारा 13 वीं लोकसभा में 1999 में इस विधेयक को पेश करने की कोशिश की, लेकिन संसद में शोरगुल की वजह से इसे पारित नहीं किया जा सका.
- 2003 में एनडीए सरकार ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी यह विधेयक हंगामे की भेंट चढ़ गया
- हालांकि 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ.

अन्य देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी

विश्व शांति के लिए काम करने वाली जेनेवा स्थित संस्था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (आईपीयू) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में वर्षों गृहयुद्ध की आग में जलने वाला अफ्रीकी देश रवांडा पहले स्थान पर है. वहां संसद में महिलाओं की भागीदारी 61 प्रतिशत है. हैरानी की बात यह है कि दुनिया में लोकतंत्र के अभिभावक होने का दावा करने वाले देश अमेरिका की कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी केवल 19.4 प्रतिशत है. आईपीयू के आंकड़ों में हैरानी वाली दूसरी बात यह है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में रवांडा के साथ-साथ बोलीविया, क्यूबा, निकारागुआ, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ऐसे विकासशील देश हैं, जहां महिलाओं की भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक है. संसद में 40 प्रतिशत या उससे अधिक महिला भागीदारी वाले यूरोपीय देशों में केवल तीन देश आइसलैंड, स्वीडेन और फिनलैंड शामिल हैं. लेकिन कुल मिला कर इस मामले में यूरोपीय देशों की स्थिति ठीक-ठाक है. जहां तक एशियाई देशों का सवाल है तो भारत का पड़ोसी नेपाल महिला प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे ऊपर है. वहां लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं चुनकर संसद पहुंची हैं. जहां तक भारत का सवाल है तो यहां संसद में महिलाओं की भागीदारी केवल 11 प्रतिशत है. भारत में 542 सांसदों में केवल 64 महिलाएं शामिल हैं. दरअसल भारत इस मामले में अपने पड़ोसियों अफगानिस्तान (27.7 प्रतिशत) पाकिस्तान (20.6 प्रतिशत) और बांग्लादेश (20.3 प्रतिशत) से भी काफी पीछे है.

श्रेय लेने की होड़

उक्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि भारत को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो देश की आधी आबादी को देश के फैसलों से दूर नहीं रखा जा सकता है. अब रही राजनीति की बात तो यह साफ़ है मोदी सरकार 2019 के चुनावों की तैयारी में जुट गई है. पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं पर ख़ास ध्यान दिया है. मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने तीन तलाक के मसले को उठाया, उसी तरह उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है. यदि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो यह ऐसा मुद्दा है जिसके कारण बार-बार यह विधयक ठंडे बस्ते में चला जाता है. लेकिन यदि सरकार इस विधयक में संशोधन कर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किए जाने पर सहमत हो जाए तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है. भाजपा यह संशोधन करने के लिए शायद तैयार भी हो जाए क्योंकि भाजपा और मोदी दोनों की नज़रें लगातार पिछड़े वर्ग के वोटरों पर बनी हुई है. यदि ऐसा हुआ तो इस वर्ग के वोटों पर भाजपा की दावेदारी मज़बूत हो जाएगी. दरअसल यह मान लेना कि भारत में महिलाएं अलग वर्ग नहीं हैं, सही नहीं है. इसका उदाहरण बिहार में देखने को मिला जहां महिलाओं का मुद्दा उठाने की वजह से हर वर्ग की महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया था.

इसमें कोई शक नही कि यदि मोदी सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाता है तो वो चुनावों में इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश करेगी. प्रधानमंत्री के नाम सोनिया गांधी का पत्र इसलिए भी लिखा गया है ताकि कहीं अकेले भाजपा ही महिला आरक्षण विधयक पारित कराने का श्रेय न ले जाए. बहरहाल राजनैतिक दांवपेंच अपनी जगह लेकिन सोनिया गांधी के पत्र ने जहां एक तरह इस गेंद को भाजपा के पाले में डाल दिया है, वहीं महिला आरक्षण को एक बार फिर चर्चा में ला खड़ा किया है. अब देखना यह है कि देश की आधी आबादी को कब तक उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मज़बूत करने में जुटे दिग्गी राजा

रुपेश गुप्ता

दिग्विजय सिंह दो दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा पर थे. वे डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने आए थे. वे अपनी निजी यात्रा के दौरान कांग्रेस के भीतर के समीकरणों को ठीक करने में जुटे रहे. यात्रा के दौरान भूपेश बघेल को संदेश दिया कि वे सबको साथ लेकर चलें. चाहे, इसे लेकर कितना भी विरोध हो. अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान एक दफे नहीं, कई दफे दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया कि पार्टी में मतभेद है. अगर ये मतभेद दूर कर लें, तो पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत जाएगी. लेकिन जाते-जाते उन्होंने भाजपा के बारे में ऐसा बयान दे दिया कि कांग्रेस की कलह की खबरों पर चटखारे लेने वाले भाजपा नेताओं के पसीने आ गए. दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार में कलह इतनी बढ़ चुकी है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री के काले चिट्ठे लेकर कांग्रेस के नेताओं के पास आ रहे हैं और कांग्रेस इसके आधार पर समय-समय पर उनकी पोल खोल रही है. तो क्या माना जाए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी मंत्रियों के खिलाफ जितने खुलासे हुए हैं, वो सब बीजेपी के ही दूसरे मंत्री की कारगुजारी है?

दिग्विजय ने जो आरोप लगाए हैं, उसकी फुसफुसाहट अक्सर राजनीतिक गलियारों में सुनाई पड़ती थी. लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसे खुलकर बोल दिया. दरअसल इस बात को जानने से पहले बीजेपी की अंदरुनी राजनीति को समझना पड़ेगा. प्रदेश सरकार में बीजेपी में दो खेमे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं. एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं तो दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल. रमन सिंह के चेहरे के पीछे नौकरशाहों की फौज और पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत हैं तो बृजमोहन के साथ बीजेपी के प्रेम प्रकाश पांडेय और देवजी भाई पटेल जैसे नेता.

रमन सिंह के कुछ विरोधी सरकार के बाहर हैं, जिसमें संघ से करीब से जुड़े नंदकुमार साय हैं. बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रमेश बैस और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय हैं. इन नेताओं को सरकार के मंत्रियों का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन दिल्ली तक अपनी पकड़ के बूते ये लोग रमन विरोधी अभियान में सक्रिय माने जाते हैं.

इनके अलावा कुछ मंत्री हैं, जो अपनी जाति या समुदाय के आधार पर आने वाले दिनों के ख्वाब बुन रहे हैं. सरगुजा से आने वाले राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, बस्तर से केदार कश्यप और नंदकुमार साय जो आदिवासी समुदाय के नाते अपनी दावेदारी करते रहते हैं. इसी तरह अजय चंद्राकर ओबीसी तबके के आसरे आगे बढ़ना चाहते हैं.

लेकिन जब भी प्रदेश में इनके द्वारा आदिवासी मुख्यमंत्री या फिर ओबीसी मुख्यमंत्री का शिगूफा छेड़ा जाता है, सरकार के कुछ बेहद शक्तिशाली नौकरशाह इनके खिलाफ किसी मामले को उछाल देते हैं. कहा जाता है कि ज़मीन मामले में अजय चंद्राकर के फंसने और अपनी बीवी की जगह किसी और को बिठाकर परीक्षा दिलाने के आरोप जब मंत्रियों पर लगे, उससे पहले ये नेता ओबीसी और आदिवासी सम्मेलन करके लामबंदी की कोशिशों में जुटे थे.

अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल माने जाते हैं. कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल ने किसी कैबिनेट मीटिंग में बड़े अधिकारी को झिड़क दिया था. इसके अलावा वे दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ सक्रिय रहे, जिसके बाद उनके अवैध रिजॉर्ट का मामला सामने आया. अपने मामले पर बृजमोहन ने साफ इशारा किया कि पार्टी के कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं. वो ऐसे कुछ और मामले लेकर सामने आएंगे. एक चैनल के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वे बाकी लोगों का काला चिट्ठा खोलेंगे. हालांकि बाद में बृजमोहन ने साफ कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है.

इसी दौरान पनामा में फंसने के बाद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान कोर्ट ने हटा दिया. राहुल गांधी ने बस्तर दौरे पर कह दिया कि पाकिस्तान में पनामा में नाम आने पर कोर्ट पीएम को हटा देती है लेकिन बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के बेटे (अभिषेक सिंह) का नाम सामने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती. अब कांग्रेस पर घेरे में सरकार के दोनों शीर्ष नेता थे. विधानसभा का सत्र चल रहा था. लेकिन अचानक विधानसभा स्थगित कर दी गई. मामले शांत पड़ गए. फिर सामने आई कई तरह की बातें, जिसमें रमन सिंह और बृजमोहन के बीच पैचअप की अलग-अलग वजहें बताई गई थीं. लेकिन इस बीच दोनों के रिश्ते की कड़वाहट छिपी नहीं.

इधर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर फर्जी जाति का मामला सामने आने के बाद नंदकुमार साय ने राज्य सरकार पर इस बात को लेकर हमला बोल दिया कि सरकार जोगी को बचा रही है. उनका आरोप है कि कानून के मुताबिक अजीत जोगी के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. लेकिन जब प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया. रमैश बैस अलग से नाराज़ हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें अलग-थलग करने की साज़िश रमन सिंह के लोगों की है. बीजेपी के दूसरे नेता जो अधिकारियों की प्रताड़ना के शिकार हैं वो भी मौके की ताक में हैं.

इस गुटबाजी से स्वाभाविक फायदा कांग्रेस को होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस खुद गुटों में बंटी है. जब तक पार्टी में अजीत जोगी थे, तब तक ठीक था. सभी नेता जोगी के खिलाफ एकजुट थे. जोगी जैसे ही पार्टी से अलग हुए, स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हिलोरें मारने लगीं.

इसकी बानगी पार्टी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में दिखने लगी. चरण दास महंत और भूपेश बघेल में जांजगीर- चांपा के पद को लेकर तनातनी हो गई. दोनों नेताओं के बीच हालात ऐसे बन गए हैं कि कभी एक दूसरे के बेहद करीबी रहे भूपेश और महंत एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहे हैं.

सत्यनारायण शर्मा भूपेश बघेल से तब से नाराज़ हैं, जब से भूपेश ने उन्हें लोकसभा की टिकट मिलने का विरोध किया था. रविंद्र चौबे, धनेंद्र साहू को शिकायत है कि पार्टी में उनकी वरिष्ठता के मुताबिक पूछ-परख कम हो गई है. जिलाध्यक्षों की तकरार की खबर जब आलाकमान को लगी तो उन्होंने पैचअप कराने का जिम्मा दिग्विजय सिंह को सौंपा. जो उसी वक्त डोंगरगढ़ जाने वाले थे. दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यक्रम में फेरबदल की और फिर रायपुर में नेताओं से इस संबंध में काफी बातें की. जाते-जाते दिग्विजय भूपेश बघेल को नसीहत दे गए कि वे सबको साथ लेकर चलें.

दिग्विजय ने खुलकर कहा कि कांग्रेस की सत्ता की राह में नेताओं का मतभेद सबसे बड़ा रोड़ा है. लेकिन दिलचस्प बात है कि जब वे मध्यप्रदेश जा रहे थे तब कमलनाथ का ये बयान आ गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे. दिग्विजय ने कमलनाथ के इस बयान को खारिज़ कर दिया. वो ज्योतिरादित्य को कमान देने के हक में नहीं दिखे.

ज़ाहिर है वे खुद मध्यप्रदेश में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो कैसे किसी और को उस राज्य की कमान सौंप दें जिस पर वो आज भी अपना सबसे बड़ा दावा समझते हैं. राजनीति चाहे जहां की भी हो यही सच है कि कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता. ■

feedback@chauthiduniya.com

कोई नहीं कम, चालीस पर दम

सरोज सिंह

लोकसभा चुनाव में भले ही काफी वक्त है, पर बिहार में एनडीए के घटक दलों ने सूबे की सभी चालीस सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसका दिलचस्प पहलू यह है कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग इन सीटों पर अपना कील कांटा दुरुस्त करने में लगे हैं. भाजपा और जदयू का अभियान तो चल ही रहा है पर लोजपा, हम और रालोसपा भी पूरी ताकत इन सीटों पर लगा रही है. माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद सभी घटक दल लोकसभा क्षेत्रों में अपनी दोगुनी ताकत झोंकेंगे.

जदयू के आने से सीटों का बंटवारा मुश्किल

औपचारिक तौर पर सभी घटक दलों का कहना है कि हमारा आपस में कोई टकराव नहीं है. अगर चालीस सीटों पर सभी घटक दल तैयारियों में जुटे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस बार हमलोग सौ फीसदी रिजल्ट चाहते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी और प्रचंड बहुमत से सरकार बना सकें. लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बात इतनी आसान नहीं है. एक तो इस बार पहले ही एनडीए घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुश्किल था, अब जदयू के आ जाने के बाद तो रास्ता और भी कठिन हो गया है. जदयू के आने के पहले ही यह धारणा मजबूत हो रही थी कि 2014 के चुनावों में लोजपा और रालोसपा को कुछ अधिक सीटें दे दी गईं. अब जदयू के आने के बाद तो नए सिरे से सीटों को बांटना होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह नहीं चाहेंगे कि जदयू किसी भी सूरत में लोजपा या रालोसपा के आस पास दिखे, इसलिए हर हाल में उनकी चाहत दस से अधिक सीटों की होगी. ऐसे में कोटा लोजपा और रालोसपा का ही कटेगा. अभी रालोसपा सांसद अरुण सिंह के बारे में यह तय माना जा रहा है कि वे भाजपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे.

25-15 पर होगा समझौता

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि भाजपा कम से कम सूबे की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 15 सीटों का बंटवारा सहयोगी दलों के बीच होगा. भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्र बतलाते हैं कि अमित शाह एंड कंपनी की बैठक में यह राय बन गई है कि 25 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा. 25 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी उतरेंगे, बाकी 15 सीटों पर सहयोगी दलों के बीच तालमेल कराने का प्रयास पार्टी करेगी. अगर कोई नहीं माना तो इस बार ज्यादा मान मनौव्वल भी नहीं किया जाएगा. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इसी एप्रोच ने सहयोगी दलों की नींद उड़ा दी है. सहयोगी दलों को लगता है कि अगर अंतिम समय में बात बिगड़ गई

तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए संभल कर रहने में ही भलाई है. यही वजह है कि जदयू, रालोसपा और लोजपा ने भी सूबे की सभी चालीस सीटों पर अपना दम लगाना शुरू कर दिया है.

संगठन की मज़बूती में जुटे घटक दल

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सभी 40 संसदीय सीटों पर पार्टी संगठन को मजबूत

जदयू का जनवरी से जून-2018 तक का कैलेंडर

- प्रकोष्ठों की प्रखंड-नगर क्षेत्र की बैठक हर माह पहले रविवार को
- 7 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 1 अप्रैल, 6 मई व 3 जून
- प्रकोष्ठों के जिला-नगर की बैठक हर माह के दूसरे रविवार को
- 14 जनवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च, 8 अप्रैल, 13 मई और 10 जून
- प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हर माह के तीसरे रविवार को
- 21 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च, 15 अप्रैल, 20 मई और 17 जून
- प्रदेश पदाधिकारियों व राज्य कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक
- 28 जनवरी, 25 मार्च और 27 मई
- पंचायत से प्रदेश तक के प्रत्येक पदाधिकारी निजी आवास पर पार्टी का झंडा और नेम प्लेट लगाएंगे
- महापुरुषों की जयंती और मद्य निषेध दिवस राज्यभर में पार्टी की ओर से मनाई जाएगी.

किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, परन्तु संगठन की मजबूती का लाभ हमें स्वाभाविक रूप से चुनाव में मिलेगा. आरसीपी सिंह ने कहा कि जिन जिलों में भाजपा के मंत्री प्रभारी हैं, वहां संगठन की देखरेख के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी. जदयू के 14 मंत्री हैं, जिन्हें संगठन की देखरेख के लिए अन्य 24 जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा. 15-18 नवंबर के बीच सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ नेता एवं सांसद की टीम शामिल होगी. अगले दो माह में बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त कर दिए जाएंगे. पार्टी नेताओं से सहयोग के तौर पर धनराशि लेने का भी फैसला लिया गया है. इसके लिए नवंबर एवं दिसंबर में अभियान चलाया जाएगा. जदयू पूरे बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कितना गंभीर है, इसका प्रमाण राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी मिला.

दहेजप्रथा पर चलेगा अभियान

जदयू ने नीतीश कुमार की उपस्थिति में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कई कार्यक्रम भी तय किए. लोहिया की पुण्यतिथि पर 12 अक्टूबर को हर जिले में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ पार्टी अभियान चलाएगी. साथ ही प्रखंड स्तर पर महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों की जयंती अब मुख्यालय स्तर पर ही नहीं, प्रखंड स्तर तक मनाई जाएगी. मकसद नई पीढ़ी को इन महापुरुषों के संबंध में जानकारी देना है. नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्य सिर्फ प्रदेश मुख्यालय तक सीमित नहीं रखें, इसे निचले स्तर यानी पंचायत तक मनाएं. कहा जाए तो जदयू ने कमर कस ली है. इसी तरह की तैयारी उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं. अपनी ताकत दिखाने के लिए 15 अक्टूबर को वे गांधी मैदान में एक बड़ी रैली कर रहे हैं. इसमें कोशिश है कि सूबे के हर बूथ से लोगों को जुटाया जाए. रालोसपा नेता रामबिहारी सिंह कहते हैं कि सभी चालीस सीटों पर संगठन मजबूत होगा तो आखिरकार फायदा तो एनडीए को ही मिलेगा. हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और लोकसभा चुनावों में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहेगा. लोजपा भी जिलास्तर पर अपने सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी है.

जहां तक भाजपा का सवाल है तो वह सभी चालीस सीटों पर सघन अभियान चला रही है. जिन सीटों पर पिछले चुनावों में एनडीए की हार हुई थी उस पर खास फोकस किया जा रहा है. पार्टी अध्यक्ष नित्यानंद राय सभी जिले के दौरे पर निकल रहे हैं, ताकि जमीनी हकीकत से खुद अवगत हो सकें. श्री राय के दौरे के दौरान मौटे तौर पर प्रत्याशियों की लोकप्रियता और उनके जीतने की संभावनाओं पर जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा. भाजपा चाहती है कि अभी से एक मजबूत आधार तैयार कर लिया जाए ताकि आने वाले दिनों में कई तरह के कार्यक्रमों को अंजाम देकर संगठन को धारदार बनाया जा सके. यह तय हो गया है कि भाजपा इस बार 2014 से ज्यादा आक्रमक तेवर में चुनावी मैदान में उतरेगी और कोशिश होगी कि अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर सभी चालीस सीटों पर जीत का परचम लहराया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीमा पार व्यापार पर एनआईए की नज़र

पीडीपी-भाजपा मतभेद से व्यापारियों को नुक़सान

हारून रेशी

सितंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के बीच न्यूयॉर्क में एक सुखद वातावरण में हुई मुलाकात के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में दोनों देशों के विभाजित कश्मीर के भागों के बीच व्यापारिक संबंध शुरू करने की घोषणा की गई थी. दोनों देशों की इस घोषणा ने दोनों क्षेत्रों यानी कश्मीर घाटी और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कश्मीरियों को पिछले सात दशकों से प्रतीक्षा थी. कश्मीर घाटी में सलामाबाद, चकोठी और जम्मू में पूंछ रावला कोट राजमार्ग व्यापार के लिए खोल दिए गए. दोनों तरफ से मालवाहक गाड़ियों के काफिले सात दशकों के बाद पहली बार 21 अक्टूबर 2008 को रवाना हुए. तय पाया गया कि आर-पार का यह व्यापार बार्टर सिस्टम के तहत होगा. अर्थात इसमें पैसों का कोई लेन-देन नहीं होगा बल्कि वस्तुओं के बदले वस्तु का कारोबार होगा. दरअसल, मसला ये था कि केवल भारत या केवल पाकिस्तान की करेंसी प्रयोग नहीं की जा सकती थी. डॉलर को इस व्यापार के लिए रिफरेंस प्वाइंट बनाने का मतलब इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दर्जा देना था, जो कश्मीर में अस्वीकार्य हो सकता था, क्योंकि कश्मीरियों ने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल को स्वीकार ही नहीं किया है. बहरहाल, 21 विभिन्न वस्तुओं की लिस्ट व्यापार के लिए स्वीकृत की गई. तय ये हुआ कि जम्मू कश्मीर से कालीन, वॉल हैंगिंग, पेपर माशी से बनी चीजें, शॉल, अखरोट की लकड़ी से बनी चीजें, ड्राई फ्रूट, कश्मीरी मसाले, दालें, जाफरान इत्यादि नियंत्रण रेखा के उस पार भेजी जाएंगी और वहां से इसके बदले चावल, लहसन, प्याज, मसाले, ड्राई फ्रूट और पेशावरी चप्पल यहां लाई जाएंगी. शुरुआती कुछ वर्षों में ये व्यापार खूब फला-फूला. व्यापार के लिए सप्ताह में चार दिन आवंटित किए गए. हरेक दिन लगभग तीस माल-वाहक ट्रक कंट्रोल लाइन के उस पार चले जाते थे और लगभग उतने ही मालवाहक ट्रक यहां आ जाते थे. लेकिन फिर अचानक इस सारी प्रक्रिया को किसी की नजर लग गई. आर-पार का

व्यापार कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई.

आर-पार का व्यापार शुरू होने के चार वर्ष बाद अगस्त 2012 में भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से आनेवाले एक मालवाहक ट्रक में से 10 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद हुई है. इसके दो वर्ष बाद, जनवरी 2014 में उस पार से आए एक ट्रक में से 100 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स बरामद हुए. एक वर्ष बाद, फरवरी 2015 में अधिकारियों ने कहा कि एक और ट्रक से बारह किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई. इसके कुछ समय बाद अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से यहां दाखिल होने वाले एक मालवाहक ट्रक में से तीन सौ करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई. इतना ही नहीं, उस साल मार्च में अधिकारियों ने उस पार से आए ट्रक से हथियार भी बरामद करने का दावा किया. इसके बावजूद आर-पार का व्यापार जारी रहा. सरकार ने स्मगलिंग रोकने के लिए आश्वासन दिया, ताकि व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचे. इस साल 29 जुलाई को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्ष और प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरपार के व्यापार का बचाव करते हुए कहा कि स्मगलिंग तो बाघा बॉर्डर से भी होती है, लेकिन उसके कारण तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान व्यापार और लोगों की आवाजाही नहीं रुक जाती है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर-पार के व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे.

ऐसा लगता है कि ये मामला इतना सरल नहीं रहा. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) राय दे रही है कि आरपार का व्यापार हवाला फंडिंग से जुड़ा है. एनआईए ने इस साल जुलाई में केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट पेश करते हुए जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के आर-पार जारी व्यापार को फिलहाल बंद करने की सलाह दी है. अपनी रिपोर्ट में एनआईए ने कहा है कि अबतक जम्मू कश्मीर में इस आर-पार व्यापार से 2770 करोड़ रुपए का फर्जी लेन-देन हुआ है. एनआईए ने व्यापारियों का रिकॉर्ड जब्त किया है. 40 व्यापारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इनमें से 15 व्यापारियों के घरों पर छापे मारे गए हैं, तलाशियां ली गई हैं. इससे साफ जाहिर है कि आर-पार व्यापार के हवाले से अब मामला बहुत गंभीर बन चुका है. पिछले पांच वर्षों से आर-पार व्यापार करने वाले समीउल्ला कहते हैं कि हमें एनआईए की जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यापारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली और लखनऊ न बुलाया जाए. एनआईए जब किसी व्यापारी को दिल्ली या लखनऊ हेडक्वार्टर पर बुलाती है, तो न केवल उसे बल्कि उसके घरवालों को भी बहुत परेशानियां होती हैं. समीउल्ला ने चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ये मामला गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नोटिस में भी लाया है. गृहमंत्री ने तो उस समय आश्वासन दिया था, इसके बावजूद व्यापारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ. एक और व्यापारी ने अपना नाम छिपाने की शर्त पर बताया कि हम इस बात से चकित हैं कि नौ वर्ष बाद इस व्यापार पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. हम व्यापारी हैं, आतंकवादी नहीं हैं.

व्यापारियों में एक आम धारणा है कि जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के आर-पार की इस व्यापार के संबंध में पीडीपी और भाजपा के बीच मतभेद होने की वजह से व्यापारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. फारूक अहमद वाणी नाम के एक व्यापारी ने चौथी दुनिया के साथ बात करते हुए कहा कि सच बात तो यह है कि ये लड़ाई पीडीपी और भाजपा की है. भाजपा नहीं चाहती कि कंट्रोल लाइन के आर-पार व्यापार कायम रहे, इसीलिए एनआईए द्वारा उसे बदनाम किया जा रहा है. अगर सचमुच इस व्यापार द्वारा कोई हवाला फंडिंग होती, तो एनआईए इस केस में अबतक अपराधियों की निशानदेही कर चुकी होती. सबूत सामने लाए गए होते और गिरफ्तारियां होती और सबसे अहम कि अदालत में चार्ज सीट दाखिल कर दी गई होती. एनआईए पिछले कई महीनों से जांच के नाम पर केवल व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है. ये कैसी जांच है, जो खत्म ही नहीं हो रही है. अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए. हर दस दिन बाद जांच के नाम पर छापे मारना और रिकॉर्ड जब्त करने से क्या होगा? सच तो यह है कि आरपार व्यापार को पहले की तरह से जारी रखने के लिए आवश्यक है कि एनआईए और सरकार पहले व्यापारियों को क्लीन चीट दे. शायद ये तभी संभव हो पाएगा, जब गठबंधन सरकार की दोनों इकाइयां यानी पीडीपी और भाजपा दोनों में आरपार के व्यापार को कायम रखने पर सहमति बने. ■

feedback@chauthiduniya.com

आलाकमान को ख़ुश करने के लिए झारखंड भाजपा ने किया करोड़ों ख़र्च

शहंशाह की तरह हुआ शाह का स्वागत

प्रशांत शरण

मिशन 2019 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर रांची आये थे. यहां भाजपा ने शाह का स्वागत शहंशाह की तरह किया. आखिर हो भी क्यों नहीं, शाह का रुतबा पार्टी में क्या है, ये तो सभी को पता है. मुख्यमंत्री रघुवर दास भी यह भली-भांति जानते हैं कि शाह खुश तो सब खुश. इस बार भी मुख्यमंत्री ने शाह को खुश करने में कोई कोर-कसर नही छोड़ी. पूरे शहर को बैनर होर्डिंग्स एवं झंडों से पाट दिया गया था. कार्यक्रम स्थल इतना भव्य बनाया गया कि उसे देखकर अमित शाह गदगद हो गए. अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास था. यह दौरा एक तरह से आलाकमान की तरफ से रघुवर दास के प्रदर्शन का निरीक्षण भी था और जिस तरह इस से अमित शाह की आवभगत हुई, उससे वे खूब खुश भी हुए. मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पता है कि अगर शाह का आर्शीवाद इन्हें मिलता रहा, तो फिर किसी अन्य के समर्थन की जरूरत नहीं है.

ख़ातिरदारी में पानी की तरह बहाया पैसा

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पानी की तरह पैसे बहाए. उनके स्वागत में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई. कारों के काफिले से लेकर, आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल और रहने-खाने के लिए भी शाही व्यवस्था की गई थी. पूरे शहर को भाजपाई झंडों, बैनरों और होर्डिंग्स से पाट दिया गया था. राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठहरने के लिए लगभग तीन करोड़ की लागत से स्टेट गेस्ट हाउस को सजाया-संवारा गया था. गेस्ट हाउस में पंद्रह लाख कीमत का रिमोट कंट्रोल वाला झुमर भी लगा था. लेकिन मीडिया में इसे लेकर खबरें आने के बाद अमित शाह ने भाजपा कार्यालय में ही रुकने का मन बनाया. उसके बाद आनन-फानन में भाजपा कार्यालय को भी सजाया-संवारा गया. पार्टी के एक वरीय नेता की बातों पर विश्वास करें, तो शाह के इस तीन दिवसीय दौरे पर उनके स्वागत में 20-25 करोड़ रुपए खर्च किए गए. उत्तम स्वागत व्यवस्था व आवभगत से खुश अमित शाह ने रघुवर सरकार के कार्यकलापों पर तो अपनी मुहर लगा दी, लेकिन वे संगठन के कार्यों से खुश नजर नहीं आए.

सरकार, संगठन और संघ में समन्वय की कोशिश

अमित शाह ने अपने इस दौरे पर प्रदेश सरकार, प्रदेश भाजपा संगठन और आरएसएस के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी की. इस दौरे पर अमित शाह के साथ पार्टी के दो महासचिव एवं संगठन मंत्री भी थे. पार्टी अध्यक्ष आरएसएस कार्यालय जाकर संघ के नेताओं से मिले. वहां संघ के नेताओं के साथ अमित शाह की गहरी मंत्रणा हुई. संघ के नेताओं ने भाजपा संगठन एवं सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका साफ तौर पर कहना था कि न तो रघुवर सरकार संघ के नेताओं को तवज्जो देती है और न ही पार्टी संगठन के लोग किसी मुद्दे पर संघ के नेताओं से विचार विमर्श करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यहां समन्वय का घोर अभाव है. पार्टी संगठन में ही नेताओं के बीच समन्वय नहीं है. कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की घोर उपेक्षा होती है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है. भाजपा विधायकों, पार्टी एवं संघ के पदाधिकारियों एवं बोर्ड निगम के अध्यक्ष की बैठक के बाद शाह को भी यह अहसास हुआ कि यहां लोगों के बीच गंभीर मतभेद है. इसके बाद अमित शाह ने उन्हें कई नसीहतें दी. मंत्रियों और विधायकों को कहा गया कि वे जनसंवाद करें, लोगों की समस्याएं सुनें और उनका हल निकालने का काम करें. अमित शाह ने मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों को संकेतों के जरिए ही सही, ये संदेश जरूर दिया कि वे जल्द से जल्द सुधर जाएं और गुटबाजी से बाज आएं. पार्टी के अंदरखाने में टकराव और विघटन की राजनीति करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि अब पार्टी के अंदर टकराव की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा. लंबे समय से निष्क्रीय रहे राज्य संगठन के पदाधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि वे तत्काल प्रभाव से पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार के कामों के प्रचार-प्रसार में जुट जाएं. दरअसल झारखंड भाजपा के भीतर सरकार और पार्टी के लिए विपक्ष से ज्यादा बड़ी चुनौती अपने लोग पेश कर रहे हैं. हाल के दिनों में सीएनटी-एसपीटी, धर्मान्तरण सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को विपक्ष से ज्यादा अपने लोगों के ही विरोध का सामना करना पड़ा है. पार्टी के अंदर से ही आए दिन होने वाली सरकार विरोधी बयानबाजी भाजपा के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है. वैसे भी भाजपा अध्यक्ष का सबसे ज्यादा फोकस झारखंड और बिहार पर ही है. इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार रहने के बाद भी पार्टी के भीतर की गुटबाजी को खत्म नहीं किया जा सका है. यही कारण भी है कि इन दोनों राज्यों में भाजपा संगठन सुदृढ नहीं हो पाया है. अमित शाह भी इन सब बातों को भलीभांति जानते हैं और यही कारण है कि उन्होंने सभी को एकसाथ मिलकर काम करने की नसीहत दी है.

बिरसा मुंडा बहाना है, आदिवासी वोट निशाना है

अमित शाह मिशन 2019 के तहत झारखंड में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ ही दलितों और आदिवासियों का मन टटोलने भी आए थे. उन्होंने लोकसभा की सभी चौदह सीटों और विधानसभा की 60 सीटों के बारे में चर्चा करते हुए पार्टी नेताओं को कई नसीहतें भी दी. आदिवासियों का दिल जीतने के लिए उन्होंने आदिवासी परिवार के यहां भोजन भी किया. साथ ही आदिवासियों का भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहातू जाकर आदिवासी समुदाय को भाजपा के पक्ष में बोलबंद करने का काम किया. उलिहातु में वे बिरसा मुंडा के परिजनों से मिले. अमित शाह ने बिरसा मुंडा के गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे आधुनिक ढंग से उलिहातु का विकास कराएंगे. राजधानी हरम में अमित शाह ने भव्य गरीब कल्याण मेला का उद्घाटन किया और गरीबों के बीच लगभग चार सौ करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया. इसके जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा गरीबों के उत्थान के प्रति कृत संकल्पित है. गौरतलब है कि झारखंड में ज्यादातर आदिवासी नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री रघुवर दास के उपेक्षित व्यवहार के कारण भाजपा से नाराज हैं. उनलोगों ने इसकी शिकायत पार्टी के आला नेताओं से भी की है. सीएनटी-एसपीटी संशोधन विधेयक, धर्मान्तरण विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक आदि को लेकर पहले से ही आदिवासियों में असंतोष व्याप्त है. लिट्टीपाड़ा विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा भुगत भी चुकी है. अमित शाह ये बात भलिभांति जानते हैं कि भाजपा से आदिवासियों की नाराजगी का असर लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता हैं. इसलिए वे अभी से आदिवासियों में पैठ बनाने और उन्हें भाजपा की तरफ मोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं.

मंच पर नहीं मिली मुंडा को जगह!

एक तरफ अमित शाह ने सबको एक साथ मिलकर मिशन 2019 में जुट जाने को कहा, तो वही रघुवर दास ने इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को नीचा दिखाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. मुंडा शाह के कार्यक्रमों में अलग-थलग दिखे. गरीब कल्याण मेला में तो अर्जुन मुंडा ने मंच भी शेयर नहीं किया. वे मंच के नीचे बने वीआईपी गैलरी में ही बैठे रहे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सरकार के अधिकारियों ने मुंडा को मंच पर आने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं गए. झारखंड की राजनीति में रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के बीच छत्तीस का आंकड़ा जगजाहिर है और दानों के बीच का खटपट खुलकर सामने आने लगा है. हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में भाजपा अर्जुन मुंडा की उपेक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि आदिवासी विधायकों के साथ ही आदिवासी समाज पर भी मुंडा की अच्छी पकड़ मानी जाती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी इस बात का अच्छी तरह से अहसास है और यही कारण भी है कि मोदी ने अर्जुन मंडा को दिल्ली बुलाकर झारखंड की राजनीति पर उनसे चर्चा की थी. मोदी के साथ उस मीटिंग ने झारखंड में मुंडा का कद बढ़ाने का काम किया था.

शाहख़र्ची को लेकर भाजपा पर बरसी कांग्रेस

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं झारखंड कांग्रस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अमित शाह के रांची दौरे को लेकर भाजपा पर शाहखर्ची का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राज्य के दो बड़े अस्पतालों में संसाधनों के अभाव में बच्चों की मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ अमित शाह के रांची आगमन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. यह उचित नहीं है. अमित शाह को जहां ठहरना था, उस जगह को करोड़ों रुपए खर्च कर के सजाया संवारा गया. पूरी राजधानी में होर्डिंग्स और पंडाल पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए. आरपीएन सिंह ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और मुख्यमंत्री रघुवर दास जीरो टॉलेरेंस की बाते कर रहे है. सरकार हर मोंचे पर विफल है, लेकिन अपनी सरकार की सफलता का ढोल पीट रही है. कांग्रेस सबूतों के साथ इस सरकार की कथित उपलब्धियों का पोल खोलेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी
पूरे हफ्ते ख़बरों का ख़ज़ाना
जुड़िए...
Editor's Take & दो-टूक
में देश के सबसे निर्भीक पत्रकार संतोष भारतीय से
Fourth Dimension में
छप क्या रहा चौथी दुनिया के नए अंक में
Crime Time में हर दिन अपराध की पड़ताल
हम ख़बरें बनाते ही नहीं दिखाते भी हैं

देश की स्थिति बिगड़ रही है

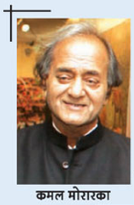

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

जो ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको बैंक रोज एसएमएस भेज रहा है. सबकुछ देखते हुए देश की हालात सकारात्मक नहीं है. छोटी-छोटी चीजें हो रही हैं, बिखरते हुए हो रही है. गांव में पुलिस का तंत्र तो वही है, जो इतने साल से है. अधिकारियों का तंत्र तो वही है. एक दिन में तो कुछ बदलता नहीं है. तो जो छोटा आदमी है, जिसकी पहुंच नहीं है, वो पिस रहा है, चाहे वो किसान, मजदूर बेरोजगार या फिर भूमिहीन हो. जरूरत है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दे प्राइम मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बना दे, जो ऐसी नीतियां निर्धारित करे, जो लोगों को समझ में भी आ जाए, सरल भी हो और लोगों को कम से कम आत्महत्या के रास्ते पर या बिल्कुल निराश होने की तरफ तो न ले जाए.

भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगले कई साल तक कृषि प्रधान ही रहेगा. एक नीति, जो पिछली सरकार ने शुरू की थी और ये सरकार भी आगे बढ़ाना चाहती है, यह है कि 80 करोड़ लोगों को ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाके में लाने की बात की जा रही है. मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है और इतनी जल्दी ये क्रियान्वित नहीं हो पाएगी. किसानों की जो हालत है, प्रधानमंत्री कहते हैं छह साल में किसानों की आमदनी वो दोगुनी कर देंगे. उनके कृषि मंत्री भी यही कहते हैं. किसानों की आमदनी दोगुनी करने के दो तरीके हैं, पहला, उनकी उत्पादकता दोगुनी हो जाए, जबकि ये हो नहीं सकती. जितनी जमीन है, उसमें दस बीस प्रतिशत इजाफा हो सकता है, दोगुनी तो नहीं हो सकती. दूसरा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. उसमें आप इजाफा करें. पिछली सरकार बढ़ाती थी 70, 80 रुपए या 100 रुपए. ये बढ़ाते हैं 20, 30 या 40 रुपए, तो उससे भी कुछ नहीं होना है. आज हमलोग देख रहे हैं, खबरें अखबार में आती हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली और राज्य सरकारों ने ऋण माफ कर दिया. लेकिन जब तक हमलोग मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है. ये तत्कालीन बातें हैं और इसमें भी विडंबना है.

कुछ दिनों पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में एक किसान को एक पैसे का ऋण माफ करने का सर्टिफिकेट दिया गया. यह मखौल है. किसान त्रस्त हैं, गरीब हैं, बहुत दबाव में हैं, उनके साथ भद्दा मजाक करना देश के हित में नहीं है. किसान की समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसान की समस्याओं को समझने की जरूरत है. उसके पास जो अनाज होता है, उसके भंडारण के लिए जगह चाहिए. यातायात चाहिए, ताकि अनाज मंडी तक पहुंच सके, मंडी में उसको सही दाम मिलना चाहिए. सरकार के पास कोई इस तरह का अप्रेटस नहीं है. कोई इस तरह का यंत्र नहीं है, जिससे ये बातें सुनिश्चित कर सके. और कहीं भी चले जाइए महाराष्ट्र में राजू शेट्टी हैं, यूपी में दूसरी किसान संस्थाएं हैं, सब त्रस्त हैं. उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती हैं. औद्योगिक घराने के पास तो फिक्की, एसोचैम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो दबाव बना लेते हैं. लेकिन अगर देश का दीर्घकालीन भविष्य ठीक रखना है, तो ग्रामीण इलाके ठीक होने चाहिए.

युवा वर्ग को नौकरी मिलनी चाहिए. जमीन सीमित है. एक परिवार में जैसे ही पीढ़ी बढ़ती है जमीन बंटती जाती है, तो जरूरी यह है कि कृषि से जुड़े उद्योग, लघु उद्योग बढ़ें, ताकि लोग नौकरी पा सकें. प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि मैं चाहता हूं कि नौकरी मांगने की जगह आप लोगों को नौकरी दें. जॉब सीकर की जगह लोग जॉब गीवर बनें. यह जुमला ही हो सकता है. जो आदमी खुद नौकरी ढूंढ रहा है, आज सोच रहा है कि वो कोई इकाई खोलकर नौकरी देगा. बहुत अच्छी सोच है, करिए. उसके लिए तो कुछ है ही नहीं. एक मुद्रा बैंक बनी थी. एक-दो साल पहले बजट में अनाउंस किया था, पर वो क्रियान्वित नहीं हुई, क्योंकि रिजर्व बैंक ने नहीं करने दिया. यह बहुत जटिल देश है. वो सॉल्यूशन यहां काम नहीं करेंगे, जो यूरोप या अमेरिका में करते हैं. अमेरिका की कुल आबादी कितनी है, यहां से एक चौथाई भी नहीं है. पूरे यूरोप की आबादी कितनी है, भारत जितनी भी नहीं है. एक काम आपको बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा. एक ही देश है दुनिया में, जिससे हमलोग तुलना कर सकते हैं, वो है चीन. उससे तुलना इसलिए रुक जाती है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है. लोकतंत्र नहीं है. वो आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है. हमलोगों के यहां लोकतंत्र है, हमारी सीमाएं हैं, अच्छी बात है. यहां प्रेस की भी आजादी है. न्यायपालिका भी है. यह सब ठीक है लेकिन जो भी सरकार पावर में आती है, उसे यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में आपको लोगों ने पांच साल दिए हैं. पांच साल में आप वो हर चीज नहीं बदल सकते हैं, जो 70 साल से होती आयी हैं.

> **युवा वर्ग को नौकरी मिलनी चाहिए. जमीन सीमित है. एक परिवार में जैसे ही पीढ़ी बढ़ती है जमीन बंटती जाती है, तो जरूरी यह है कि कृषि से जुड़े उद्योग, लघु उद्योग बढ़ें, ताकि लोग नौकरी पा सकें. प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि मैं चाहता हूं कि नौकरी मांगने की जगह आप लोगों को नौकरी दें. जॉब सीकर की जगह लोग जॉब गीवर बनें. यह जुमला ही हो सकता है. जो आदमी खुद नौकरी ढूंढ रहा है, आज सोच रहा है कि वो कोई इकाई खोलकर नौकरी देगा. बहुत अच्छी सोच है, करिए. उसके लिए तो कुछ है ही नहीं. एक मुद्रा बैंक बनी थी.**

दुर्भाग्यवश इस सरकार का रवैया यह है कि 70 साल तक गड़बड़ियां हुई हैं, ये पांच साल में ठीक करना चाहते हैं. पहली बात तो 70 साल से गड़बड़ियां नहीं हुई हैं. ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है. लेकिन अटल बिहारी सरकार छह साल थी, आप उनको कांग्रेस के रंग में नहीं रंग सकते. जो संविधान में, ढांचे में फिट होगा, वही तो आप लागू कर सकते हैं. आज सामाजिक सहिष्णुता खराब हो रही है. हिन्दू मुसलमान का झगड़ा, गायों पर झगड़ा, जो स्थिति बन रही है, वो बहुत ठीक नहीं है. सरकार को औद्योगीकरण चाहिए, तो ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको आधुनिक देश बनाना है और लोगों को नौकरियां देनी है, तो मैं नहीं कहता कि खाली कृषि से ऐसा होगा. उद्योग खोलिए, उद्योग खुल रहे हैं, हमलोग अगर आज मंगलयान बना सकते हैं या सेटेलाइट बना सकते हैं या मिसाइल बना सकते हैं, तो ये पांच साल में हो गया क्या? ये हो रहा है, तो वो मैं नहीं कहता. लेकिन जब तक आप तत्कालीन समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, लोगों में रोष बढ़ता जाएगा. इलेक्शन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. देश तो है, हर पांच साल में देश नए सिरे से तो शुरू नहीं हो सकता. देश जैसे चलता है, आगे भी चलेगा.

जो पॉलिसी पहले से चल रही है, उसको आप और कितना चेंज कर सकते हैं. ये तो खुद इस सरकार ने देख लिया. जब पावर में आए, तो उन्होंने कहा मनरेगा हटा देंगे. हम आधार हटा देंगे और वही पॉलिसी उनकी खास पॉलिसी हो गई क्योंकि वो नीतियां तर्कसंगत थीं. देश के फायदे के लिए थीं. देश के हित के लिए थीं. ठीक है, अच्छी पॉलिसी है, तो करिए, लेकिन न्यायपालिका को समझ के करिए. आज आधार कार्ड है. पहले आपने कहा था, जिनको सब्सिडी चाहिए, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए ताकि सब्सिडी सीधे उनके खाते में चली जाए और बिचौलिए उसमें कोई फायदा न उठाएं. बहुत अच्छी बात है. मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने कहा कि मुझे कभी कोई सब्सिडी नहीं चाहिए. मैं आधार कार्ड नहीं लूंगा. मुश्किल हो गई. मेरा बैंक वाला कहता है कि आप आधार कार्ड दीजिए, नहीं तो मैं आपका बैंक अकाउंट बंद कर दूंगा. दूसरा आदमी बोलता है, कैसे भाई, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं. इनकम टैक्स वाला कहता है कि आधार कार्ड नहीं देंगे तो मैं आपका रिटर्न नहीं लूंगा. जब पैन कार्ड है, जो इनकम टैक्स का खुद का कार्ड है, तो फिर ऐसा क्यों? कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है, जरूरत है आदमी संतुलित ढंग से अपना दिमाग लगाए और ऐसी पॉलिसी बनाए जो आम जनता को भी समझ में आती हो. सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, उसका तर्क भी समझ में आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी का जजमेंट दिया, जिसे समझना जटिल है. लेकिन उसका मतलब ये है कि लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. ये तो कोई भी समझता है. गांव का आदमी भी समझता है. शहर का भी समझता है. सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक अमलीजामा पहना दिया कि अब कानून भी ये होगा. अब आधार का जजमेंट उसी कसौटी पर होना है. तो कम से कम जब तक आधार का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट न दे, तब तक परेशान करना बंद करिए.

जो ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको बैंक रोज एसएमएस भेज रहा है. सबकुछ देखते हुए देश की हालात सकारात्मक नहीं है. छोटी-छोटी चीजें हो रही हैं, बिखरते हुए हो रही हैं. गांव में पुलिस का तंत्र तो वही है, जो इतने साल से है. अधिकारियों का तंत्र तो वही है. एक दिन में तो कुछ बदलता नहीं है. तो जो छोटा आदमी है, जिसकी पहुंच नहीं है, वो पिस रहा है, चाहे वो किसान, मजदूर बेरोजगार या फिर भूमिहीन हो. जरूरत है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दे प्राइम मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बना दे, जो ऐसी नीतियां निर्धारित करे, जो लोगों को समझ में भी आ जाए, सरल भी हो और लोगों को कम से कम आत्महत्या के रास्ते पर या बिल्कुल निराश होने की तरफ तो न ले जाए. आज जॉब है नहीं, सबको दिख रहा है. बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियां इंफोसिस, कई बैंक हजारों लोगों को नौकरियों से हटा रहे हैं. नई नौकरियां क्रिएट करना अलग बात है. ये डिसएम्प्लायमेंट है, अनइम्प्लाइमेंट नहीं है. लगी हुई नौकरी छूट रही है. इससे देश की स्थिति बिगड़ेगी और अगले पांच साल में मैं समझता हूं कि अगर तत्कालीन कदम नहीं उठाए गए, तो हमलोग बहुत मुश्किल में आ जाएंगे. सोचता हूं कि ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी और वे कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सफ़ेद हाथी साबित होगी बुलेट ट्रेन

अनिल धारकर

क्या बुलेट ट्रेन एक सफेद हाथ साबित होगी या इसके सहारे भारत उन्नत प्रौद्योगिकी के नए युग में दाखिल होगा? यदि आप तार्किक रूप से इस सवाल पर विचार करेंगे, तो इसका केवल एक ही संभावित जवाब आपको मिलेगा.

जापान ने टोक्यो और ओसाका के बीच अपनी उच्च-गति की शिंकानसेन लाइन की शुरुआत 1964 में की थी. उस समय उसकी अधिकतम गति सीमा 210 किमी/घंटा थी, अब यह 350 किमी/घंटा है. पहली बुलेट ट्रेन के संचालन से लेकर अब तक 10 अन्य देशों ने अपना हाई-स्पीड नेटवर्क विकसित कर लिया है. इन देशों में चीन का स्थान सबसे ऊपर है. चीन में 89 हाई स्पीड पटरियां हैं, जिनकी लम्बाई 26,783 किमी है, जबकि जापान के पास 17 हाई स्पीड पटरियां हैं, जो 3416 किमी है. हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक विकसित करने वाले अन्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और तुर्की. गौरतलब है कि इन देशों में से कोई भी शिंकानसेन प्रणाली का उपयोग नहीं करता. अब सवाल यह उठता है कि क्या जापानी तकनीक वास्तव में सबसे अच्छी है? ऐसा लगता है कि यह फैसला लेने से पहले शिंकानसेन प्रणाली का अन्य प्रणालियों की तकनीकी के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है. तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आंख मूंदकर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना शुरू करने जा रहे हैं.

बहस के लिए मान लेते हैं कि शिंकानसन प्रणाली का मुकाबला किसी भी अन्य उपलब्ध तकनीक के साथ किया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि भारतीय इंजीनियरिंग को इसके सहारे नई बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? सरकारी हलकों से यह दावा किया जा रहा है. यहां यह जान लेना दिलचस्प होगा कि कुछ साल पहले, जापान ने चीन को उच्च गति का रेल नेटवर्क बनाने की पेशकश की थी. कई दौर की बातचीत के बाद बातें इस पर आकर रुक गयी कि जापान तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं था. आम तौर पर इस तरह की वृहत् परियोजना में एक खास अवधि के बाद तकनीक का हस्तांतरण होता है.

परियोजना पर सहमति के दूसरे दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का एक महत्वपूर्ण बयान आया. उनका कहना था कि परियोजना के लिए कच्चे माल और मजदूर कहां से आएंगे? ज़ाहिर है भारत से! परियोजना में इस्तेमाल होने वाली हरेक चीज (सेवा से लेकर सामग्री तक) में राजस्व सृजन की अपार क्षमता होगी. अन्य राजनेताओं की तरफ से भी फडणवीस के अंदाज़ का ही बयान आया. गौर करने वाली बात यह है कि किसी ने भी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात नहीं की. सरकार या सरकारी स्रोतों की तरफ से भी इस सिलसिले में अबतक कोई खुलासा नहीं किया गया है. क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जापानियों ने कहा है कि वे सुरक्षा की गारंटी तब देंगे, जब वे पूरी प्रणाली का निर्माण करेंगे? संभवतः यह शर्त बुलेट ट्रेन के उन परियोजनाओं पर भी लागू होगी जिसके तहत भविष्य में प्रमुख महानगरों को जोड़ने का प्रस्ताव है. इस पृष्ठभूमि में हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत कैसे होगी?

अगर परियोजना का कोई तकनीकी मूल्यांकन नहीं हुआ और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कोई समझौता नहीं हुआ, तो क्या कम से कम कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी? ज़ाहिरी तौर पर हां! लेकिन उसकी तफसील कहां है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नौकरशाही ने उस रिपोर्ट को साझा करने से इंकार कर दिया. यहां तक कि आरटीआई आवेदनों को भी खारिज कर दिया गया. बहरहाल, हमारे पास ताइवान का उदाहरण मौजूद है. वहां जापानी शिंकानसन प्रणाली स्थापित की गई थी. ताइवान में 1990 के दशक के शुरू में बीओटी मॉडल (बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल) के आधार पर एक उच्च गति वाली ट्रेन सिस्टम स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों का एक संघ बनाया गया था. वर्ष 2007 में 14.3 अरब डॉलर के निवेश के साथ यह सिस्टम चालू हुआ. वर्ष 2014 आते-आते इस रेल के संचालक दिवालिया हो गए थे. उन्हें कुल 1.5 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था. चूंकि यह नेटवर्क जनता के हित के लिए था, इसलिए ताइवानी सरकार ने कंपनियों के इस संघ को इस घाटे से उबारने के लिए सरकारी खजाने से 1 अरब डॉलर की सहायता दी और संचालकों के शेयर को 60 फीसदी तक कम कर दिया. भारत में बीओटी मॉडल को बहस में ही नहीं लाया गया. ज़ाहिर है इसका कारण यह था कि कोई भी निजी कंपनी इस पर बोली लगाने के लिए तैयार ही नहीं होती. दरअसल कैपिटल-इंटेंसिव मेट्रो परियोजना (बीओटी) की विफलता हर किसी के सामने है.

दिल्ली में भाजपा सरकार ने यूपीए सरकार की कई योजनाओं को अपनाया (इस दावे के साथ जैसे वो उनके विचार की उपज हों), मिसाल के तौर पर जीएसटी. इसलिए यहां यह जानना जरूरी है कि यूपीए सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना को अव्यवहार्य करार देते हुए खारिज कर दिया था. वास्तव में, तत्कालीन वित्त सचिव राकेश मोहन ने यहां तक कह दिया था कि यदि जापान ऋण के बजाय आर्थिक अनुदान भी देता है, तो भी वो इस परियोजना को स्वीकृति नहीं देंगे. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक मुंबई-अहमदाबाद सेवा के किराए को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रति दिन करीब एक लाख यात्रियों को सफर करना पड़ेगा. दोनों शहरों के बीच फ़िलहाल केवल 18 हजार लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं. इसका मतलब यह है कि या तो किरायों को हवाई जहाज़ के किराए से अधिक करना पड़ेगा या फिर इसे एक स्थाई सब्सिडी देनी पड़ेगी.

जापान के लगभग ब्याज-मुक्त ऋण को कई तरह से पेश किया गया. जापानी 1,10,000 करोड़ रुपए लागत की कुल परियोजना का 88 हजार करोड़ रुपये का ऋण 50 साल की अवधि के लिए दे रहे हैं, शेष राशि का भार केंद्र सरकार एवं गुजरात और महाराष्ट्र सरकार वहन करेंगे. यदि जापान द्वारा भारत को की गई 0.10 फीसदी ब्याज दर की पेशकश बहुत अनुकूल है, तो कुछ अन्य बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए. 10 साल के जापानी सरकारी बांड पर ब्याज दर 0.04 फीसदी है और अन्य ब्याज दरें नकारात्मक भी हो सकती हैं. ये तथ्य बहुप्रचारित जापानी दरियादिली की पोल खोल देते हैं.

भारत और जापान के बीच ब्याज दरों में अंतर (हमारे 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर 6.5 फीसदी है), का एक और गंभीर एवं दीर्घकालिक प्रभाव है. एक वित्तीय विश्लेषक के मुताबिक, अगर हम औसत भारतीय मुद्रास्फीति को तीन प्रतिशत और जापानी मुद्रास्फीति को शून्य पर मानते हैं तो जापानी मुद्रा येन के मुकाबले में रुपए की कीमत हर साल तीन प्रतिशत कम होगी. इस लिहाज़ से देखा जाए तो आने वाले 50 वर्षों में ऋण की मूल राशि 88 हजार करोड़ रुपये दोगुनी से अधिक हो जाएगी. कुल मिला कर कहा जाए तो बुलेट ट्रेन हमारी भावी पीढ़ियों के सिर पर तनी बन्दूक के बुलेट की तरह हो जाएगी.

एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने के अलावा, इस परियोजना का कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है? रेलवे मामलों के जानकार और नीति आयोग के सदस्य विवेक देवरॉय (जो किसी सरकारी-विरोधी खेमे से संबद्ध नहीं हैं) के मुताबिक भारत में रेल के 95 प्रतिशत लोग राजधानी या शताब्दी ट्रेनों से सफ़र नहीं करते हैं. केवल पांच प्रतिशत भारतीय मौजूदा सुपर फास्ट ट्रेनों से सफ़र करते हैं, क्योंकि अन्य लोगों की जेब अतिरिक्त किराया वर्दाश्त नहीं कर सकतीं. संक्षेप में कहें तो बुलेट ट्रेनें देश की आबादी के केवल पांच प्रतिशत लोगों की यात्रा को तेज करने जा रही हैं. ये वो लोग हैं जिनके पास पहले से ही हवाई यात्रा का विकल्प मौजूद है.

आइए इस परियोजना को एक वृहत् परिदृश्य में देखने की कोशिश करते हैं. बुलेट ट्रेन परियोजना पर 1,10,000 करोड़ रुपये की लागत आने वाली है. पिछले साल के रेल बजट में संपूर्ण भारतीय रेलवे व्यवस्था के लिए कुल 1,21,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था. बुलेट ट्रेन की सेवा का लाभ केवल दो शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की एक छोटी संख्या ही ले सकेगी. वहीं भारतीय रेलवे प्रणाली में रोजाना 13 हजार से अधिक ट्रेनें चलती हैं. ये ट्रेनें प्रति वर्ष देश में 8 अरब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं और 100 करोड़ टन माल की ढुलाई करती हैं. यदि बुलेट ट्रेन और भारतीय रेल पर होने वाली लागत पर नज़र डालें तो दोनों आंकड़ों में बहुत अंतर नज़र नहीं आता.

तो अब आप ही फैसला कर लीजिए कि भारत को वास्तव में क्या चाहिए? चंद गिने-चुने लोगों के लिए धमाकेदार बुलेट ट्रेन या एक बड़ी, बेहतर और सुरक्षित प्रणाली जिसका उपयोग सभी कर सकें? क्या वास्तव में आप इस सवाल के जवाब के इंतज़ार में हैं? ■

(साभार:इंडियन एक्सप्रेस)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यशवंत सिन्हा की चिंताएं जायज़ हैं

ये हमारे दौर के बाप-बेटे की दूसरी कहानी है. यशवंत सिन्हा ने अपनी सीट अपने बेटे जयंत सिन्हा को ये मान कर दी कि जयंत सिन्हा उनके रहते-रहते राजनीति में स्थापित हो जाएं और वो हजारीबाग से लोकसभा में आ जाएं. यशवंत सिन्हा लगातार हजारीबाग जाते रहे, वहां के लोगों से उनका संपर्क रहा. झारखंड की राजनीति में उन्हें बहुत बड़ा नेता माना जाता है. हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर के उससे बड़े नेता हैं. यशवंत सिन्हा के महत्व के परिणामस्वरूप उनके पुत्र जयंत सिन्हा लोकसभा में आए और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई. पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें नागरिक उड्डयन का राज्यमंत्री बनाया गया.

यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर जी के सबसे विश्वासपात्र लोगों में से एक रहे. अगर वो और कमल मोरारका नहीं होते तो शायद जनता दल का निर्माण नहीं हो पाता. इन्हीं दोनों की दूरदर्शिता की वजह से जनता दल बना और उसमें चंद्रशेखर जी की जनता पार्टी का विलय हुआ. यशवंत सिन्हा को चंद्रशेखर जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी. यशवंत सिन्हा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली. यशवंत सिन्हा के जमाने में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट की खराब होती स्थिति से निपटने के लिए हमने अपना सोना गिरवी रखकर देश की साख बचाई. इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया. लेकिन यशवंत सिन्हा की सलाह पर चंद्रशेखर जी ने यह कठोर फैसला लिया और उस फैसले से देश की साख बचाई और वित्तीय स्थिति को संभालने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया. हालांकि यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, तब देश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा था. उसी समय इराक युद्ध शुरू हो गया था और हम उस युद्ध के परोक्ष परिणामों को बुरी तरह झेल रहे थे.

यशवंत सिन्हा हमेशा से राजनीति के ऐसे विद्यार्थी रहे हैं, जो देश के सवालों के ऊपर कभी समझौता नहीं करते. वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो चंद्रशेखर जी से बात कर शामिल हुए. यशवंत सिन्हा को अटल विहारी वाजपेयी ने भी अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी. यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अटल जी के सबसे खास विश्वासपात्रों में शामिल हो गए. हालांकि उनकी संघ की या भारतीय जनता पार्टी की कोई पृष्ठभूमि नहीं रही. अटल जी ने उनके काम को परखा, उनके काम को सराहा और उनकी मेहनत का पुरस्कार उन्हें अपना सबसे नजदीकी व्यक्तियों में से एक बनाकर दिया. आडवाणी जी भी यशवंत सिन्हा की सोच और मेहनत के तरीकों से प्रभावित होकर उनके प्रशंसकों में शामिल हो गए थे.

यशवंत सिन्हा इन दिनों देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही परेशान हैं. उन्होंने सार्वजनिक और व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार भारत सरकार की मौजूदा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सुझाव दिए. लेकिन अब ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा सरकार की गिरती हुई आर्थिक स्थिति और उससे होने वाले दुष्परिणामों को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें एक अखबार में लेख लिखकर कई सारी चीजें रेखांकित करनी पड़ी. शायद इसके पीछे कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों इनमें से किसी का संवाद प्रधानमंत्री के साथ नहीं है. इसलिए उनका कोई सुझाव प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचता है और न इस देश के हालत की जानकारी पहुंचती है. शायद यशवंत सिन्हा ने इसी स्थिति से परेशान होकर अखबार में लेख लिखा. उनकी लेख के वो बिन्दु, जिसे उन्होंने रेखांकित किया है, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर खराब फैसले, जीडीपी की ग्रोथ रेट का चिंताजनक रूप से गिरना, वित्त मंत्री द्वारा कोई भी सही फैसला न लेना और उन फैसलों को कठोर बनाना, जिन्होंने देश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा है. इसे देश के लोगों ने बहुत पसंद किया. उन्होंने तंज भी कसा कि अरुण जेटली सुपरमैन जैसे हो गए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने चार-चार विभाग दिए, जबकि उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय का अकेला काम चौबीस घंटे से ज्यादा का काम है. अगर व्यक्ति सोए न, तो भी इतना बड़ा देश, इतनी चुनौतियां, विकास की चुनौतियां, नौकरियों की चुनौतियां इन सबके रास्ते निकालने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर जिम्मा है वो हर मंत्रालय का आंशिक मंत्री बना हुआ है और अपनी चिंताएं प्रधानमंत्री के सामने सही ढंग से नहीं रख रहा है. शायद उनके लिखने का यह तरीका अरुण जेटली से सही उत्तर प्राप्त करने का तरीका भी हो सकता है. क्या यशवंत सिन्हा की चिंताएं गलत हैं?

यशवंत सिन्हा की अर्थव्यवस्था को लेकर और मोदी सरकार को लेकर कोई चिंता गलत नहीं है, क्योंकि उन सारे सवालों को हम अपने आस-पास घटित होते हुए देख रहे हैं. अरुण जेटली कभी भी वित्तीय मामलों के जानकार नहीं रहे. वो अच्छे वकील रहे लेकिन वो वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ कभी नहीं रहे. अरुण जेटली के वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ न होने की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल है. शायद इसीलिए वित्त मंत्रालय में एक पूर्णकालिक वित्त मंत्री रहे, इसकी आवश्यकता देश को महसूस हो रही है, राजनीतिक दलों को भी महसूस हो रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी को भी महसूस हो रही है. मेरी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मुलाकात होती है, चाहे वो संघ से जुड़े हों या पार्टी से जुड़े हों या लोकसभा व राज्यसभा के सांसद हों, सभी का कहना है कि अरुण जेटली बहुत अच्छे आदमी हैं. प्रधानमंत्री के सबसे विश्वासपात्र लोगों में हैं. तो अच्छा हो, वो सभी मंत्रालय छोड़कर बिना मंत्रालय के मंत्री रहें और सारे मंत्रालयों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को तर्कसंगत ढंग से समझाएं. शायद ये उनका सबसे बड़ा रोल हो सकता है. अरुण जेटली के रक्षा मंत्री रहते देश को तब नुकसान होता, जब देश का किसी के साथ युद्ध होता. कंपनी मामलों के मंत्री होने से नुकसान तब होता जब अरुण जेटली कंपनियों को इग्नोर करते. जेटली जी का सबसे प्रिय विषय भारत का कंपनी जगत है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जिसके वो बहुत डार्लिंग या ब्लू-आईड ब्वॉय रहे हैं. पर वित्त मंत्रालय को तो अरुण जेटली के अज्ञान से और देश को प्रधानमंत्री के इस फैसले से बहुत नुकसान हुआ है. शायद यही यशवंत सिन्हा की चिंता है.

यशवंत सिन्हा की चिंताओं का जवाब सरकार के मंत्रियों ने वैसे ही देना शुरू किया, जैसे वो राहुल गांधी का जवाब उनकी विदेशों में दिए हुए भाषणों के ऊपर देते रहे. 19 मंत्री, 24 घंटे राहुल गांधी के ऊपर आक्रामक रहे. यशवंत सिन्हा के ऊपर पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह सबसे पहले आक्रामक हुए. जब सरकार ने देखा या शायद प्रधानमंत्री ने देखा कि उनका असर देश के ऊपर नहीं जा रहा है, तो उन्होंने यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को उनका उत्तर देने के लिए खड़ा किया और उनका उत्तर क्या था कि अब पुराने तरीकों से अर्थनीति को नहीं मापा जा सकता. अब नए तरीकों से अर्थनीति को मापना चाहिए. शायद जयंत सिन्हा या सरकार ही इस भाषा को समझ रही हो और तो कोई इस भाषा को समझा नहीं. लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि सत्ता इतनी हरजाई होती है कि जिसे पाने के लिए, जिसमें बने रहने के लिए व्यक्ति अपने रिश्ते भी भूल जाता है. चाहे वो बाप-बेटे का रिश्ता ही क्यों नहीं हो.

> यशवंत सिन्हा इन दिनों देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही परेशान हैं. उन्होंने सार्वजनिक और व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार भारत सरकार की मौजूदा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सुझाव दिए. लेकिन अब ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा सरकार की गिरती हुई आर्थिक स्थिति और उससे होने वाले दुष्परिणामों को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें एक अखबार में लेख लिखकर कई सारी चीजें रेखांकित करनी पड़ीं. शायद इसके पीछे कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों इनमें से किसी का संवाद प्रधानमंत्री के साथ नहीं है. इसलिए उनका कोई सुझाव प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचता है और न इस देश के हालत की जानकारी पहुंचती है.

जयंत सिन्हा इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं. उन्हें उत्तर देने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने उत्तर इसलिए दिया क्योंकि शायद उनसे कहा गया और जिसने ये फैसला किया उसने बेवकूफी का फैसला किया. यशवंत सिन्हा के सवालों का उत्तर वित्त मंत्री अरुण जेटली को देना चाहिए था और अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली नहीं देते तो वित्त राज्य मंत्री देते. लेकिन जिन यशवंत सिन्हा को कश्मीर में की गई उनकी कोशिशों के जवाब में उनकी तारीफ करने की जगह प्रधानमंत्री मिलने का मौका भी न दें, ऐसे व्यक्ति के सवालों का जवाब शायद अरुण जेटली के द्वारा दिलवाना सरकार को लगा कि वो फंसने की बात हो सकती है. इसीलिए यशवंत सिन्हा का उत्तर जयंत सिन्हा से दिलवाया गया.

यशवंत सिन्हा के प्रशंसकों का दायरा बढ़ा है. पार्टी में उनके पक्ष में छोटी-मोटी लहर फैल गयी. शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे पहले मुंह खोलकर उन्हें एक अच्छे और बड़े नेता के रूप में याद किया और उनका समर्थन किया. मेरी जानकारी के हिसाब से श्री मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी भी यशवंत सिन्हा के आरोपों से सहमत हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है कि संसद के अगले सत्र में जब सारे सांसद दिल्ली में होंगे तब यशवंत सिन्हा द्वारा उठाए गए सवालों के ऊपर गंभीर बातचीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से खुद कोई नई बात निकलकर सामने आएगी.

हालांकि सरकार करेगी नहीं, लेकिन हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सवाल चाहे अखबारों द्वारा उठाए गए हों, टेलीविजन चैनलों द्वारा उठाए गए हों, राजनीति व्यक्तियों द्वारा उठाए गए हों या उनकी पार्टी के सबसे जिम्मेदार लोगों द्वारा उठाए गए हों, जिनमें यशवंत सिन्हा एक हैं, उनके जवाब देने में हर्ज क्या है? अगर आप अपना नजरिया रखते हैं तो इसे ही तो स्वस्थ राजनीति कहते हैं. स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ राजनीति आवश्यक है. पर अगर आप उसे अनदेखा करें, उसे स्तरहीनता तक ले जाएं, ये बताएं कि आपके लिए किसी भी सवाल का उत्तर देना कोई आवश्यक नहीं है तो ये फिर लोकतंत्र तो नहीं होता. इसे आप तानाशाही जैसी स्थिति विश्लेषित कर सकते हैं. पर सवाल ये है कि क्या ये देश अभी तानाशाही स्वीकार करने के पक्ष में है. सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी बड़ी संख्या में भड़ैत बैठे हैं और चापलूसों और भांड़ों से देश नहीं चलता. देश चलता है जिम्मेदारी से और यहां हम फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वो वित्त मंत्रालय का काम अपने हाथ में लें. देश के ऐसे सारे अर्थ विशेषज्ञों से, जो न वामपंथी हों, न संघ से जुड़े हों पर जो देश से जुड़े हों उन्हें बैठाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में विचार-विमर्श करें. हमें पूरा विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री इस काम को अपने हाथ में लेते हैं तो इसका हल भी निकलेगा और हम मंदी के दौर में जिस तेजी से फिसल रहे हैं हमारी वो फिसलन कम होगी या रुकेगी. क्या प्रधानमंत्री जी सचमुच देश के प्रति अपने उस कर्तव्य को निभाएंगे, जिसमें वित्तीय स्थिति की गिरावट का तोड़ निकालने में वो अपना वक्त या अपने समय का योगदान कर सकें, समय की मांग है, इसलिए प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह है. ■

editor@chauthiduniya.com

गोरखपुर, फ़र्रुख़ाबाद के बाद अब आया लखीमपुर खीरी का नंबर

चार महीने में 19 बच्चों की मौत

इलाज देने के बजाय मौत की ख़बर दबाने में सरकार अधिक सक्रिय

अजय गुप्ता

उत्तर प्रदेश की नाकारा स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है. गोरखपुर और फर्रुखाबाद के बाद लखीमपुर खीरी जिले का नंबर आया है. खीरी के मुख्य जिला अस्पताल में ही पिछले चार महीने में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. लेकिन शासन-प्रशासन पर इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सरकार इलाज मुहैया कराने के बजाय मौत की खबरों को दबाने में लगी रहती है. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपने गृह जनपद गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी. फिर भी सरकार को होश नहीं आ रहा. स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार सबकुछ ठीक करने का दावा कर रही है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है. गोरखपुर जैसी घटनाएं शासन-प्रशासन के दावों की पोल तो खोलती हैं, लेकिन ऐसे हादसों के बाद शासन की नींद नहीं खोल पातीं. शासन की इतनी मोटी खाल है कि कुछ असर नहीं पड़ता. गोरखपुर और फर्रुखाबाद जैसी घटनाओं से सीख लेने के बजाय शासन-प्रशासन बेतुकी बयानबाजी करता रहता है.

लखीमपुर खीरी जिला भी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की जर्जर हालत का शिकार है. दुखद तथ्य यह है कि नेपाल सीमा पर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े इस जिले से सत्ताधारी भाजपा के दो सांसद और सात विधायक आते हैं. जनपद का मुख्य चिकित्सालय इतना बदहाल है कि लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इसका उदाहरण दिया जाने लगा है. जापानी इन्सेफ्लाइटिस और एक्यूट इन्सेक्लोपैथी सिन्ड्रोम (एईएस) ने पूरे जनपद को अपने घेरे में ले रखा है. इस भयानक बीमारी से होने वाली मौतों से पूरे जिले में सन्नाटा पसरा है. इससे निपटने के लिए चाहे जो भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन वह बच्चों की जान बचाने के काम नहीं आ रहे हैं. अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्डों में बच्चों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है. जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह है कि मरीजों की संख्या की तुलना में डॉक्टरों की संख्या नगण्य है. एईएस वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी है. स्टाफ के नाम पर तीन ऑपरेटर और एक टेक्नीशियन है. वह भी ठेके पर. कहने को यहां दो डॉक्टर्स की नियुक्ति है, लेकिन इन दो डॉक्टरों के जिम्मे ओपीडी, चिल्ड्रेन वार्ड और एईएस वार्ड है. बच्चों की मौत के आकड़ों को देखें, तो साफ पता चलता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य महकमा कितना हृदयहीन है. खीरी जनपद के चिकित्सालय के आंकड़ों पर यदि गौर करें, तो अकेले जिला अस्पताल में गत चार महीनों में केवल एईएस वार्ड में मरने वाले बच्चों की संख्या 19 के पार चली गई है. जनपद में बुखार का कहर इस कदर हावी है कि यह बच्चों को सीधे मौत के मुंह में ढकेल रहा है और स्वास्थ्य महकमा इतना लापरवाह है कि उपचार के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है. जिला अस्पताल खुद बीमारी की हालत में है, यह बात जिलाधिकारी के निरीक्षण में आधिकारिक तौर पर जाहिर हो चुकी है. बच्चों की मौत की बढ़ती हुई संख्या से जब पूरे जनपद में हाहाकार मचा, तब जिलाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और सांसद की नींद खुली. वे बदहाल अस्पताल गए, लोगों से बातचीत की, निरीक्षण किया, जरूरी निर्देश दिए और छुट्टी. उनकी जिम्मेदारी पूरी. बच्चों का मरना जारी रहा. अस्पताल की बदहाली पूर्ववत जारी है. जिले के गैर जिम्मेदार डॉक्टर बच्चों को प्राथमिक उपचार की औपचारिकता पूरी कर सीधे लखनऊ रेफर कर देने का पुनीत कर्तव्य निभा रहे हैं. हृदयहीनता की हद यह है कि पिछले दिनों बाजूडिहा के रहने वाले पप्पू के एईएस पीड़ित छह वर्षीय पुत्र अभिषेक की जिला अस्पताल में मौत हो जाने पर शव ले जाने के लिए शव-वाहन नहीं दिया गया. पिता को अपने बच्चे का शव मोटरसाइकिल पर उठा कर ले जाना पड़ा.

डीएम भड़के, पर पत्ते तक नहीं खड़के

बुखार और एईएस से हो रही बच्चों की मौतों पर जब जनपद में जनाक्रोश बढ़ा तब डीएम आकाश दीप को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने की सुध आई. अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और बदइंतजामियों को देख कर अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर डीएम खूब भड़के, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा. पीड़ित लोग कहते हैं कि जबतक अस्पताल के अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, डीएम के निरीक्षण से कुछ नहीं होने जाने वाला. जिला अस्पताल की बदइंतजामियों पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कहते हैं कि मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाने के कारण अफरातफरी जरूर हुई. यहां तक कि एक बेड पर कई-कई बच्चों को लिटाना पड़ा. लेकिन अब मरीजों की संख्या कम हुई है. उन्होंने माना कि दवाओं की कमी है, लेकिन लोकल स्तर पर दवाएं खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है.

चिंतित कर रहा बच्चों की मौत का आंकड़ा

लखीमपुर खीरी जिले में पिछले पांच वर्षों में एईएस के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है. शासन की लापरवाही के कारण यह बीमारी बेकाबू होती चली गई. बच्चों का मरना जारी है. स्वास्थ्य महकमा पंगु बना हुआ है. जिले के लोगों की चिंता बढ़ती ही जा रही है. रोगियों की संख्या का ग्राफ देखें, तो आपको आश्चर्य होगा. वर्ष 2012 में एईएस का मात्र एक मरीज भर्ती हुआ था. 2013 में रोगियों की संख्या आठ हो गई. वर्ष 2014 में यह संख्या पांच रही, लेकिन अचानक वर्ष 2015 में रोगियों की संख्या 57 पर पहुंच गई. 2016 में रोगियों की संख्या 33 पर आई, लेकिन इस साल (2017) अगस्त महीने तक मरीजों की संख्या सौ पार कर चुकी है. पिछले महज चार महीनों में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. खीरी के जिला चिकित्सालय के पीआईसीयू में बच्चों की हो रही मौतों के आंकड़े यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अराजक स्थिति का ढिंढोरा पीट रहे हैं. ■

नाकारा स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश अव्वल

स्वास्थ्य सेवाओं को जकड़ रहे पूंजी प्रतिष्ठान

सूफी यायावर

गोरखपुर, फर्रुखाबाद और अब लखीमपुर खीरी में हुई तमाम बच्चों की दुखद मौत ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकार की हृदयहीनता उजागर की है. प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कहता है कि बच्चों की मौत तो होती ही रहती है, यह सरकार के हत्यारे होने की सनद है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस गोरखपुर जिले से आते हैं और वहीं से लगातार सांसद होते रहे हैं. गोरखपुर में बच्चों की लगातार होने वाली मौतों पर वे लगातार यही कहते रहे कि भाजपा जब सत्ता में आएगी तो सरकार का पहला काम होगा बच्चों की मौत रोकना. लेकिन नतीजा सामने है. ऑक्सीजन के लिए महज 67 लाख रुपए का भुगतान नहीं देने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई और 60 से अधिक बच्चों को दम घोंट कर मार डाला गया. मानवतावादी होने का दावा करने वाली इसी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा का बजट घटाकर आधा कर दिया. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इसी बजट में पैसे मिलते रहे हैं. प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों और उनके साथ जुड़े अस्पतालों का बजट पिछले वर्ष के 2344 करोड़ से घटाकर इस वर्ष 1148 करोड़ कर दिया गया. बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष 15.9 करोड़ रुपए था, जिसे घटा कर इस वर्ष 7.8 करोड़ कर दिया गया. चिकित्सा से जुड़ी मशीनों और उपकरणों के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को मिलने वाली राशि तीन करोड़ रुपए से घटाकर मात्र 75 लाख रुपए कर दी गई. प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी यही किया गया. कानपुर और इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेजों का बजट आवंटन 15.9 करोड़ से घटा कर इस वर्ष क्रमशः 3.3 करोड़ और 4.2 करोड़ कर दिया गया. गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के इंसेफलाइटिस वार्ड में कार्यरत 378 चिकित्साकर्मियों (चिकित्सक, शिक्षक, नर्स और कर्मचारी) को मार्च 2017 से तनख्वाह नहीं मिली. करीब दर्जनभर पीएमआर कर्मचारियों को 27 महीने से वेतन नहीं मिला. यह क्या है? यह क्या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति योगी सरकार का मानवीय 'अप्रोच' है?

विडंबना यह है कि इसी साल मई महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने पोलियो और फाइलेरिया की तरह जापानी इन्सेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान शुरू किया था. लेकिन यह अभियान केवल प्रधानमंत्री मोदी की चाटुकारिता के दायरे में ही रह गया. इसके शिकार केवल गोरखपुर, फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी जिले ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अस्पताल हुए हैं. जनसंख्या के मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से लेकर विभिन्न स्तर के अस्पतालों की स्थापना के कानूनी प्रावधानों का पालन करने की बात तो छोड़िए, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहले से हैं उन्हें भी फेल करने की तरफ भाजपा की सरकार अग्रसर है. पूंजी घरानों को मजबूत करने और स्वास्थ्य-माफियाओं को सुखी-सम्पन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है.

केंद्र सरकार भी इस साल जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेकर आई, उसने पूंजी घरानों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आखेट करने का मौका दिया है. इस नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी निजी घरानों-संस्थानों से खरीदी जाएंगी. इंगलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन जैसे कई पूंजी-परस्त देशों में यह व्यवस्था वर्षों पहले (1985 से) लागू है, लेकिन उन देशों में भी 'परचेज़र प्रोवाइडर स्प्लिट मॉडल' की व्यवस्था फेल साबित हो चुकी है. ऐसी ही व्यवस्था को अपने यहां माथे पर उठा कर उसे नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के नाम से बेचा जा रहा है. यूपी सरकार ने भी 'बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन' के साथ मिलकर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को 'आउटसोर्स' करने का करार किया था. इस करार की शर्त ही थी कि स्थानीय सेवादाताओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. नई स्वास्थ्य नीति लागू होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के घरेलू बाज़ार का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा और इस क्षेत्र में खर्च होने वाला सरकारी धन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली निजी कम्पनियों के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद साबित होगा. इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने और अस्पतालों की श्रृंखला चलाने वाली ज्यादातर बड़ी कम्पनियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 से बेहद प्रसन्न हैं. देश की नई स्वास्थ्य नीति का लाभ आम मरीजों को क्या मिल पाएगा, इस बारे में आप समझ सकते हैं और यह भी बखूबी समझ सकते हैं कि निजी कम्पनियां इससे कितना बेशुमार धन कमाएंगी.

नीतियां बनाने वाले हवाबाज-राजनीतिकों को देश की जमीनी स्थिति दिखाई नहीं देती. यूपी को ही एक उदाहरण के बतौर लें, तो पाएंगे कि यहां जनसंख्या बढ़ती रही, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं नीचे ही गिरती चली गईं. यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए केवल एक सरकार दोषी नहीं है, दोष सभी सरकारों का है. सबने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को केवल धन कमाने के स्रोत के बतौर इस्तेमाल किया. इस वजह से नौबत यहां तक आ गई कि विभिन्न बीमारियों से होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में अव्वल है. टाइफाइड से देशभर में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत मौतें यूपी में होती हैं. कैंसर से मरने वाले लोगों में यूपी की भागीदारी 20 प्रतिशत के करीब है, जबकि करीब इतने ही लोग टीबी से मरते हैं. प्रसव के समय मरने वाली महिलाओं (एमएमआर) में उत्तर प्रदेश का स्थान असम के बाद दूसरे नम्बर पर है. वर्ष 2015 का आंकड़ा बताता है कि यूपी में प्रत्येक एक लाख महिलाओं में से 285 महिलाओं की मौत प्रसव के दरम्यान हो गई. प्रदेश की 62 प्रतिशत से अधिक महिलाएं प्रसव से पूर्व मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं. जन्म से पहले के पांच साल में शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है. यूपी में हजार नवजात बच्चों में से 64 बच्चे पांच साल की आयु पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं. प्रति हजार बच्चों पर जन्म के एक महीने के भीतर 35 बच्चे मरते हैं. 50 बच्चे एक साल भी पूरा नहीं कर पाते. विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे पिछड़े आठ राज्यों में होती है.■

feedback@chauthiduniya.com

नई पार्टी की घोषणा के लिए प्रेस वार्ता बुलाकर पलट गए मुलायम

अब नेता जी नहीं, केवल पिता जी

लक्ष्मण बनने के चक्कर में क़ुरबान हो गए शिवपाल

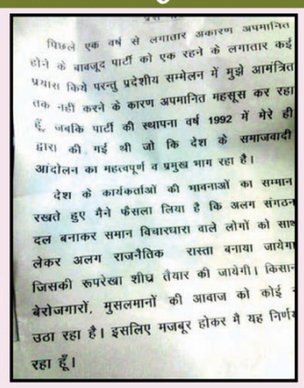

पिछले एक वर्ष से लगातार अकारण अपमानित होने के बावजूद पार्टी को एक रहने के लगातार कई प्रयास किये परन्तु प्रदेशीय सम्मेलन में मुझे आमंत्रित तक नही करने के कारण अपमानित महसूस कर रहा हूँ, जबकि पार्टी की स्थापना वर्ष 1992 में मेरे ही द्वारा की गई थी जो कि देश के समाजवादी आंदोलन का महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग रहा है।

देश के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैंने फैसला लिया है कि अलग संगठन बनाकर समान विचारधारा वाले लोगों को साथ लेकर अलग राजनैतिक रास्ता बनाया जायेगा जिसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार की जायेगी। किसान, बेरोजगारों, मुसलमानों की आवाज को कोई उठा रहा है। इसलिए मजबूर होकर मै यह निर्णय ले रहा हूँ।

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी के गृह-युद्ध में रामायण और महाभारत दोनों का पुट मिलता है. मुलायम सिंह यादव ने 25 सितम्बर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर यही साबित किया कि शिवपाल यादव भले ही लक्ष्मण की भूमिका में हों, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बल्कि पुत्र-मोह से ग्रस्त धृतराष्ट्र हैं. मुलायम सिंह ने इतने लंबे अर्से से चले आ रहे तमाम उहा-पोह और भ्रम समाप्त कर दिए और यह जाहिर कर दिया कि कलह-उपक्रम उन्होंने अपने पुत्र के राजनीतिक करियर की स्थापना के लिए ही रचा था. शिवपाल भातृ-भाव में कुरबान हो गए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुलायम नेता जी नहीं, केवल पिता जी होकर रह गए. सियासत की नब्ज पहचानने और जानने वाले यह जानते हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भी शिवपाल को भाजपा में शामिल होने का न्यौता और मंत्रिमंडल में सम्मानजनक स्थान दिए जाने का प्रस्ताव मिला था. भाजपा की सरकार बन जाने के बाद भी न्यौता कायम था, लेकिन शिवपाल ने भातृ-भाव में ही उस ऑफर को ठुकरा दिया. मुलायम के रुख से पूरी अंतरगाथा स्पष्ट हो जाने के बाद अब शिवपाल अपने बूते नई पार्टी का ऐलान करेंगे.

25 सितम्बर को मुलायम की ओर से नई पार्टी का ऐलान होना था. पूरा स्टेज सेट था. इसी आशय का प्रेस नोट भी तैयार था. मुलायम ने आखिरी समय तक शिवपाल और समर्थकों को भी भ्रम में रखा. लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नई पार्टी की घोषणा को उन्होंने आखिरी समय में ताक पर रख दिया. मुलायम ने साफ-साफ कहा कि वे नई पार्टी नहीं बनाएंगे. मुलायम यह भी बोल गए कि समाजवादी पार्टी वे ही चला रहे हैं. यानि, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी में अब तक जो कुछ भी हुआ, सब उनके ही इशारे पर हुआ. मुलायम ने कहा, 'मैं न अखिलेश के साथ हूं न शिवपाल के साथ, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ हूं.' प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम ने इसके अलावा जो कुछ भी कहा वह चतुर-छलावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था. इसी छलावे पर मुलायम अपने समर्थकों के साथ-साथ प्रदेशभर के लोगों को अब तक भ्रम में रखे रहे. मुलायम के लिए प्रतिबद्ध रहे एक वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि मुलायम बेटे अखिलेश द्वारा धोखा देने और दुर्व्यवहार करने जैसी बातें छलावे के तहत ही करते रहे. मुलायम एक तरफ अखिलेश के विश्वासघात की बात करते रहे तो दूसरी ओर अपने सारे वरिष्ठ समर्थकों को चुपचाप अखिलेश का समर्थन करने का निर्देश भी देते रहे. मुलायम अखिलेश के दुर्व्यवहार का रोना भी रोते रहे और लोगों से सपा के साथ जुड़ने की अपील भी करते रहे. मुलायम का यह रवैया देख कर भगवती सिंह, शारदा प्रताप शुक्ला समेत कई अन्य नेता भी हतप्रभ रह गए, जब मुलायम ने अचानक पैंतरा बदलते हुए कहा कि नया दल बनाने का सवाल नहीं उठता. नई पार्टी के गठन के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर भी मुलायम बुरा मान रहे थे. उन्होंने अखबार वालों से तल्खी से कहा भी, 'यह सवाल बार-बार क्यों पूछ रहे हैं?' जबकि जो प्रेस विज्ञप्ति बनी थी, उसमें ही नई पार्टी की घोषणा किए जाने के बारे में लिखा था. आप भी देखें, प्रेस विज्ञप्ति में साफ-साफ लिखा है, 'देश के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैंने फैसला किया है कि अलग संगठन दल बनाकर समान विचार-धारा वाले लोगों को साथ लेकर अलग राजनीतिक रास्ता बनाया जाएगा. इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार की जाएगी. किसानों, बेरोजगारों, मुसलमानों की आवाज को कोई नहीं उठा रहा है. इसलिए मजबूर होकर मैं यह निर्णय ले रहा हूं.'

मुलायम के इस रवैये से इटावा, मैनपुरी, जसवंत नगर समेत कई अन्य इलाकों से बड़ी तादाद में लखनऊ पहुंचे मुलायम और शिवपाल के समर्थकों में निराशा और मायूसी देखने को मिली. शिवपाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे. समर्थकों की भीड़ शिवपाल के घर पहुंच गई और उनसे नई पार्टी बनाने को कहा. लखनऊ में मायावती की प्रतिमा तोड़कर समाजवादी सरकार का प्रमुख चुनावी वादा पूरा करने वाले उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल के कट्टर समर्थक अमित जानी ने कहा कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने ठाकुर अमर सिंह के उस आरोप को स्वतः सिद्ध कर दिया है, जिसमें उन्होंने सपा के महाभारत का स्क्रिप्ट राइटर मुलायम सिंह को बताया था. अमित जानी ने कहा कि शिवपाल लक्ष्मण-भ्राता का कर्तव्य निभाते रहे, लेकिन वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति रामभक्तों का हत्यारा होगा वह राम कैसे हो सकता है? जिस तरह पांडवों के त्याग को नजरअंदाज करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और दुःशासन का साथ दिया, ठीक उसी तरह नेता जी भी पुत्र-मोह में अंधे हो गए हैं. दुर्योधन के पास भी पिता का आशीर्वाद था लेकिन युद्ध में धर्म की जीत हुई पिता-पुत्र की नहीं. अमित जानी ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में जो भी दल बनेगा, वर्ष 2019 में देश की सरकार बनाने में उसकी महती भूमिका होगी, जबकि सपा खाता तक नहीं खोल सकेगी.

नई पार्टी की घोषणा न करने पर सपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला भी मुलायम के खिलाफ मैदान में आ डटे हैं. शुक्ला ने कहा कि मुलायम नकली समाजवादी हैं और सारा कुछ पिता-पुत्र की मिलीभगत से हुआ है. उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मुद्दा ही नए मोर्चे के गठन का था, लेकिन मुलायम ने वह कागज पढ़ा ही नहीं. मैंने उन्हें मंच पर याद भी दिलाया तो मुलायम ने यह कहकर टाल दिया कि यह वक्त सही नहीं है. मुलायम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से अखिलेश पर हमला करने का छद्म करते रहे, लेकिन असली कागज छुपाते रहे, जो प्रेस की निगाह में आ ही गया.

मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बनी स्थितियों पर शिवपाल यादव ने 'चौथी दुनिया' से इतना ही कहा, 'नेता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा, वह उनका निजी विचार है, नेता जी मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं उन्हें अपना शुभेच्छु-दिग्दर्शक भी मानता हूं, लिहाजा उनके कहे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. जहां तक राजनीतिक निर्णय का प्रसंग है, उसकी मैं अपने समर्थकों के साथ समीक्षा कर रहा हूं और शीघ्र ही उस अनुरूप फैसला करूंगा.' आपको यह बता दें कि मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव की अनुपस्थिति चर्चा के केंद्र में रही. 23 सितम्बर को ही मुलायम ने लोहिया ट्रस्ट के सचिव पद से रामगोपाल यादव को हटाकर शिवपाल को सचिव बना दिया था. 24 सितम्बर को शिवपाल ने दो बार मुलायम सिंह से उनके घर जाकर मुलाकात की. इन दो दिनों में मुलायम और शिवपाल के बीच समाजवादी सेकुलर मोर्चा के गठन और उसके ऐलान की बात तय हो गई थी. दरअसल, इसी घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई भी गई थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले भी शिवपाल की मुलायम से बात हुई, लेकिन उस बात में ही शिवपाल को यह आभास हो गया कि मुलायम नई पार्टी की घोषणा नहीं करेंगे. इसके बाद ही शिवपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने का फैसला किया. जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल का राजनीतिक भविष्य तय होना था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम ने यह तय कर दिया कि बेटे के आगे भाई के राजनीतिक करियर से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है. अब शिवपाल यादव के पास नेताजी का साथ छोड़कर अपना अलग राजनीतिक सफर तय करने का निर्णय लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है. शिवपाल समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन कर एनडीए के साथ जा सकते हैं. राजनीतिक गलियारे में शिवपाल के कभी बसपा में तो कभी जेडीयू में भी जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन शिवपाल समर्थकों को शिवपाल के नेतृत्व में नई पार्टी के अस्तित्व में आने की उम्मीद है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पीएम से छेड़खानी की शिकायत करना चाहती थीं बीएचयू की छात्राएं, बरसी लाठियां

अहमक़ वीसी को पसंद नहीं लोकतांत्रिक मूल्य

पहली बार बीएचयू की छात्राएं उतरीं सड़क पर, देशभर से मिल रहा समर्थन

दीनबंधु कबीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया है. वाराणसी में मोदी का आगमन एक नए राजनीतिक बवाल का सबब बन गया है. बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) लंबे अर्से से अंदर ही अंदर सुलग रहा था. प्रधानमंत्री के हाल के आगमन के बाद वह अचानक भड़क गया. बीएचयू के कुलपति डॉ. गिरीश चंद्र त्रिपाठी को नागवार यह लगा कि छेड़खानी और बदसलूकियों के खिलाफ बीएचयू की छात्राओं ने ऐन प्रधानमंत्री के आगमन के समय धरना-प्रदर्शन का फैसला क्यों कर लिया. लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखने वाले कुलपति को यह एहसास ही नहीं हुआ कि अपने सांसद के समक्ष शिकायतें रखना छात्राओं का लोकतांत्रिक अधिकार है. कुलपति ने छात्राओं पर बर्बर लाठियां चलवाईं. छेड़खानी के विरोध में धरना दे रही छात्राओं पर लाठियां चलाने वाले बीएचयू के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस वालों ने भी छात्राओं के साथ भीषण बदतमीजियां कीं. बनारस के कमिश्नर रमेश गोकर्ण ने छेड़खानी की घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि करते हुए लाठी चार्ज के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को सीधे तौर पर दोषी करार दिया है. कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी है. दंभ से भरे वीसी त्रिपाठी ने चुनौती देते हुए कहा कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद उन्हें कोई सस्पेंड नहीं कर सकता.

कैंपस में बढ़ती छेड़खानी के विरोध में छात्राएं दो दिन से धरने पर बैठी थीं. बीएचयू के सुरक्षाकर्मियों द्वारा किए गए पथराव व बीएचयू गेट और महिला महाविद्यालय के पास बर्बर लाठी चार्ज के बाद शनिवार 23 सितम्बर की देर रात से स्थिति खराब होने लगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएचयू कैंपस में भी पुलिस बुला लिया. पुलिस को छात्रों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा. इस पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की और बेतहाशा आंसू गैस के गोले दागे. लाठी चार्ज में छात्राओं के जख्मी होने और सुरक्षा कर्मियों द्वारा छेड़खानी किए जाने से स्थिति बेकाबू हो गई. छात्रों ने भी

जमकर पथराव किया. पुलिस ने बिड़ला हॉस्टल में घुसने की कोशिश की, तो वहां कई बम धमाके हुए. इसके बाद पुलिस बल को बाहर निकलने का आदेश दिया गया. आगजनी की भी घटनाएं हुईं.

छेड़खानी के विरोध में धरना दे रही छात्राओं की मांग थी कि कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी मौके पर आकर छात्राओं की समस्याएं सुनें और कार्रवाई का आश्वासन दें. लेकिन कुलपति धरनास्थल पर नहीं आए. कुलपति के इस रवैये से छात्र-छात्राओं में और गुस्सा बढ़ा. फिर कुलपति ने लाठी चार्ज का आदेश देकर आग में घी डाल दिया. छात्रों को काबू में करने के लिए 23 थानों की पुलिस, एक दर्जन वज्र वाहन और पांच कंपनी पीएसी बुला ली गई थी. बीएचयू के छात्र कहते हैं कि 21 सितम्बर को विभाग से त्रिवेणी हॉस्टल जा रही दृश्य कला संकाय की छात्रा के साथ भारत कला भवन के पास कुछ लड़कों ने छेड़खानी और बदसलूकी की थी. इस घटना के विरोध में त्रिवेणी हॉस्टल की छात्राएं रात में ही सड़क पर उतर आईं. 22 सितम्बर को सुबह छह बजे से छात्राओं ने सिंह-द्वार पर धरना शुरू कर दिया. छात्राओं की शिकायतें न कुलपति सुन रहे थे और न प्रशासन ध्यान दे रहा था. इससे विवश होकर छात्राएं 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाले अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कहना चाहती थीं. लेकिन कुलपति ने इसमें रोड़ा डाल दिया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं का धरना खत्म कराने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन छात्राएं कार्रवाई की मांग पर अड़ी रहीं. छात्राओं का कहना था कि वीसी आकर कार्रवाई का भरोसा देते तो धरना उसी समय खत्म हो जाता. छात्राओं के आंदोलन के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का रूट बदलना पड़ा. इससे कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी और बिफर गए. वे इस निम्नस्तरीयता पर उतर आए कि बेसाख्ता कह दिया कि छात्राओं पर लाठी चली ही नहीं. जबकि दर्जनों छात्राएं जख्मी हुईं और उनका इलाज कराया गया. पत्रकारों को भी बुरी तरह पीटा गया था. बनारस के कमिश्नर रमेश गोकर्ण ने लाठीचार्ज की तो पुष्टि की ही छेड़खानी की घटनाओं को भी सही बताया है. कमिश्नर ने घटना के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव राजीव कुमार को भेज दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस घटना की जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को ही सौंपी है. हालांकि बीएचयू प्रशासन ने भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वीके द्विवेदी की एक सदस्यीय समिति से मामले की न्यायिक जांच कराने का उपक्रम किया है. घटना के बाद इलाके के एसीएम (फर्स्ट) मनोज कुमार सिंह को ज्ञानवापी सुरक्षा ड्यूटी में भेज दिया गया है. लंका थाने के प्रभारी राजीव कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है और भेलपुर के सीओ विनय कटियार को लेखा शाखा में तैनात कर दिया गया है.

बीएचयू की घटना पर प्रख्यात साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने कहा कि छात्राओं पर लाठी चार्ज ही अगर राष्ट्रप्रेम है, तो इस देश का ईश्वर ही मालिक है. काशीनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने 32 साल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी की. इसके पहले जो भी आंदोलन हुए वे छात्रों और छात्र संघों ने किए. यह पहला आंदोलन है, जिसकी अगुवाई छात्राओं ने की और सैकड़ों की तादाद में छात्राएं आगे बढ़कर आईं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर बड़ी तादाद में छात्राएं धरना दे रही थीं. वे धरने पर इसलिए बैठी थीं कि उस रास्ते से प्रधानमंत्री जाने वाले थे जो इस क्षेत्र के सांसद भी हैं. लड़कियों का हक बनता था कि वे अपनी बात उनसे कहें. प्रधानमंत्री ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया और चुपके से दूसरे रास्ते से चले गए. यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. 'चौथी दुनिया' के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने भी कहा कि चुपके से दूसरे रास्ते से निकलने के बजाय प्रधानमंत्री अगर छात्राओं से मिल लेते और 'बेवकूफ-बुद्धिजीवी' जीसी त्रिपाठी को वीसी पद से हटा देते तो मोदी की राष्ट्रव्यापी छवि उभरती और उन्हें व्यापक प्रसिद्धि मिलती. लेकिन मोदी ने इस मौके को खुद ही गंवा दिया. ■

शरद मानेंगे नहीं और जदयू छोड़ेगा नहीं

सरोज सिंह

जैसी आशंका थी ठीक वैसे ही शरद यादव और जदयू नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. शरद यादव पूरे बिहार के दौरे पर निकल पड़े हैं और इसमें राजद इनका पूरा साथ दे रहा है. शरद यादव जहां जा रहे हैं वहीं नीतीश सरकार को अपने जुबानी तीरों से घायल करने की कोशिश कर रहे हैं. शरद कहते हैं कि बिहार में अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. वे आरोप लगाते हैं कि विकास योजनाओं में लूट मची है. अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बांध उद्घाटन के पहले थोड़े ही टूट सकता है. आरोपों से इतर शरद खेमा राजनीतिक दांव पेंच भी आजमा रहा है. शरद के खास और पूर्व मंत्री अर्जुन राय ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि हमलोगों ने विजेंद्र यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय कर रखा है और उचित समय आने पर बिहार में इनके नेतृत्व में नई सरकार बन जाएगी. पार्टी पर कब्जे को लेकर तो लड़ाई चुनाव आयोग में चल ही रही है. कहा जाए तो शरद यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश खेमे को परेशानी में डाला जाए.

इधर राज्यसभा में जदयू के नेता आरसीपी सिंह शरद यादव पर जुबानी हमले कर रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने शरद यादव को ये सलाह दे डाली कि आप आंखों की जांच कराकर चश्मे का नंबर बदलवाइए. उन्होंने कहा, शरद को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वे किसके साथ खड़े हैं. वे खुद भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता लोगों के साथ हैं. दूसरों पर बोलने से पहले वे अपने गिरेबां में झांक कर देखें. शरद यादव वो दिन भूल गए, जब वे अपने लोकसभा चुनाव के दौरान गिनती में हुई धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे थे. दोबारा गिनती हुई तब वे चुनाव जीते. वे बताएं कि उस समय किसका राज था. उन्हें ये भी बताना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार ने किसी को छुड़ाने या बचाने के लिए पैरवी की है. बिहार की जनता जानती है कि शरद का यहां पर कोई आधार नहीं है. वे कभी जदयू तो कभी लालू प्रसाद के सहारे बिहार आते और घूमते रहे हैं. उनकी बिहार में अपनी क्या पहचान है? उन्हें तो जदयू ढो रहा था. आरसीपी सिंह ने शरद यादव से ये भी सवाल किया कि वे बताएं कि बिहार में अब कहां अंधेरा है. राज्य की सरकार ने बिजली की स्थिति को सुधार कर बिहार में अंधेरा खत्म कर दिया है. जीएसटी पर शरद यादव को कुछ समझ ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जदयू ने शरद यादव पर सीधी कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने इनके दावे को भी खारिज कर दिया है.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने शरद यादव पर लालू को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी यात्रा का असली मकसद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पारिवारिक विरासत और संपत्ति को बचाना है. साझी विरासत का नाम लेकर शरद सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शरद जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे उनकी हताशा साफ झलक रही है. शरद यादव से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी. वैसे कल्पना के सागर में डूबने या गोते लगाने से किसी को रोका तो नही जा सकता है. वे जिले-जिले घूमकर अपना दुखड़ा रो रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इधर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी शरद यादव को अपनी भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए. जिस बिहार ने शरद को इतना मान-सम्मान दिया और जिस दल ने उन्हें राजनीतिक बुलंदी दी, आज उसी बिहार को और उसी जदयू को वे अपमानित कर रहे हैं.

पिछले दिनों नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव का नाम उछाल कर शरद खेमे ने दोहरी चाल चली. शरद खेमा चाह रहा है कि नीतीश से नाराज और भाजपा के साथ गठबंधन से नाराज जदयू के विधायक विजेंद्र यादव के नेतृत्व में एकजुट हों. शरद खेमे का ऐसा मानना है कि भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर जदयू के यादव और मुसलमान विधायक बहुत खुश नहीं हैं. लेकिन दलबदल कानून के डर से ये विधायक चुप हैं वरना बहुत पहले ही ये सभी शरद यादव के साथ आ जाते. शरद खेमे का मानना है कि यादव व मुसलमान विधायक हर हाल में लालू का साथ चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अगले चुनाव में भी जीत कर आना है. ऐसे विधायकों को लगता है कि लालू प्रसाद का जो वोट बैंक है, वो अगली लड़ाई में इन्हें मदद कर सकता है. इसी धारणा को आधार मानते हुए अर्जुन राय ने विजेंद्र यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछाल दिया. अर्जुन राय का कहना है कि विजेंद्र यादव यह नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद के साथ रिश्ता खत्म किया जाय. पार्टी की बैठक में भी उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था. इसलिए हमलोग चाहते हैं कि विजेंद्र यादव के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार का गठन हो. लेकिन शरद खेमे के इस तीर को सबसे पहले विजेंद्र यादव ने ही भोथर कर दिया. विजेंद्र यादव कहते हैं कि पार्टी की बैठक में मैंने विरोध नहीं किया. हां, मेरे मन में कुछ आशंका थी जिसका मैंने इजहार किया था. लेकिन पार्टी ने उन शंकाओं का समाधान कर दिया. विजेंद्र यादव ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि इसको पीछे छोड़ना किसी के वश की बात नहीं है. जदयू में आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो यह कोरा बकवास है और शरद खेमे में फैली हताशा का प्रतीक है.

शरद यादव खेमे के इस ताजा हमले के बाद नीतीश खेमा अब और भी आक्रामक हो गया है. पहली कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो और शरद को पूरी तरह लालू के पिछलग्गू के तौर पर दिखाया जाय. जदयू जनता में यह संदेश फैलाना चाहती है कि नीतीश कुमार ने जिस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए महागठबंधन तोड़ दिया, शरद यादव उसी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए लालू प्रसाद के पीछे-पीछे घूम रहे हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा भी उठाया जाएगा कि शरद यादव अपने बेटे के टिकट के लिए लालू की शरण में चले गए हैं. नीतीश ने चूंकि परिवारवाद का विरोध किया, इसलिए शरद और नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो गए. शरद यादव की बोलती बंद करने के लिए जदयू उनके दिल्ली के नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की कोशिश में है. जमीनी ताकत में शरद यादव पहले से ही कहीं नहीं टिकते. देखा जाए तो अब लड़ाई आर-पार की है और सीज फायर की भी कोई गुंजाइश नहीं है. न शरद मानेंगे और न ही जदयू छोड़ेगा.■

जदयू जनता में यह संदेश फैलाना चाहती है कि नीतीश कुमार ने जिस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए महागठबंधन तोड़ दिया, शरद यादव उसी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए लालू प्रसाद के पीछे-पीछे घूम रहे हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा भी उठाया जाएगा कि शरद यादव अपने बेटे के टिकट के लिए लालू की शरण में चले गए हैं. नीतीश ने चूंकि परिवारवाद का विरोध किया, इसलिए शरद और नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो गए. शरद यादव की बोलती बंद करने के लिए जदयू उनके दिल्ली के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश में है.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार के पहले सोलर पार्क को नक्सलियों ने उड़ाया

थम नहीं रही लेवी के लिए नक्सली कार्रवाई

सुनील सौरभ

झारखंड से लगे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लेवी के लिए होने वाली नक्सल गतिविधियों में कमी नहीं आ रही है. 2017 में ही अबतक दर्जन भर हिंसक नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं. इन घटनाओं में नक्सलियों का ज्यादातर टार्गेट जीटी रोड़ के आसपास का क्षेत्र रहा है. पुल-पुलिया और सड़क निर्माण के साथ-साथ नहर व बिजली परियोजनाएं भी यहां प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के निशाने पर हैं. कार्य कराने वाले ठेकेदारों व ठेका कम्पनियों से लेवी वसूलने के लिए नक्सली लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. जबकी अत्याधुनिक हथियारों एवं संसाधनों से लैस केन्द्रीय व राज्य के करीब 10 हजार से अधिक सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित झारखंड की सीमा से लगे बिहार के क्षेत्रों में तैनात हैं. गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में ही नक्सल विरोधी ऑपरेशन को लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती है. इनमें सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा के साथ-साथ बिहार पुलिस भी शामिल है. यहां नक्सल विरोधी अभियान में प्रति महीने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बहुत सार्थक नहीं है.

ताजा घटना है, बिहार के पहले सोलर पार्क पर नक्सली हमले की. लेवी के लिए नक्सलियों ने 19 सितम्बर 2017 को 25 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले सोलर पार्क को निशाना बनाया. गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के सांवकला में 125 एकड़ में स्थापित सोलर पार्क पर नक्सली हमले में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है. यहां से उत्पादित बिजली की आपूर्ति शेरघाटी और बोधगया ग्रीड को की जाती है. बिहार सरकार की पहल पर पीपीपी मोड के अंतर्गत वेलस्पॉन नामक कम्पनी ने बिहार के इस पहले सोलर पार्क की स्थापना की थी. जीटी रोड पर ही डोभी में इस कम्पनी का दूसरा सोलर पार्क संचालित है. बताया जाता है कि इसी के लिए नक्सलियों के एक संगठन ने लेवी की मांग की थी. लेवी नहीं दिए जाने पर 19 सितम्बर को दो सौ की संख्या में आए हथियारबंद नक्सलियों ने सोलर पार्क को चारो तरफ से घेर लिया. 30 हथियारबंद नक्सली अंदर गए और उन्होंने वहां मौजूद 15 सुरक्षा गार्ड एवं 5 टेक्निकल स्टाफ को कब्जे में ले लिया. इसके बाद नक्सलियों ने सोलर पार्क के केबीन, कंट्रोल रूम और प्लांट के मुख्य भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया.

गौर करने वाली बात ये है कि इस सोलर पार्क से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आमस थाना और एसएसबी कैम्प स्थित है, लेकिन इतनी दूरी को तय करने में ही सुरक्षाबलों को 3 घंटे लग गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जब आश्वास्त हो गई कि नक्सली चले गए, तब वो वहां पहुंची. इससे नक्सलियों से लोहा लेने की बिहार पुलिस की प्रतिबद्धता समझी जा सकती है. इस घटना के चंद दिनों बाद ही 23 सितम्बर को गया के ही परैया में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगी ठेका कम्पनी के लोगों को हमला कर भगा दिया और टैक्टर, डीजल समेत लाखों के सामान लूट ले गए. ये इस तरह की पहली घटनाएं नहीं हैं. केवल मार्च में ही इस क्षेत्र में कई नक्सल घटनाएं हुईं. 12 मार्च को इमामगंज के पसेवा गांव में नक्सलियों ने कैशल पासवान का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी. इसके तीन दिन बाद ही 15 मार्च 2017 को नक्सलियों ने मोहनपुर थाना क्षेत्र में गैस पाईप लाईन का काम कर रही गेल इंडिया के कैम्प पर हमला किया था. 24 मार्च 2017 को बाराचट्टी के गजरागढ़ में लेवी के लिए नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया. वहीं 26 मार्च को शेरघाटी के चितार उचिरमा के बीच चल रहे पुल निर्माण कार्य पर हमला कर दिया. इस प्रकार लगातार नक्सली घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल लाचार बने हुए हैं. सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तो दूर, जीटी रोड पर हो रहे नक्सली हमलों पर ही काबू नहीं पाया जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

खुले में शौच से मुक्ति के लिए शुरू हुआ अभियान

'चम्पारण का रण'

राकेश कुमार

चम्पारण के पताही प्रखंड अंतर्गत परसौनी कपूर गांव के पठनू पासवान रोज की भांति लोटा में पानी लेकर शौच के लिए खेत की ओर निकले. वे शौच कर ही रहे थे कि कुछ लोग आए और उन्हें पकड़ लिए. हतप्रभ पठनू ने उनसे पूछा कि उन्होंने आखिर कौन सा गुनाह कर दिया, तो उन्हें बताया गया कि आप खुले में शौच कर रहे थे, इसलिए आपको पकड़ा गया है. पठनू के साथ-साथ सभी ग्रामवासी भी भौंचक थे कि खुले में नित्यक्रिया अपराध कैसे हो गया. तब उन्हें स्वच्छता अभियान और खुले में शौच से होने वाले खतरों के बारे में बताया गया. पठनू पर 200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया. उन्हें इस हिदायत के साथ छोड़ा गया कि वे जल्द से जल्द अपने घर में शौचालय बनवाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे.

दरअसल, ये 'चम्पारण का रण' अभियान के तहत की गई कार्रवाई थी. पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अभियान चल रहा है. चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक के अभियान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वच्छता अभियान के तहत पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है. पूर्वी चम्पारण जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने की थी. इस अभियान को गति देते हुए वर्तमान जिलाधिकारी रमण कुमार ने इसे 'चम्पारण का रण' नाम दिया है. श्री कुमार पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संस्थाओं के साथ-साथ आम आदमी को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं. इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी 'चम्पारण का रण' नामक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें हर गांव-टोलों में होने वाली स्वच्छता से सम्बन्धित गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध होती है. 'चम्पारण का रण' अभियान का अलग से प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है. इसकी सफलता को लेकर जिला स्तर से गांव व टोले तक नोडल पदाधिकारी और निगरानी टीम बनाई गई है, जो जनजागरूकता के साथ ही शौचालय निर्माण के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.

ग्रामीणों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करते डीएम रमण कुमार

डीएम श्री कुमार स्वयं भी सुदूर गांवों में रात्री चौपाल लगा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं. जिला प्रशासन के दावों पर यकीन करें, तो पूरे जिले में अब तक लगभग 25 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कराया गया है. लेकिन धरातल पर अब भी कई खामियां दिखाई दे रही हैं. जिले का पहला ओडीएफ पंचायत है, पताही प्रखंड का परसौनी कपूर, जहां खुले में शौच के कारण पठनू पासवान को अर्थदंड का भागी होना पड़ा. मुखिया अनिल कुमार सिंह की मानें, तो यहां हर परिवार के पास अपना शौचालय है. वे बताते हैं कि वार्ड सदस्यों और पदाधिकारियों की कड़ी मेहनत के बाद पूरे पंचायत को मात्र 22 दिनों के प्रयास में खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया. ये स्थिति बनी रहे इसके लिए ग्रामीणों की निगरानी समिति बना कर खुले में शौच करने वालों को पकड़ा जाता है और उनसे 100 से 300 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता है. वहीं खुले में शौच करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को पुरस्कार स्वरूप 50 रुपए दिए जाते हैं. मुखिया अनिल सिंह ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से एक बैंक एकाउंट खोला गया है, जिसमें जुर्माने की राशि जमा कराई जाती है.

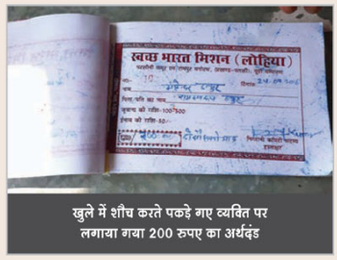

खुले में शौच करते पकड़े गए व्यक्ति पर लगाया गया 200 रुपए का अर्थदंड

इस अभियान की सफलता को लेकर 'चौथी दुनिया' की पड़ताल में ये जानकारी भी सामने आई कि कई जगह ये अभियान कमाई का जरीया बन गया है. बंजरीया प्रखंड के अजगरी गांव में इसकी बानगी देखने को मिली. प्रावधान के अनुसार, शौचालय निर्माण के लिए सरकारी स्तर पर लोगों को बारह हजार रुपए मिलने थे. लेकिन सरकारी राशि के बंदरबांट के लिए किसी एजेंसी से लोगों के लिए शौचालय निर्माण कराया गया. उस एजेंसी द्वारा किए गए कार्य की किसी ने निगरानी नहीं की, लिहाजा उसने काम गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया. ग्रामीण नारद मुखिया, दया महतो और भाग्यनारायण राउत बताते हैं कि खराब ईंट और लोकल बालू से उस एजेंसी ने जैसे-तैसे शौचालय बनवा दिया. नतीजतन एजेंसी द्वारा बनाए गए कई शौचालय बारिश भी बर्दास्त नहीं कर सके और गिर गए. चूंकि सहायता राशि परिवार के मुखिया के बैंक एकाउंट में आती है, इसलिए पहले ही ज्यादातर लोगों से विड्रॉल फार्म भरवा लिया गया और राशि आने के बाद भुगतान उठा लिया गया. दरअसल, तत्कालीन डीएम अनुपम कुमार ने सभी प्रखंडों के एक-एक पंचायत को ओडीएफ करने के लिए चुना था और निर्देश दिया था कि जो पंचायत ये लक्ष्य पूरा नहीं करेगा, उसे अन्य सभी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा. पता चला कि एजेंसी द्वारा आनन-फानन में आधे-अधूरे शौचालय का घटिया निर्माण करा कागज पर अजगरी को ओडीएफ दिखा दिया गया और सहायता राशि का बंदरबांट हो गया. यह तो बानगी भर है, अगर जांच हो, तो ज्यादातर ओडीएफ गांव ऐसे मिलेंगे, जहां अभी भी 10 से 20 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय नहीं है. इस बारे में जिलाधिकारी रमण कुमार का कहना है कि हम पूरे जिले को शौच से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं. इसमें जो भी गड़बड़ी करता पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई होगी. सहायता राशि का बंदरबांट करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ओडीएफ के प्रभारी पदाधिकारी उप विकास आयुक्त का कहना है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने स्वीकार किया कि बाढ़ के कारण इस अभियान की रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद पुन: इस अभियान में गति आ गई है.■

भारत व नेपाल के दिलों को जोड़ता बराह छत्तर मेला

संजय सोनी

भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के करीब भारत व नेपाल आध्यात्म के जरिए भी जुड़े हुए हैं. कई धार्मिक स्थल सीमावर्ती ग्रामीणों की आपसी प्रगाढ़ता का कारण बनते हैं. बराह छत्तर मेला भी कुछ ऐसा ही है. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के बराह क्षेत्र में हर साल लगने वाले इस मेले में बिहार के कोसी क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना व कोसी स्नान करते हैं. इसी स्थान पर कोसी नदी हिमालय से नीचे जमीन पर उतरती है और वहां से ये नदी भारतीय प्रभाग के बीरपुर पहुंचकर कोसी बराज में कैद हो जाती है. यहां कार्तिक की पूर्णिमा के रोज

से भव्य मेला लगता है.

कहा जाता है कि दैत्य हिरणकश्यप से रक्षा के लिए देवतागण ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी. देवताओं की करुणामयी पुकार सुनकर भगवान विष्णु बराह का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल से लेकर प्रकट हुए और देवतागणों को बचाया. यहां नदी के किनारे ही मंदिर भी बना है, जहां भगवान विष्णु बराह रूप में विराजमान हैं. हिंदू धर्मावलंबियों के लिए हरिहर क्षेत्र, कुरु क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र व बराह क्षेत्र बहुत पवित्र माना जाता है. भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के कारण यह स्थान धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहां कोसी स्नान की परम्परा रही है. यहां न केवल नेपाल के श्रद्धालुओं का आगमन होता हैं, बल्कि नेपाल से सटे भारत के सीमवर्ती क्षेत्रों से भी भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं.

इस बार भी 26 अक्टूबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बराह क्षेत्र में मेले का भव्य आयोजन होना है. जहां श्रद्धालुगण कोसी स्नान कर पितरों के मोक्ष की कामना करेंगे. बिहार की तरफ से बराह क्षेत्र मेला जाने के लिए नेपाल से सटे भारतीय सीमा क्षेत्र भीमनगर से होकर भंटाबाड़ी स्थित महेंद्र राजमार्ग से इटहरी पहुंचना होता है. वहां से करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ने पर झुमका पहुंचते हैं. झुमका चौक से नहर के किनारे बनी सड़क छह किलोमीटर बाद चतरा पहुंचाती है. चतरा से ही कोसी नदी के साथ-साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है. यहां ये शुरू होता है हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य. यहां पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को आभास होता है कि वे अब पूरी तरह से प्रकृति की गोद में हैं. चतरा से छह फीट संकरे पथरीले रास्ते पर चार किलोमीटर पैदल चलने के बाद आता है बराह क्षेत्र. इस मेले की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ दर्शनार्थी बल्कि सामान और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी बड़ी संख्या में यहां तक पहुंचते हैं और बराह मेले की रौनक बढ़ाते हैं.■

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

बच्चों का मानसिक विकास महत्वपूर्ण
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
Prodigy 104 Anandpuri west Boring Canal Road Patna-01
डॉ. साची गुन्जन जो कि कुपोषित और मानिकस रूप से कमजोर बच्चों के लिए सेन्टर की शुरूआत कर रही हैं और उनके साथ डॉ. रमित गुन्जन ऑर्थो के कुशल चिकित्सक ने बताया कि वर्तमान समय में टेलीविजन और दौड़ती भागती जिन्दगी के बीच बच्चों में क्या बड़ों में भी मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं लेकिन यदि आप गौर करें तो आपके बच्चे की संवेदना को पढ़ कर उनका सही इलाज करना भी जरूरी है। और इसके लिए काउन्सेलिंग भी जरूरी है। कई बच्चों में लिखावट अर्थात राइटिंग की प्रॉब्लम या फिर किसी एक ही एक्टीवीटि को दुहराते रहने की समस्या हो पड़ने में समस्या आ रही है तो उसके लिए इन्होंने यह संस्था शुरू की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम इसकी ओपनिंग दिनांक 30 सितम्बर 2017 को 11 बजे दिन में रखी है। आगे उन्होंने बताया कि जो बच्चे सोसायटि में कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो अपनी अलग दुनिया में खोए रहते हैं और एक खास प्रक्रिया करते रहते हैं और आप उसे बुलते हैं तो आपकी बात नहीं सुनते लाईट से ये बच्चों काफी सेन्सेटिव रहते हैं ऐसे बच्चे आंख से आंख नहीं मिला कर बात करते हैं जैसे कोई बच्चा को आप कोई काम करने के लिए करते हैं लेकिन वह उस काम को नहीं समझा पाते हैं या आईडीयेशन नहीं कर पाते इस तरह के बच्चों में नींद की समस्या होती है पेट की समस्या भी होती है और यह शुरू होती है वह जब मां के पेट में रहते हैं इस तरह के बच्चों में देर से चलना हंसना बोलना आदि शामिल है। यह अनुवांशिक भी हो सकता है। यह समस्या सामजिक बदलाव के कारण होता है जैसे दोस्त नहीं मिलते हैं खेलने के लिए या फिर अधिक उम्र में शादी के बाद बच्चा होना या मां बाप नशा करते हों, समय से पहले पैदा हुआ हो यह रोग लड़कियों से ज्यादा लड़कों में होते हैं। इसे हम विहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, प्ले थेरापी, व अन्य तरीकों से ठीक करते हैं हम बच्चों को समाज में जीना सीखाते हैं। बच्चों की आदतों का अध्ययन कर इलाज अवश्य करायें।
Dr. Shachi Gunjan
Prop-Sensor Intigration& Rehab Foundationfor kids
Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

रद्द आयोजनों पर सफ़ाई

अनंत विजय

बिहार में विश्व कविता समारोह का प्रस्तावित आयोजन और उसमें अशोक वाजपेयी की केंद्रीय भूमिका लंबे समय तक साहित्य जगत में चर्चा के केंद्र में रहा. अशोक वाजपेयी ने इस मसले पर पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने बिहार सरकार को विश्व कविता समारोह के बारे में प्रस्ताव दिया था. अभी हाल ही में फेसबुक पर अशोक वाजपेयी ने 'कुछ तथ्य' के अंतर्गत लिखा – 'बिहार में 'सत्याग्रह' नाम से विश्व कविता समारोह का प्रस्ताव मैंने पिछले वर्ष जून 2016 में दिया था. उस पर विचार धीमी गति से हुआ. जब वित्तीय अनुमोदन हो गया तो आगे की कार्रवाई बहुत मन्द गति से हुई. त्रस्त होकर मैंने 14 जून 2017 को ही अपने को उससे अलग कर लिया. इस सारे दौरान श्री नीतीश कुमार का स्पष्ट रुख साम्प्रदायिकता, असहिष्णुता, हिंसा आदि के विरूद्ध मुखर और सक्रिय था.' अच्छी बात है कि अशोक जी ने लिखित रूप से ये स्वीकार किया. अबतक को वो इससे पल्ला ही झाड़ते रहे थे. इस स्तंभ में इस कविता समारोह को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है.

पहले अशोक वाजपेयी ये कहते रहे थे कि उन्होंने एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्व कविता सम्मेलन के आयोजन का सुझाव दिया था. तब भी इस बात पर हैरत जताई गई थी कि किसी आयोजन में मंच से दिए गए सुझाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना त्वरित फैसला कैसे लिया. बाद में पता चला था कि इस आयोजन को लेकर पटना में बैठक हुई थी, जिसमें अशोक वाजपेयी ने औपचारिक प्रस्ताव दिया था. वाजपेयी जी उस बैठक में शामिल होने पटना भी गए थे. उस बैठक में उनके अलावा आलोक धन्वा, अरुण कमल और आरजेडी के नेता दीवाना भी शामिल हुए थे. पटना की उस बैठक के बाद विश्व कविता समारोह के आयोजन में अशोक वाजपेयी की भूमिका को पुरस्कार वापसी के पुरस्कार के तौर पर देखा गया था. अशोक वाजपेयी ने भी लेख लिखकर इसका खंडन किया था और कहा था कि इस समारोह का पुरस्कार वापसी से कोई लेना देना नहीं है. जाहिर सी बात है कि इसको मानना बेहद कठिन था कि ये असहिष्णुता की मुहिम का इनाम था.

अफसरशाही की औपचारिकताओं में उलझकर ये कार्यक्रम टलता रहा. इस बात को लेकर भी काफी मंथन हुआ कि विश्व कविता सम्मेलन बिहार में करवाया जाए या फिर इसका आयोजन दिल्ली में हो. विश्व कविता सम्मेलन में कवियों की भागीदारी को लेकर भी फैसला नहीं हो पा रहा था. जब इस आयोजन का जिम्मा बिहार संगीत नाटक अकादमी को सौंपा गया था, उस वक्त बिहार में नीतीश-लालू की पार्टी की साझा सरकार थी. संस्कृति विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था और शिवचंद्र राम उस महकमे के मंत्री थे. उनका और आयोजन समिति में शामिल आरजेडी के नेता रामश्रेष्ठ दीवाना का मानना था कि बिहार के कवियों का तो कोटा हो ही, कुछ दलित कवियों को भी इसमें शामिल किया जाए. कुल मिलाकर इस आयोजन को लेकर उस वक्त नीतीश कुमार का सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी उत्साहित नहीं था. आरजेडी इसको नीतीश के व्यक्तिगत समारोह की तरह देखता था और बगैर किसी उत्साह के इसको धीमी गति से चला रहा था.

अशोक जी ने लिखा भी है कि वित्तीय अनुमोदन होने के बाद मन्द गति से वो त्रस्त हो गए थे, इसलिए समारोह से अलग हो गए थे. उन्होंने ईमेल से बिहार सरकार को अपनी मंशा अवश्य बता दी थी, लेकिन सरकार की तरफ से अशोक जी को जिम्मेदारी मुक्त करने का कोई फैसला हो नहीं पाया था. बाद में सियासत ने करवट बदली और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए. संस्कृति मंत्री बीजेपी के कोटे से बनाए गए. मंत्री जी ने कार्यभार संभालते ही विश्व कविता समारोह को रद्द कर दिया. इस तरह से हिंदी का हाल के दिनों में सबसे चर्चित आयोजन, जो हो ना सका, का पटाक्षेप हो गया.

अपनी उसी सफाई में अशोक वाजपेयी ने आगे लिखा- 'जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को मैंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया. उसने मुझसे कविता पर केंद्रित एक बड़ा आयोजन करवाने का आग्रह किया और मैंने मुक्तिबोध शती के दौरान उनकी पुण्यतिथि को शामिल कर 'समवाय' की रूपरेखा बनाई. कवियों और आलोचकों के नाम, विचार के लिए विषय आदि सुझाए जो सभी केन्द्रों ने मान लिए. उससे कुछ लेखकों के अपने को अलग करने के बावजूद पूरी तैयारी सुचारु रूप से चल रही थी. उसे स्थगित करने का निर्णय परिस्थितिवश केन्द्र ने, बिना मुझ से पूछे, लिया.' जवाहर कला केंद्र में अशोक जी की अगुवाई या रहनुमाई में आयोजित कविता केंद्रित कार्यक्रम रद्द हुआ इसको लेकर अशोक वाजपेयी के समर्थक प्रगतिशील लेखक संघ पर आक्रामक हो रहे हैं. 'जनवादी' मंगलेश डबराल हाल ही में 'कलावादी' अशोक वाजपेयी के समर्थक बने हैं. अशोक वाजपेयी की सफाई पर वो लिखते हैं- 'मेरा अनुभव यह है कि झूठ और दुष्प्रचार पर आमादा लोगों से कोई तर्क नहीं किया जा सकता. उन्हें समझाना नामुमकिन है और उनका कोई वैचारिक पक्ष भी नहीं है. यह देखकर दुःख जरूर होता है कि प्रगतिशील लेखक संघ और भी अधिक निर्वासन में जाना चाहता है और साहित्य में एक संयुक्त पहल नहीं चाहता.' पता नहीं कविवर किस संयुक्त पहल की बात कर रहे हैं. क्या कोई साहित्यिक पहल हो रही थी या फिर साहित्य की आड़ में राजनीति का खेल जवाहर कला केंद्र में खेला जाना था. आमंत्रित कवियों लेखकों आदि की सूची से साफ है कि वहां मुक्तिबोध के नाम पर क्या होता. जिस भी वजह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन वसुंधरा सरकार के लिए आसन्न अप्रिय स्थिति टल गई.

अफसरशाही की औपचारिकताओं में उलझकर ये कार्यक्रम टलता रहा. इस बात को लेकर भी काफी मंथन हुआ कि विश्व कविता सम्मेलन बिहार में करवाया जाए या फिर इसका आयोजन दिल्ली में हो. विश्व कविता सम्मेलन में कवियों की भागीदारी को लेकर भी फैसला नहीं हो पा रहा था. जब इस आयोजन का जिम्मा बिहार संगीत नाटक अकादमी को सौंपा गया था, उस वक्त बिहार में नीतीश-लालू की पार्टी की साझा सरकार थी. संस्कृति विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था और शिवचंद्र राम उस महकमे के मंत्री थे. उनका और आयोजन समिति में शामिल आरजेडी के नेता रामश्रेष्ठ दीवाना का मानना था कि बिहार के कवियों का तो कोटा हो ही, कुछ दलित कवियों को भी इसमें शामिल किया जाए. कुल मिलाकर इस आयोजन को लेकर उस वक्त नीतीश कुमार का सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी उत्साहित नहीं था. आरजेडी इसको नीतीश के व्यक्तिगत समारोह की तरह देखता था और बगैर किसी उत्साह के इसको धीमी गति से चला रहा था.

तीसरी सफाई अशोक जी ने रायपुर में होनेवाले कार्यक्रम को लेकर दी है- 'रायपुर में मुक्तिबोध शती के अवसर पर दो दिनों का जो समारोह 'अंधेरे में अन्तः करण' नाम से 12-13 नवम्बर 2017 को होने जा रहा है. वह पूरी तौर से रज़ा फ़ाउण्डेशन का, मुक्तिबोध परिवार के साथ मिलकर किया जा रहा आयोजन है. उसमें छत्तीसगढ़ सरकार से कोई मदद न मांगी गई है, न ली जा रही है, न उसकी कोई दरकार है. अज्ञेय-शमशेर-मुक्तिबोध और कविता को तरह-तरह से सार्वजनिक मंच, विमर्श और संवाद में प्रक्षेपित करने का प्रयत्न मैं पिछले 50 वर्षों से, बिना कोई राजनैतिक, अवसरवादी, वित्तीय समझौता किए, सारे अपवाद और लांछनों के बावजूद, करता रहा हूं-आजीवन करता रहूंगा.' इस बात से किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता है कि अशोक जी साहित्य के लिए समर्पित रहे हैं. विभूति नारायण राय लाख उनको साहित्य का इवेंट मैनेजर कहें, लेकिन साहित्य को लेकर अशोक जी की प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है. पहचान सीरीज से लेकर हाल में दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन तक.

हां, उनकी इस बात पर दो तरह के मत हो सकते हैं कि उन्होंने राजनैतिक समझौते नहीं किए, अवसरवादी समझौते नहीं किए. अशोक जी को लंबे समय से जानने वाले लोग कहते हैं कि उनको ना तो कभी सत्ता से परहेज रहा और ना ही कभी उन्होंने सत्ताधारियों से निकटता से कोई परहेज किया. चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव के साथ मंच साझा करना हो या फिर नीतीश कुमार के साथ. पुरस्कार वापसी अभियान के बाद तो नीतीश कुमार से उनकी निकटता काफी बढ़ गई थी. कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अशोक वाजपेयी जैसे हिंदी के वरिष्ठ और बेहद आदरणीय लेखक उस कमेटी में रहने को राजी क्यों और कैसे हो गए, जिसके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के मुखिया लालू यादव की पार्टी के हैं. विश्व कविता सम्मेलन के लिए बनाई गई उस कमेटी की सदस्यता स्वीकार करने को भी साहित्य जगत में अवसरवादिता माना गया था. रही बात समझौते की, तो उसको लेकर भी अशोक वाजपेयी अछूते नहीं हैं. साहित्य जगत में यह बात आम है कि उन्होंने संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहते अपने मातहत विभाग साहित्य अकादमी का पुरस्कार लिया. आरोप लगाने वाले तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए तमाम तरह की घेरेबंदी भी की. अब आरोप लगाने वालों का तो मुंह बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि अशोक जी ने जितने आयोजन हिंदी में किए उतना करनेवाला दूसरा कोई नहीं है. अफसर साहित्यकार बहुत हुए, साधन संपन्न भी कई थे, लेकिन अशोक जी जैसा साहित्यिक उत्सवधर्मी हिंदी में अबतक दूसरा नहीं है. और जब आप इतने बड़े काम करेंगे, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत समझौते करने पड़ते हैं. बिहार में विश्व कविता सम्मेलन के बारे में आंशिक ही सही, लेकिन उनकी सफाई ने उनके समर्थकों को वाह-वाह करने का मौका दे दिया है. फेसबुक पर उनके 'भक्त' जयकारा कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम नहीं जन्नत की हकीकत. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

वज़ीफ़ा वितरण में हुई अनियमितता के बारे में जानें

चौथी दुनिया ब्यूरो

विद्यालयों में वजीफा वितरण में होने वाली अनियमितता और धांधली आम है. जिन जरूरतमंद बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए उनमें से अधिकतर इससे वंचित रह जाते हैं और उन्हें मिलने वाली राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि स्कूलों में प्रधानाध्यापक ने किन्हीं नियमों व गलतियों का हवाला देते हुए किसी छात्र को वजीफा देने से मना कर दिया, जबकि वो छात्र पूरी तरह से उस वजीफे के लिए उपयुक्त होता है. छात्र या अभिभावक जानकारी और जागरूकता के अभाव में अपने हक की आवाज नहीं उठा पाते. ऐसे लोग सूचना के अधिकार का सहारा ले सकते हैं. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के बारे में बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को मिलने वाले वजीफे की जानकारी और उसकी पूरी प्रक्रिया का विवरण प्राप्त कर सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया..... विद्यालय में वजीफा के वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें :

1. उपरोक्त विद्यालय के कक्षा..... में मेरा पुत्र/पुत्री..... पढ़ता/पढ़ती है. आपके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या वह इस वर्ष वजीफा पाने का हकदार है? यदि हां तो उसे कितनी राशि मिलनी चाहिए?

2. क्या आपके विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उसे इस वर्ष का वजीफा दिया जा चुका है? यदि हां, तो सम्बन्धित दस्तावेजों/रजिस्टरों के उस भाग की प्रमाणित प्रति दें, जहां उसे वजीफा दिए जाने का विवरण दर्ज है.

3. यदि उसे वजीफा नहीं दिया गया है, तो इसका क्या

कारण है? सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दें.

4. उपरोक्त विद्यालय में कुल कितने छात्र/छात्राओं को वजीफा प्रदान किया जाता है? प्रत्येक छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं कक्षा का विवरण दें.

5. वर्ष..... में कुल कितने छात्र/छात्राओं को वजीफा दिया गया? प्राप्ति रजिस्टर, जिस पर छात्रा-छात्राओं का या उनके अभिभावकों का हस्ताक्षर हो, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

6. छात्र/छात्राओं के वजीफे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? वजीफा प्रदान करने के लिए क्या नियम एवं कानून है? इस सम्बन्ध में समस्त शासनादेशों/निर्देशों एवं कानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

7. सरकार ने विभिन्न कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को वजीफा देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की है?

8. अगर किसी छात्र के वजीफे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, तो इसका क्या कारण है? ऐसे सभी छात्रों कि सूची दें जिन्हे अब तक वजीफा नहीं दिया गया है, इस सूची में निम्नलिखित विवरण अवश्य शामिल हो :

क. छात्रा का नाम
ख. पिता का नाम
ग. वजीफा नहीं दिए जाने का कारण

10. वजीफे का भुगतान समय से न किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नाम एवं पद बताएं? अपना काम विभाग के नियम कानूनों के अनुसार न करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

जयंती विशेष

लोक के नायक, लोकतंत्र के प्रहरी जयप्रकाश नारायण

जन्मदिन- 11 अक्टूबर 1902
पुण्यतिथि- 8 अक्टूबर 1979

> भारत की आजादी के बाद हुए 1952 के चुनाव में कांग्रेस के सामने सभी दलों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नेहरू ने जयप्रकाश नारायण को मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर दिया. लेकिन जयप्रकाश नारायण ने नेहरू जी के सामने शर्त रखा कि वे इनके चौदहसूत्री कार्यक्रम पर विचार करें, तब वे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में जयप्रकाश नारायण की भूमिका के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आजादी के आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत में देश और समाज को दिशा देने में उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा है. बात चाहे, आजाद भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं का हल निकालकर टकराव दूर करने की स्थिति बनाने की हो, या कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सामने संधि प्रस्ताव रखने की, जयप्रकाश नारायण ने हमेशा एक समझदारी भरी पहल की. इसी तरह नगालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले विद्रोही नगाओं के हृदय परिवर्तन में जयप्रकाश नारायण का अहम योगदान रहा. चीन द्वारा अधिनायकवाद लादे जाने के विरोध में तिब्बतियों के मामले में भी जयप्रकाश नारायण ने समझदारी भरी सक्रिय भूमिका निभाई और आगे बढ़कर देश के लोगों को उस सन्दर्भ में सचेत किया. आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर जनचेतना जगाने और रचनात्मक सगंठन तैयार करने की जयप्रकाश नारायण की अद्भुत क्षमता को देखते हुए उन्हें 1965 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया.

जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को गंगा-सरयू के संगम स्थल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित सिताबदियारा में हुआ था. जयप्रकाश नारायण के पिता हरसूदयाल राज्य सरकार के नहर विभाग में काम करते थे. गांव में कोई हाई स्कूल न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद वे पटना आ गए. वे एक मेधावी छात्र थे. उन्होंने अच्छे नम्बरों के साथ हाईस्कूल पास किया, जिसके आधार पर सरकारी छात्रवृत्ति लेकर उन्हें पटना कॉलेज में प्रवेश मिला. जयप्रकाश नारायण जिस सरस्वती भवन छात्रावास में रहते थे, वो राजनैतिक गतिविधियों का अड्डा था. उस समय जब पूरे देश में राष्ट्रीय भावनाओं की लहर तेज हो रही थी, सरस्वती भवन में गांधी, बालगंगाधर तिलक और अरविंद घोष आदि के भाषणों पर चर्चा हुआ करती थी.

जयप्रकाश नारायण 1919 में गांधीजी के असहयोग आंदोलन से जुड़े. उनपर मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस भाषण का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरोध की बात कही थी. उनके प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने उस समय कॉलेज छोड़ दिया, जब उनकी परीक्षा के बस बीस दिन बाकी रह गए थे. पटना कॉलेज छोड़कर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया. लेकिन चौराचौरी आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण विद्यापीठ का पठन-पाठन भी बाधित हो गया. इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने पढ़ाई के लिए अमरीका जाने का निश्चय किया. इसी दौरान अक्टूबर 1920 में उनका विवाह प्रभावती से हो चुका था. प्रभावती एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी वकील ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थीं और स्वयं भी गांधीवादी विचारों से बेहद प्रभावित थीं. जयप्रकाश नारायण के अमेरिका प्रवास के दौरान प्रभावती ने महात्मा गांधी के आश्रम में रहने का निर्णय लिया.

अमरीका में जयप्रकाश नारायण का प्रवास बहुत ही कठिनाई भरा अनुभव रहा. आर्थिक परेशानियों के

कारण उन्हें बार-बार यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ी. इस दौरान खर्चे के लिए उन्होंने अंगूरों को डिब्बाबंद करने की फैक्ट्री में पैकिंग का भी काम किया. अमेरिका में जयप्रकाश नारायण ने समाजशास्त्र पढ़ा तथा इस विषय पर उनका पर्चा 'सोशल वेरियेशन' साल का सर्वश्रेष्ठ पर्चा घोषित किया गया, जो समाज के बदलाव का अध्ययन प्रस्तुत करता था. विस्कोसिन में जयप्रकाश नारायण को कार्ल मार्क्स की किताब 'दास कैपिटल' पढ़ने का मौका मिला, जिससे वे मार्क्सवाद से बेहद प्रभावित हुए. जयप्रकाश नारायण अपनी डाक्टरेट पूरी नहीं कर सके और नवम्बर 1929 में उन्हें अपनी मां की बीमारी के कारण वापस भारत आना पड़ा.

भारत आने पर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया और जयप्रकाश नारायण 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए. 1930 में जब बहुत से कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे, तब भी जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कामकाज जारी रखा. लेकिन बनारस में एक मीटिंग के दौरान वे गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1933 तक जेल में रहना पड़ा. एक बार जेल से भागकर वे नेपाल चले गए, जहां उन्होंने 'आजाद दस्ता' के नाम से एक गोरिल्ला फौज का गठन किया. लेकिन वे फिर गिरफ्तार हो गए. उन्हें रावलपिंडी के रास्ते लाहौर लाया गया और गम्भीर यातनाएं दी गईं. लगातार सोलह महीने लाहौर के किले में बंद रखने के बाद आखिरकार 12 अप्रैल 1946 को उन्हें रिहा किया गया.

भारत की आजादी के बाद हुए 1952 के चुनाव में कांग्रेस के सामने सभी दलों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नेहरू ने जयप्रकाश नारायण को मंत्रिमंडल

में शामिल होने का अवसर दिया. लेकिन जयप्रकाश नारायण ने नेहरू जी के सामने शर्त रखा कि वे इनके चौदहसूत्री कार्यक्रम पर विचार करें, तब वे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे. उस चौदहसूत्री कार्यक्रम में संविधान में सुधार, प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था में सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमिहीनों को जमीन देने का प्रस्ताव आदि थे. इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण स्वदेशी नीति को आगे लाना चाहते थे और उनकी योजना सहकारी इकाइयों के गठन की थी. जवाहरलाल नेहरू इन प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में कोई ठोस उत्तर देने के पक्ष में नहीं दिखे, तो जयप्रकाश नारायण ने मंत्रिमंडल में जाने से इंकार कर दिया. जयप्रकाश नारायण भले ही सरकार, मंत्रिमंडल तथा संसद का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उनकी राजनैतिक सक्रियता बराबर बनी रही. उन्होंने ट्रेड यूनियन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन, पेंशन, चिकित्सा-सुविधा तथा घर बनाने के लिए सहायता जैसे जरूरी मुद्दे लागू कराने में सफल हुए.

दिसंबर 1973 में जेपी ने यूथ फ़ॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन बनाया और देशभर के युवाओं से अपील की कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएं. गुजरात के छात्रों ने जब 1974 में चिमनभाई पटेल की भ्रष्ट सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया, तो जेपी वहां गए और नवनिर्माण आंदोलन का समर्थन किया. जेपी ने तब कहा था- मुझे क्षितिज पर वर्ष 1942 दिखाई दे रहा है. मार्च में पटना में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की. शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन का भरोसा मिलने की शर्त पर जेपी ने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया. यही बिहार आंदोलन बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बदल गया. जून 1975 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई. उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया. आंदोलन में शामिल विपक्ष ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा. जेपी ने विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया. देश में सरकार विरोधी माहौल बना और इंदिरा गांधी का सत्ता में रहना मुश्किल होने लगा. इन घटनाओं से असुरक्षित महसूस कर रही इंदिरा ने देश में रातोंरात इमरजेंसी लगा दी. देशभर में सेंसरशिप लागू कर दी गई और जेपी समेत सैकड़ों बड़े नेताओं को मीसा और राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत गिरफ़्तार कर ज़ेलों में डाल दिया गया. 19 महीने के काले क़ानून के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने आम चुनाव की घोषणा कर दी. जेपी का गुर्दा खराब था, लेकिन डायलसिस पर होने के बावजूद उन्होंने चुनाव की चुनौती स्वीकार की. चुनाव में उत्तर भारत से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया. इंदिरा और संजय गांधी चुनाव हार गए. आपातकाल का दंश भोगने वालों के लिए ये एक तरह से दूसरी आजादी थी. केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, लेकिन इस बदलाव का अगुआ, भारतीयों का लोकनायक 8 अक्टूबर 1979 को इस संसार से विदा हो गया. जेपी के योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरान्त 1998 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

सर्दियों में कैसे करें नवजात शिशु की देखभाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

गर्मी के बाद जब सर्दी शुरू होती है, तो लोग राहत महसूस करते हैं. लेकिन सर्दी भी अपने साथ कई तकलीफें लाती है. खासकर शिशुओं के लिए इस मौसम में ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है. खुश्क हवाएं, खांसी और जुकाम जैसी तकलीफें बच्चों के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं सर्दियों में बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें.

त्वचा की देखभाल: सर्दी के मौसम में हवा की नमी चली जाती है, जिस से शिशु की त्वचा शुष्क हो जाती है. ऐसे में बच्चे की मालिश जैतून के तेल से करने से बहुत लाभ होता है. मालिश से बच्चे के शरीर में खून का संचार सही रहता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. मालिश करते समय बच्चे को गरम और आरामदेह जगह पर लिटाना चाहिए. मालिश के कुछ देर बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए. बच्चे की त्वचा अत्यधिक नरम होती है, इसलिए साबुन ग्लिसरीन युक्त होना चाहिए और पानी कुनकुना होना चाहिए. जिस दिन ज्यादा सर्दी हो, उस दिन स्नान के बजाय साफ तौलिए को पानी में भिंगो कर व निचोड़ कर उससे बच्चे का बदन पोंछ सकते हैं.

होंठों की देखभाल: सर्दी में शिशु के होंठ

उस के थूक निकालने से गीले हो जाते हैं. उन की ऊपरी परत हट जाती है और उन पर सूखापन आ जाता है. उस के लिए पैट्रोलियम जैली या लिपबाम का उपयोग करना चाहिए.

आंखों की देखभाल: सर्दी में कभी-कभी शिशु की आंखों के कोने से सफेद या हलके पीले रंग का बहाव हो सकता है. इसे न तो हाथ से रगड़ें और न ही खींच कर निकालने की कोशिश करें. कुनकुने पानी में रुई डाल कर उसे हाथों से दबाएं फिर उससे आंखों को अंदर से बाहर की तरफ साफ करें. अगर शिशु की आंखें लाल हों या उनसे पानी निकल रहा हो, तो तुरंत आंखों के विशेषज्ञ को दिखलाना चाहिए.

> सर्दियों में शिशु के कपड़े गरम, नरम और आरामदेह होने चाहिए, जिनमें कोई जिप या टैग न लगा हो. बच्चे के हाथपैर गरम रखने के लिए उसे दस्ताने और मोजे पहनाने चाहिए और उसका सिर टोपी से ढकना चाहिए. बच्चे के कपड़े धोने का डिटर्जेंट माइल्ड होना चाहिए. बच्चे को कई बार ऊनी कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, जिससे उसके शरीर पर रैशेज हो जाते हैं. इसलिए कपड़े तापमान के हिसाब से ही पहनाने चाहिए.

शिशु के कपड़े: सर्दियों में शिशु के कपड़े गरम, नरम और आरामदेह होने चाहिए, जिनमें कोई जिप या टैग न लगा हो. बच्चे के हाथपैर गरम रखने के लिए उसे दस्ताने और मोजे पहनाने चाहिए और उसका सिर टोपी से ढकना चाहिए. बच्चे के कपड़े धोने का डिटर्जेंट माइल्ड होना चाहिए. बच्चे को कई बार ऊनी कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, जिससे उस के शरीर पर रैशेज हो जाते हैं. इसलिए कपड़े तापमान के हिसाब से ही पहनाने चाहिए. बच्चे को सीधा ऊनी कपड़ा पहनाने के बजाय पहले एक सूती कपड़ा पहनाना चाहिए. शिशु को सुलाते वक्त जब कंबल डालें, तो ध्यान रखें कि कंबल से मुंह न ढक जाए, इससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. शिशु के कपड़े अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और ज्यादा तंग नहीं होने चाहिए.

डायपर रैशेज से बचाव: सर्दी में डायपर और सूती नैपीज की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि शिशु सर्दी में जल्दी गीला करता है और सूखने में ज्यादा समय लगता है. कुछ खास बातें ऐसी हैं, जिनका ख्याल रखना आवश्यक है, जिससे डायपर रैशेज से बचाव हो पाए. इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि डायपर समय पर बदला जाए. डायपर ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए. उसे सही नाप का चुनना चाहिए. डायपर बदलने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए. डायपर बदलते वक्त ध्यान रखें कि शिशु की त्वचा सूखी और साफ हो. गुप्तांगों को रगड़ें नहीं, कोमलता से साफ करें. नैपी रैश क्रीम का इस्तेमाल करें.

घर का वातावरण: आपको घर और बच्चे के कमरे को गरम रखना चाहिए, जिसके लिए कमरे की खिड़की-दरवाजे बंद रखने चाहिए. दीवारों पर गीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फफूंदी लग सकती है और इससे बच्चे को एलर्जी या सर्दी व खांसी हो सकती है. यदि घर का कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, तो उसे घर से बाहर जा कर करना चाहिए. कमरे और बाथरूम के फर्श को अच्छे डिटर्जेंट से धोना चाहिए. सर्दी में मच्छर वैसे कम होते हैं, लेकिन अगर कीड़े या मच्छर हैं, तो पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहिए और बच्चे को उस दिन उस कमरे में नहीं ले जाना चाहिए. इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न हो और घर की नियमित रूप से सफाई हो. आजकल बाजार में स्टिकर के रूप में भी मौसक्यूटो उपलब्ध हैं, जो बच्चे की चारपाई या गाड़ी में भी लगाए जा सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बर्थ डे गर्ल रेखा के लिए हर दिन ख़ास होता है

ख़ूबसूरती के मामले में आज भी युवा अभिनेत्रियों पर भारी पड़ती हैं रेखा

बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने 10 अक्टूबर को अपनी ज़िंदगी के 63 साल पूरे कर लिए. 1954 में उनका जन्म चेन्नई में हुआ था. रेखा ने भले ही 6 दशक से ज्यादा की ज़िंदगी जी ली, लेकिन वे आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं. उनकी ख़ूबसूरती और अदाकारी ने सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बनाया है. वे आज भी उतनी ही ख़ूबसूरत नजर आती हैं, जितनी पहले दिखती थीं. उनके जन्मदिन पर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि तमाम प्रशंसक भी रेखा की लंबी उम्र और उनके सुखद-स्वस्थ्य जीवन की कामना करते हैं.

रेखा कहती हैं कि उनके जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं होता, क्योंकि वे हर दिन को विशेष मानती हैं. उन्होंने एक रेडियो चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था, मैं समझ नहीं पाती कि लोग एक दिन को इतना महत्व क्यों देते हैं. मेरा मानना है कि हर दिन उत्सव है और हर दिन मेरा नया जन्म होता है. मैं स्वाभाविक रूप से हर दिन अलग तरह से जीने की कोशिश करती हूं. रेखा ने ये भी कहा कि वे अपने जन्मदिन पर अपनी मां पुष्पावली जिन्हें वे प्यार से *अम्मा* कहती हैं, को याद करती हैं.

रेखा ने अपनी दिलकश अदाकारी के बल पर 70–80 के दशक में करोड़ों लोगों को अपना मुरीद बनाया है. बॉलीवुड में आज की जनरेशन रेखा को अपना आदर्श मानती है. करीब 40 वर्षों के फिल्मी करियर में वे लगभग 200 फिल्मों में काम कर चुकी हैं. रेखा की जोड़ी सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ ही पसंद की जाती थी. जब-जब ये जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर आती थी, तो सिनेमाघरों में दर्शकों का हुजूम सा उमड़ पड़ता था. अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर रेखा ने सालों तक बॉलीवुड पर राज किया. आज भी रेखा के सामने बड़ी-बड़ी हिरोइनें फीकी लगती हैं. सावन भादो, मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, ख़ूबसूरत, सिलसिला, ख़ून भरी मांग, सुहाग, राम बलराम, खून पसीना, रामपुर का लक्ष्मण और उमराव जान जैसी फिल्में आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्मों में शुमार हैं. सक्सेस की कहानियों के साथ-साथ रेखा की ज़िंदगी कॉन्ट्रोवर्सीं से भी भरी हुई है. रेखा की बायोग्राफी *रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी* में जाने-माने फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान ने रेखा की ज़िंदगी के कई अनछुए पहलुओं से पर्दा हटाया है. आइए जानते हैं, बॉलीवुड की इस दिलकश अदाकारा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में...

1. ये किस्सा है मुंबई के महबूब स्टूडियो का, जहां फिल्म *अंजाना सफर* की शूटिंग हो रही थी. उस समय रेखा की उम्र महज 15 साल थी. फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाठे और एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने मिलकर एक साजिश रची. राजा के एक्शन कहते ही विश्वजीत ने रेखा को पकड़ा और उन्हें एकतरफा चुंबन देने लगे. रेखा को इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया गया था. कैमरा रोल करता रहा और पूरा क्रू चिल्ला रहा था. डायरेक्टर ने पांच मिनट बाद कट बोला. रेखा की आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू छलक पड़े थे.

2. रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, उनकी मां तमिल की हिरोइन थीं. कहा जाता है कि जब रेखा का जन्म हुआ, उस समय उनके माता-पिता की शादी नहीं हुई थी, रेखा के पिता ने चार शादियां की थीं, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की. यहां तक कि वे रेखा को अपना ख़ून भी नहीं मानते थे. रेखा को अपने पिता से इतनी नफ़रत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गईं. रेखा की मां खुद काम कर जीवनयापन करती थीं, लेकिन उनके ऊपर कर्ज का इतना बोझ था कि छोटी उम्र में ही रेखा को भी काम करना पड़ा.

3. रेखा ने 12 साल की उम्र में ही तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. कहा जाता है कि छोटी उम्र के कारण रेखा जब काम करके थक जाती थीं और काम पर जाने से मना करती थीं, तो उन्हें उनके भाई मारते थे. पैसे की तंगी के कारण रेखा को सी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी. बतौर हिरोइन रेखा की पहली तेलगु फिल्म 1968 में आई .

4. बॉलीवुड में रेखा को पहला ब्रेक मिला 1970 में, फिल्म थी, *सावन भादो*. ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई.

5. करीब 3 साल तक विनोद मेहरा के साथ रेखा का अफेयर चला. 1973 में ये ख़बर भी आई कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी कर ली. लेकिन बाद में पता चला कि विनोद मेहरा के माता-पिता ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया. ये भी कहा जाता है कि उसके बाद रेखा ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी.

6. 1976 में फिल्म *दो अनजाने* में पहली बार रेखा और अमिताभ ने एक साथ काम किया. कहा जाता है कि फिल्म *मुकद्दर का सिकंदर* के बाद से अमिताभ-रेखा के बीच नजदीकियां आईं. फिल्म *गंगा की सौगंध* के सेट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी थी.

7. 1982 में नीतू और ऋषि की शादी में रेखा पहली बार सिंदूर में दिखीं. उसके बाद रेखा की शादी को लेकर चर्चाएं होने लगीं. बाद में पता चला कि रेखा एक फिल्म की शूटिंग करके सीधे वहां पहुंची थीं, वे किरदार के कॉस्ट्यूम में ही थीं.

8. 1982 में फिल्म *कुली* की शूटिंग के दौरान अमिताभ को चोट लगी थी. कहा जाता है कि उस समय जया ने रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया था. आज भी रेखा और अमिताभ किसी पार्टी में एक-दूसरे से नजरें चुराने से बचते हैं.

9. एक महीने की मुलाकात के बाद ही रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली. लेकिन जल्द ही रिश्ता बिखरने लगा. मुकेश डिप्रेशन के शिकार थे और दिल्ली में काम छोड़कर मुम्बई में रेखा की शूटिंग देखा करते थे. दोनों के बीच रिश्ते बेहद ख़राब हो चले थे. अंतत: 2 अक्टूबर 1990 को शादी के सात महीने बाद मुकेश ने रेखा का दुपट्टा गले में बांधकर आत्महत्या कर ली. उस वक्त ना केवल अग्रवाल परिवार, बल्कि फिल्म जगत के दिग्गजों ने भी रेखा को ख़ूब कोसा था. कोसने वालों में सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे नाम भी शामिल थे.■

मेरा मानना है कि हर दिन उत्सव है और हर दिन मेरा नया जन्म होता है. मैं स्वाभाविक रूप से हर दिन अलग तरह से जीने की कोशिश करती हूं.

न्यूटन से चमकी राजकुमार राव की क़िस्मत

प्रवीण कुमार

राजकुमार राव एक ऐसे अभिनेता हैं, जो ज्यादातर कम बजट की फिल्मों में ही दिखाई देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें लोग जानते नहीं, या फिर उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होतीं. राजकुमार राव की एक अच्छी ख़ासी फैनफॉलोइंग है और दुनियाभर में उनके लाखों-करोड़ों प्रशंसक मौजूद हैं. राजकुमार राव की गिनती सशक्त अभिनेताओं में होती है. किरदार को को पर्दे पर जीने का उनका एक अंदाज है. उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है. इस साल राजकुमार राव की 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी हैं. जिनमें *बहन होगी तेरी* औसत रही, वहीं फिल्म *बरेली की बर्फी* बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. बहुत कम बजट में बनी ये दोनों फिल्में अच्छा ख़ासा मुनाफा कमा चुकी हैं, वो भी तब, जब इनके साथ एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. इन दोनों फिल्मों में दमदार अभिनय को लेकर राजकुमार राव की ने ख़ूब वाहवाही बटोरी.

ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हुई न्यूटन

इन दोनों के अलावा राजकुमार राव की इस साल की तीसरी फिल्म *न्यूटन* भी बीते दिनों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. यह फिल्म पहले ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में धूम मचा चुकी है. यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही चर्चा में रही. यह फिल्म न्यूटन नामक एक ऐसे शख्स की कहानी है, जिसके सिर पर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी है. न्यूटन को भरोसा है कि ईमानदारी के दम पर छत्तीसगढ़ के इन घने जंगलों तक लोकतंत्र की रोशनी पहुंचाई जा सकती है. शायद यही कारण भी है कि केंद्र सरकार को फिल्म की कहानी पसंद आई और उन्होंने इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी. यह पहली फिल्म होगी, जिसे केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. बॉलीवुड में भी इस फिल्म की ख़ूब चर्चा है. बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर राजकुमार राव की इस फिल्म की ख़ूब तारीफ की है. इस बीच इस फिल्म पर कॉपी राइट उल्लंघन को लेकर आरोप भी लगे हैं. कुछ लोगों ने *न्यूटन* को ईरानी फिल्म *सीक्रेट बैलेट* की कॉपी बताया है. लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने इन आरोपों को साफ तौर से ख़ारिज कर दिया है.

आपको बता दें कि भारत की ओर से इस साल राजकुमार राव स्टारर फिल्म *न्यूटन* को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है. फिल्म को लेकर राव के काम की तारीफ हर जगह हो रही है और अब ये फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी जाएगी. *न्यूटन* को 26 भारतीय फिल्मों में से चुना गया है.

कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमार राव के लिए फिल्म *न्यूटन* मील का पत्थर साबित हो सकती है. इससे पहले राजकुमार राव ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें सिटी लाइट, अलीगढ़, क्वीन, काई पो छे, हमारी अधूरी कहानी, लव सेक्स और धोखा, डॉली की डोली, तलाश, गैंग ऑफ वासेपुर-1,2 आदि फिल्में शामिल हैं. कुल मिलाकर, राव के लिए यह साल बेहतरीन साबित हो रहा है. इस साल रिलीज हुईं उनकी तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया है. फिल्म *न्यूटन* ने उनको बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के बीच स्थापित कर दिया है, जिसके वे असल में हकदार भी हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

अमिताभ का अर्थ है कभी न बुझने वाली लौ

संघर्ष और सफलता की कहानी आश्चर्यजनक है

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन सब के लिए ख़ास है. अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ. उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और उनकी मां का नाम तेजी बच्चन है. जन्मदिन के मौके पर बिग-बी को चौथी दुनिया की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. अमिताभ ने इलाहाबाद के जनाना प्रोबधिनी एंड ब्वायज हाईस्कूल से स्कूलिंग की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी किया. अमिताभ ने फिल्मों में प्रवेश से पहले कलकत्ता में शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी के लिए बतौर फ्रेट ब्रोकर का काम किया था.

अमिताभ बच्चन को उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई

अमिताभ का अर्थ है, *कभी न बुझने वाली लौ* और उन्होंने अपने नाम का अर्थ सार्थक कर दिखाया. अमिताभ ऐसा नाम है, जिन्हें आज की युवा पीढ़ी ही नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां अपना आदर्श मानतीं रहेंगी. उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख शख्सियत बनने के लिए संघर्ष के कई दौर से गुजरना पड़ा.

बिग-बी ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया है. उनकी कड़ी मेहनत और उत्साह ने उन्हें आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पहुंचने का सपना शायद उन्होंने भी कभी नहीं देखा था. अमिताभ के संघर्ष और सफलता की कहानी जितनी आश्चर्यजनक है, उतनी ही रोमांचक भी. अमिताभ इस 11 अक्टूबर को 75 साल के हो गए. लेकिन आज भी उनमें काम करने की वही लगन देखी जा सकती है. वे आज भी काम को लेकर उतने ही उत्साहित हैं, जितने पहले हुआ करते थे.

बहुत कम लोगों को शायद आज भी पता होगा कि अमिताभ का सरनेम *श्रीवास्तव* था. लेकिन अमिताभ के पिता ने *बच्चन* उपनाम अपना लिया. इसी उपनाम से उनकी सारी रचनाएं भी प्रकाशित होती थीं. अमिताभ ने इसी उपनाम के साथ फिल्मों में प्रवेश किया और यह उपनाम सभी सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल होने लगा.

उन्होंने अपने जीवनकाल में ख़ूब सुर्खियां बटोरीं. वे अभिनेत्री रेखा के साथ रिश्ते को लेकर भी चर्चा में रहे. बताया जाता है कि रेखा दिल ही दिल में अमिताभ को चाहती थीं, लेकिन अमिताभ कभी इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़े. सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ की जोड़ी रेखा के साथ ख़ूब जमती थी. लेकिन अमिताभ बच्चन की शादी अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुई. अमिताभ को लेकर जया और रेखा में छत्तीस का आंकड़ा बॉलीवुड में चर्चा का विषय रहा है और ये आज तक कायम भी है. अमिताभ-जया की बेटी श्वेता नंदा और बेटा अभिषेक बच्चन हैं.

अपने फिल्मी करियर में अमिताभ ने अनेको सम्मान जीते, जिसमें उन्हें 4 बार नेशनल फिल्म अवार्डस से नवाजा गया. ख़ास बात ये है कि इसमें से तीन बार उन्हें बेस्ट एक्टर की श्रेणी में अवार्ड मिला. फिल्म फेयर अवार्डस में बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए 20 बार नॉमिनेट होकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है. इसमें से 14 बार वे विजयी भी रहे हैं.

अभिताभ ने जंजीर, रोटी कपड़ा और मकान, ख़ुदा ग़वाह, कुली, कुंवारा बाप, फ़रार, शोले, चुपके चुपके, कसमें वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, मि. नटवरलाल, काला पत्थर, दोस्ताना, सिलसिला, शान, लावारिस, आज का अर्जुन, पा, ब्लैक, अग्निपथ, शक्ति और पिंक जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने *कौन बनेगा करोड़पति* जैसे रियलिटी शोज से भी दर्शकों को अपना मुरीद बनाया है. अमिताभ अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर ऐसे मुकाम पर पहुंचे, जहां वे सभी की आंखों का तारा बन गए. महानायक का संघर्षमय जीवन प्रेरणा देता है कि राह में लाख कांटे आएं, लेकिन आपके पग डगमगाने नहीं चाहिए.■

चौथी दुनिया ब्यूरो